रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 10, 1981/पौष 20, 1902

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 10, 1981/PAUSA 20, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1980

(आय-कर)

का० आ० 84—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "गुरुद्वारा श्री हेमकुण्ड साहिब, चमोली, उत्तर प्रदेश " को, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं० 3218 (फा० सं० 176/10/79-आ०क० I)]

बी० एम० सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 19th March, 1980

(INCOME TAX)

S.O 84.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) (b) of Section 80G of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies Gurudwara Shri Hemkunt Sahib Chamoli, Uttar Pradesh, to be a place of public worship of renown throughout the State of Uttar Pradesh for the purposes of the said Section.

[No 3218 (F No 176/10/79 IT AI)]

B M SINGH, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1980

का० आ० 85—राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंध और प्रकीर्ण (उपबंध) स्कीम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री अशोक नारायण के स्थान पर वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री डी० आर० मेहता को एतद्द्वारा इलाहाबाद बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/1/80- बी० ओ० I)]

च० रा० मीरचन्दानी उप सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi the 23rd December, 1980

S.O. 85.—In pursuance of sub clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri D R Mehta, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division),

New Delhi as a Director of the Allahabad Bank vice Shri Ashok Narayan.

[No. F. 9/1/80-BO.I]

C. W. MIRCHANDANI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1980

का० आ० 86.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध 9 नवम्बर, 1981 तक हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि० कानपुर, पर उसके द्वारा अचल संपत्ति अर्थात् मोहितगांसगंज, इलाहाबाद में मकान नं० 116/377 की धारिता के संबंध में लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15 (41)/80 बी० ओ०III)]

एन० डी० बत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 24th December, 1980

S.O. 86.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provision of Section 9 of the said Act shall not apply till the 9th November, 1981 to the Hindustan Commercial Bank Ltd., Kanpur in respect of the immovable property viz. a house No. 116/377 held by it at Mohitshansganj, Allahabad.

[No. 15(41)/80-B.O.III]

N. D. BATRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1980

का० आ० 87.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) और उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एन० एन० पै को 1 जनवरी, 1981 से आरम्भ होने वाली तथा 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/30/80-बी० ओ० I(1)],

New Delhi, the 26th December, 1980

S.O. 87.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) and of sub-section (2) of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby appoints Shri N. N. Pai as the Managing Director of the Industrial Development Bank of India for the period commencing on the 1st January, 1981 and ending with the 31st December, 1983.

[No. F. 9/30/80-BO.I(1)]

का० आ० 88.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एन० एन० पै को, जो कि 1 जनवरी, 1981 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किए गये है, उसी तारीख से औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[सं० 9/30/80-बी० ओ०-I(2)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 88.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby appoints Shri N. N. Pai who has been appointed as the Managing Director of the Industrial Development Bank of India with effect from the 1st January, 1981, to be the Chairman of the Board of Directors of the Industrial Development Bank of India with effect from the same date.

[No. F. 9/30/80-BO.I(2)]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1980

का० आ० 89.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होकर तथा 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) और (ii) के उपबन्ध इण्डियन ओवरसीज बैंक पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक वे उपबन्ध उक्त बैंक का प्रबंध इसके अध्यक्ष द्वारा किये जाने पर इस कारण प्रतिबंध लगाते हैं कि वह कृषि वित्त निगम, लिमिटेड के निदेशक हैं जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत एक कम्पनी है, तथा

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के उपबंध उपर्युक्त बैंक पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक ये उपबंध उक्त बैंक के कृषि वित्त निगम लिमिटेड का शेयर धारिता पर पाबन्दी लगाते है।

[संख्या, 10(51)/80-ए० सी०)]

दिनेश चन्द्र, निदेशक

New Delhi, the 26th December, 1980

S.O. 89.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulations Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that during the period commencing from the date of this notification and ending with 30th June, 1982—

(a) the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to the Indian Overseas Bank insofar as the said provisions prohibit the said bank from being managed by its Chairman by reason of his being a director of the Agricultural Finance Corporation Ltd., a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and

(b) the provisions of sub-section (3) of section 19 of the said Act shall not apply to the said bank insofar as the said provisions prohibit, the said bank from holding shares in the said Agricultural Finance Corporation Ltd

[No. 10(51)/80-AC]

DINESH CHANDRA, Director

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1981.

का० आ० 90.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 3 के साथ पठित निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा

निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, 1 जनवरी, 1981 से एक वर्ष की अवधि के लिए श्री पी० के० कौल, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) को निर्यात निरीक्षण परिषद् के अध्यक्ष के रूप में तथा निम्नलिखित को सदस्यों के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है :—

1. निदेशक, निरीक्षण तथा क्वालिटी नियंत्रण, निर्यात निरीक्षण परिषद्, नई दिल्ली—सदस्य सचिव।
2. महानिदेशक, भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली।
3. भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार।
4. महा निदेशक, वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी, कलकत्ता।
5. सचिव (तकनीकी विकास) उद्योग मंत्रालय।
6. मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात, वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)
7. अध्यक्ष लघु उद्योग संघ फैडरेशन।
8. अध्यक्ष, समुद्री खाद्य निर्यातक संघ, कोचीन।
9. अध्यक्ष, चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास।
10. अध्यक्ष, इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन।
11. विकास आयुक्त, लघु उद्योग।
12. कार्यकारी निदेशक, इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्।
13. माइसोडेट प्रा० लि० बंगलौर, (मद्रास, विजयवाडा, विशाखापत्तनम)
14. मैसर्स डा० रमन सी० अमीन के डा० रमन सी अमीन, बम्बई।
15. उद्योग निदेशक, पंजाब सरकार।

[फा० सं० 3 (94)/75-ई० आई० एण्ड ई० पी०]

MINISTRY OF COMMERCE

(Deptt. of Commerce)

New Delhi, the 1st January, 1981

S.O. 90.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with Rule 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby appoints Shri P. K. Kaul, Commerce Secretary, Ministry of Commerce (Department of Commerce) as Chairman and nominates the following as Members of the Export Inspection Council for a period of one year with effect from 1st January, 1981 :—

1. Director of Inspection and Quality Control, Export Inspection Council, New Delhi—Member Secretary.
2. Director General of Indian Standards Institution, New Delhi.
3. Agricultural Marketing Adviser of the Government of India.
4. Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta.
5. Secretary (Technical Development), Ministry of Industry, New Delhi.
6. Chief Controller of Imports & Exports, Ministry of Commerce (Department of Commerce) New Delhi.
7. President, Federation of Association of Small Industries.
8. President, Seafood Exporters Association, Cochin.
9. Chairman, Leather Export Promotion Council, Madras.
10. Chairman Indian Jute Mills Association.
11. Development Commissioner, Small Scale Industries.
12. Executive Director, Engineering Export Promotion Council.
13. Mysodet Pvt. Ltd. Bangalore, (Madras, Vijayawada, Visakhapatnam).
14. Dr. Raman C. Amin of M/s. Dr. Raman C. Amin Bombay.
15. Director of Industries, Govt. of Punjab.

[F. No. 3(94)/75-EI&EP]

आदेश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1981

का० आ० 91.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए अल्ट्रामेरीन नील का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण करने के लिए कतिपय प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3543 तारीख 20 अक्तूबर, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग—II खंड—3, उपखंड (ii) तारीख 20 अक्तूबर, 1979 में प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 25 अक्तूबर 1979 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

उन सभी व्यक्तियों से जिनके उक्त प्रभावित होने की संभावना थी 4 दिसम्बर, 1979 तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ।

अतः, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिनियम के अनुसरण में और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० 2196 तारीख 2 जुलाई, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है इसके द्वारा :—

(1) अधिसूचित करती है कि अल्ट्रामैरीन नील का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा ;

(2) (क) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानक और निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के मानकों को ;

(ख) संविदात्मक विनिर्देशों को इस शर्त के अधीन कि उत्पाद इस आदेश के उपाबंध में विनिर्दिष्ट न्यूनतम विशेषताओं को पूरा करता है,

(ग) विदेशी क्रेता और निर्यात कर्ता के बीच निर्यात संविदा के सहमत विनिर्देशों को निर्यात कर्ता द्वारा घोषित विनिर्देशों को ऐसी निर्यात संविदाओं के लिए जिनकी पुष्टि आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के पूर्व की जाती है और निर्यात उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर किया जाता है :

अल्ट्रामैरीन नील के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है।

टिप्पण :

(1) जब निर्यात संविदा में विस्तृत तकनीकी अपेक्षाओं का वर्णन नहीं होता या केवल नमूनों पर आधारित होती है तो निर्यात कर्ता को लिखित रूप में विनिर्देश प्रस्तुत करने चाहिए ।

(2) परीक्षण की पद्धतियां राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होंगी ।

(3) अल्ट्रामैरीन नील के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1981 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण

के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो उनके निर्यात से पूर्व ऐसे अल्ट्रामैरीन नील पर लागू किया जाएगा,

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान अल्ट्रामैरीन नील के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक उसके साथ निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण (अधिनियम, 1963) 1963 का 22 की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी अभिकरण के द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि अल्ट्रामैरीन नील क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करता है तथा अल्ट्रामैरीन नील निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1980 के अनुसार निर्यात योग्य है।

2. इस आदेश की कोई भी बात (क) भावी क्रेताओं को भूमि, समुद्र या वायु मार्ग, द्वारा अल्ट्रामैरीन नील (1 कि० ग्रा० से अधिक नहीं) के वास्तविक नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी।

(ख) अल्ट्रामैरीन नील के ऐसे परेषणों को लागू नहीं होगी जो इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तुरन्त पूर्व निर्यात कर्ता या विनिर्माता के परिसरों से पहले ही जा चुके हैं।

3. इस आदेश में 'अल्ट्रामैरीन नील' से निम्नलिखित प्रकारों में से किसी या प्रकार का अल्ट्रामैरीन नील अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(क) अल्ट्रामैरीन नील (तकनीकी श्रेणी)

(ख) अल्ट्रामैरीन नील (धुलाई श्रेणी)

4. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

उपाबंध

(क) तकनीकी श्रेणी के अल्ट्रामैरीन नील के लिए विनिर्देश

1. अल्ट्रामैरीन नील (तकनीकी श्रेणी) चूर्ण के रूप में या ऐसी दशा में होगा कि बेधार चाकू से पीसे बिना ही संदलन द्वारा उसका चूर्ण बन जाए।

2. सामग्री में कोई दृश्य अशुद्धि, कार्बनिक रंजक या किसी प्रकार का डाइल्यूटेंट नहीं होगा।

3. सामग्री एक समान विशेषता की होगी तथा प्रवर्ण रूप से सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकोन, गन्धक तथा आक्सीजन के सम्मिश्रण से बनी होगी।

4. अल्ट्रामैरीन नील (तकनीकी श्रेणी) का रंग, हल्का चमकापन, अभिरंजन क्षमता तथा निर्यात कर्ता तथा विदेशी क्रेता में सहमत तय हुए विनिर्देशों से निम्न स्तर का नहीं होगा।

5. पहचान परीक्षण—लगभग—0.1 ग्राम सामग्री को 1.1 (वी 1 वी) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एक परख नली में हल्का गर्म करें। सामग्री अल्ट्रामैरीन नील (तकनीकी वर्ग) तो मानी जाएगी यदि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के विमोचन के साथ-साथ रंग पूर्णतः नष्ट हो जाता है भिगोये हुए लेड ऐसीटेट कागज की पट्टी, को परख नली के ऊपर पकड़ रखने से यदि पट्टी इसके विशिष्ट भूरी रंग की हो जाती है तो इससे उसकी पहचान हो जाएगी। इस प्रक्रिया के पश्चात् भी कोई रंग शेष रह जाता है तो यह समझा जा सकता है कि कोई रंग आद्यवर्णक विद्यमान है।

6. सामग्री नीचे सारणी में दी गयी अपेक्षाओं के भी अनुरूप होगी—

सारणी

क्रम सं०	विशेषताएं	तकनीकी श्रेणी
(1)	अघुलनशील पदार्थ का अधिकतम प्रतिशत भार के अनुसार	1.0
(2)	छानने पर (63 माइक्रोन भा० मा० जाली) अवशेष का प्रतिशत (भार के अनुसार)	0.5
(3)	तेल अवशोषण	40 से 50 (तथापि वह इस विनिर्देश के अनुसार अनुमोदित नमूने के 5 प्रतिशत के भीतर होगा)
(4)	जल में घुलनशील पदार्थ का अधिकतम प्रतिशत (भार के अनुसार)	
(5)	क्षारता (यथा एन ए2 सी ओ 3) का अधिकतम प्रतिशत भार के अनुसार)	0.15
(6)	घुलनशील कार्बनिक रंजक पदार्थ	शून्य

ख. अल्ट्रामैरीन नील धुलाई श्रेणी के लिए विनिर्देश :-

1. अल्ट्रामैरीन नील (धुलाई श्रेणी), चूर्ण के रूप में या ऐसी दशा में होगा कि बेधार चाकू से पीसे बिना ही संदलन द्वारा उसका चूर्ण बन जाए।

2. सामग्री एक समान विशेषता की होगी, तथा उसमें या तो केवल अल्ट्रामैरीन (सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकोन, गन्धक और आक्सीजन का सम्मिश्रण) होगा या विदेशी क्रेता द्वारा यथा अपेक्षित क्वालिटी के अनुकूल बनाने के लिए वह फिलर युक्त होगा।

3. सामग्री की रंग आभा, अनुमोदित नमूने के निकटतम अनुरूप होगी।

4. सामग्री की पानी में घुलनशीलता, अनुमोदित नमूने के निकटतम अनुरूप होगी।

5. सामग्री के घोल में भिगोये गए कपड़े पर आई सफेदी निकटतम उसी प्रकार की होगी जो अनुमोदित नमूने में उसी प्रकार भिगोए गए कपड़े पर है।

[सं० 6(40)/72-नि० नि० तथा नि०उ०]

ORDER

New Delhi, the 10th January, 1981

S.O. 91.—Whereas for the deelopment of the export trade of India, certain proposals for subjecting Ultramarine Blue to Quality Control and Inspection prior to export, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India Part II-Section 3-Sub-section (ii), dated the 20th October, 1979, under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 3543, dated the 20th October, 1979;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 25th October, 1979;

And whereas the objections and suggestions were invited till the 4th December 1979 from all persons likely to be affected thereby;

And whereas the objection and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act. 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting

the Export Inspection Council, being of opinion that in pursuance of the said sub-rule and in supersession of the Order of the Government of India, in the Ministry of Commerce No. S.O. 2196 dated 2nd July, 1977, it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India hereby;—

(1) notifies that the ultramarine blue shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) Recognises—

(a) National and International standards and standards of other bodies recognised by Export Inspection Council;

(b) Contractual specifications subject to the product satisfying the minimum of the characteristics specified in the Annexure to this Order; and

(c) The specifications declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract between the foreign buyer and the exporter, for such export contracts as are confirmed prior to the date of publication of the Order in the Official Gazette and exported within a period of sixty days from that date; as the standard specifications for ultramarine blue.

NOTE :

(i) When the export contract does not indicate detailed technical requirements or based only on samples, the exporter should furnish a written down specification.

(ii) Methods of tests will be as per National Standards.

(3) specification the type of quality control and inspection in accordance with the Export of Ultramarine Blue (Quality Control and Inspection) Rules, 1980, as the type of quality control and inspection which shall be applied to such ultramarine prior to their export ;

(4) prohibits the export in the course of international trade of ultramarine blue, unless the same are accompanied by a certificate issued by an agency established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that ultramarine blue satisfies the condition relating to the quality control and inspection and is exportworthy in accordance with he Export of Ultramarine Blue (Quality Control and Inspection) Rules, 1981.

2. Nothing in this Order shall apply to the export of:—

(a) bonafide samples of ultramarine blue (not exceeding 1 kg.) by land, sea or air to the prospective buyers.

(b) consignments of ultramarine blue which might have already left the premises of the exporter or manufacturer immediately prior to the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. In this order 'Ultramarine blue' shall mean the ultramarine blue of any or all of the following types, namely :—

(a) Ultramarine blue (Technical Grade)

(b) Ultramarine blue (Laundry Grade)

4. This Order shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

ANNEXURE

(8) Specifications for Ultramarine Blue, Technical Grade

1. The Ultramarine Blue (Technical Grade), shall be in the form of any powder or in such a condition that it may be reduced to the powder form by crushing without grinding action under a plette knife.

2 The material shall be free from any visible impurities, organic dyestuffs or substrate of any kind.

3. The material shall be of uniform character and shall consist solely of compounds of sodium, aluminium, silicen, sulphur and oxygen.

4. The colour, light fastness, staining power and tone of the Ultramarine blue (Technical Grade) shall not be inferior to the specifications, as agreed to between the exporter and the foreign buyer.

5. Identification Test—Warm gently approximately 0.1 gm. of the material with 1.1 (v/v) hydrochloric acid in a test tube. The material shall be identified as ultramarine blue.

(Technical Grade) if the colour is destroyed completely with the evolution of hydrogen sulphide gas, detected by its characteristic brown colouration appearing on a strip of moistened lead acetate paper held above the test tube. If a colour remains after this treatment, it may be interpreted that a foreign pigment is present.

6. The material shall also comply with the requirements given in the Table below :

TABLE

Sl. No.	Characteristics	Technical Grade
(i)	Voltile matter, percent by weight, Max.	1.0
(ii)	Residue on sieve (63-micron I.S. Sieve), percent by weight, Max.	0.5
(iii)	Oil absorption	40 to 50 (It shall be however within 5 percent of the simple approved against specification)
(iv)	Matter soluble in water, per cent by weight, Max.	2.0
(v)	Alkalinity (as No. 2 CO_3) per cent by weight, Max.	0.15
(vi)	Soluble organic colouring matter	absent

(b) Specification for Ultramarine Blue Laundry Grade

1. The Ultramarine blue (Laundry grade) shall be in the form of dry powder or in such a condition that it may be reduced to the powder form by crushing without grinding action under a palette knife.

2. The material shall be of uniform character and shall consist of ultramarine (compound of sodium, aluminium, silicon, sulpher and oxygen) either alone or mixed with a tiler required to match the quality as required by the foreign buyer.

3. The shade of colour of the material shall closely match to that of the approved sample.

4. The dispersibility of the material in water shall closely match to that of the approved sample.

5. The whiteness imparted to washed cloth by rinsing in a suspension of the material shall be a close-match to that of the cloth treated in an identical manner with the approved sample.

[No. 6(40)/72-EI&EP]

का०आ० 92.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अल्ट्रामैरीन नील (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1981 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं —इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ।

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई और दिल्ली में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है,

(ग) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है,

(घ) "अल्ट्रामैरीन नील" से निम्नलिखित प्रकारों में से कोई एक या सभी अभिप्रेत है, अर्थात् —

(1) अल्ट्रामैरीन नील (तकनीकी श्रेणी)

(2) अल्ट्रामैरीन नील (धुलाई श्रेणी)

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

3. निरीक्षण का आधार —निर्यात के लिए अल्ट्रामैरीन नील का निरीक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि अल्ट्रामैरीन नील निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है या तो —

(क) यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्पाद का विनिर्माण उपाबंध I में विनिर्दिष्ट उत्पादन के दौरान आवश्यक क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए किया गया है, या

(ख) उपाबंध II में विनिर्दिष्ट ढंग से किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर किया गया है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया —(1) अल्ट्रामैरीन नील के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता संविदात्मक विनिर्देशों का ब्यौरा देते हुए अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा और ऐसी सूचना के साथ ही निर्यात संविदा या आदेश की एक प्रति भी देगा जिससे कि अभिकरण नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके ।

(2) इस बात के लिए निर्यात के लिए अल्ट्रामैरीन नील का, उपाबंध I में अधिकथित प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करके विनिर्माण किया गया है तथा इस प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा गठित परिषद्/विशेषज्ञों के पैनल के विनिर्माता यूनिट के बारे में यह निर्णय दिया है कि उसके पास प्रक्रियागत पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण अभ्यास की व्यवस्था है, निर्यातकर्ता उपनियम (1) में उल्लिखित सूचना के साथ एक घोषणा भी देगा कि निर्यात के लिए आशयित अल्ट्रामैरीन नील का विनिर्माण, उपाबंध I में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करके किया गया है तथा परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

(3) ऐसी प्रत्येक सूचना या घोषणा या दोनों की एक प्रति साथ ही साथ परिषद् के निम्नलिखित कार्यालयों में से किसी एक को जो निरीक्षण के स्थान के निकटतम है भेजी जाएगी अर्थात् :—

मुख्य कार्यालय : निर्यात निरीक्षण परिषद्
'वर्ल्ड ट्रैड सेन्टर'
14/1-बी, एजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल)
कलकत्ता- 1

क्षेत्रीय कार्यालय : निर्यात निरीक्षण परिषद्—
अमन चैम्बर्स,
113, महर्षि कार्वे रोड,
मुम्बई- 200004,
निर्यात निरीक्षण परिषद्,
मनोहर बिल्डिंग,
महात्मा गांधी रोड,
एरनाकुलम
कोचीन- 682001
निर्यात निरीक्षण परिषद्,
म्यूनिसिपल मार्केट बिल्डिंग,
3, सरस्वती मार्ग,
नई दिल्ली- 5 ।

(4) निर्यातकर्ता अभिकरण को परेषण पर लगाए जाने वाले पहचान चिन्ह भी देगा ।

(5) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक घोषणा यदि कोई है विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम 7 दिन पहले दी जाएगी ।

(6) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना और उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक घोषणा के प्राप्त होने पर, अभिकरण —

(क) अपना यह समाधान हो जाने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान विनिर्माता ने, उत्पाद को, इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप, विनिर्मित करने के लिए उपाबंध I में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का तथा परिषद् द्वारा इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का, यदि कोई है, पालन किया है, अभिकरण यह घोषणा करते हुए प्रमाण पत्र जारी करेगा कि अल्ट्रामैरीन नील का परेषण निर्यात योग्य है । विनिर्माता के निर्यातकर्ता न होने की दशा में परेषण का भौतिकी सत्यापन किया जाएगा तथा यथा-आवश्यक ऐसा सत्यापन तथा निरीक्षण अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उपरोक्त शर्तों की पूर्ति हो गई है । अभिकरण तथापि निर्यात के लिए आशयित परेषणों में से कुछ की मौके पर जांच करेगा ;

(ख) जहां निर्यातकर्ता ने उपनियम (2) के अधीन यह घोषणा नहीं की है कि उपाबंध I में अधिकथित रूप में पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया गया है, अपना यह समाधान कर लेने पर कि अल्ट्रामैरीन नील का परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, उपाबंध III में अधिकथित रूप में निरीक्षण/परीक्षण किए जाने के आधार पर या दोनों के आधार पर ऐसा निरीक्षण करने के सात दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए, प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि अल्ट्रामैरीन नील का परेषण निर्यात योग्य है,

परन्तु जहां अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है वहां वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर निर्यातकर्ता को यह घोषणा करते हुए प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर देगा कि अल्ट्रामैरीन नील का परेषण निर्यात योग्य नहीं है तथा ऐसे इंकार की सूचना, उसके कारणों सहित, निर्यातकर्ता को देगा ।

(7) विनिर्माता के निर्यातकर्ता न होने की दशा में उपनियम (6) (ख) के अधीन परेषण के निरीक्षण किए जाने की दशा में या दोनों दशाओं में अभिकरण, निरीक्षण की समाप्ति पर, परेषण में पैकेजों को इस ढंग से सील बंद करेगा कि वे सुनिश्चित किया जा सके कि सीलबंद पैकेजों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकेगा । परेषण के अस्वीकृत होने की दशा में, यदि निर्यातकर्ता चाहता है तो अभिकरण परेषण को सीलबंद नहीं करेगा परन्तु ऐसे मामलों में, निर्यातकर्ता ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा ।

5. निरीक्षण का स्थान —इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण (क) ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिसरों पर या (ख) उस परिसर पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता ने माल प्रस्तुत किया है परन्तु यह तब जबकि इस प्रयोजन के लिए वहां पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों ।

6. निरीक्षण फीस :—निर्यातकर्ता अभिकरण को ऐसे प्रत्येक परेषण के लिए पांच पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक एक सौ रुपए के लिए चालीस

पैसे की दर से निरीक्षण फीस देगा किन्तु परेषण के लिए यह फीस कम से कम पचास रुपए होगा।]

7. अपील —(1) नियम 4 के उपनियम (6) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा। इस पैनल में कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी सदस्य होंगे।

(3) विशेषज्ञों के पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अपील पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

8. निरसन अल्ट्रामैरीन नील निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण), नियम, 1977 का इसके द्वारा निरसन किया जाता है।

उपाबंध I

[नियम 3(क) के अधीन देखिए]

क्वालिटी नियंत्रण

विनिर्माता अल्ट्रामैरीन नील का क्वालिटी नियंत्रण उत्पादों के विनिर्माण परिरक्षण तथा पैकिंग के विभिन्न प्रक्रमो पर जो नीचे अधिकथित है तथा इससे संलग्न अनुसूची में दिए गए नियंत्रण स्तरों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा।

(i) क्रय और कच्ची सामग्री का नियंत्रण:—

(क) विनिर्माता प्रयुक्त की जाने वाली कच्ची सामग्री की विशेषताओं को समाविष्ट करते हुए क्रय विनिर्देश अधिकथित करेगा।

(ख) स्वीकृत परेषणो के साथ या तो क्रय विनिर्देशो की अपेक्षाओं की संपुष्टि करते हुए प्रदायकर्ता का परीक्षण और निरीक्षण प्रमाणपत्र होगा जिसमें क्रेता उपयुक्त परीक्षण या निरीक्षण प्रमाणपत्र की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए किसी विशिष्ट प्रदायकर्ता के दस परेषणों में से कम से कम एक की या तो फैक्ट्री की प्रयोगशाला में या बाहरी प्रयोगशाला में या परीक्षण सदन में आकस्मिक जांच करेगा।

(ग) निरीक्षण या परीक्षण के लिए नमूनों का लिया जाना अभिलिखित अन्वेषण पर आधारित होगा।

(घ) निरीक्षण या परीक्षण किए जाने के पश्चात् स्वीकृत और अस्वीकृत सामग्री का पृथक्करण करने के लिए अस्वीकृत सामग्री का निपटान करने के लिए व्यवस्थित पद्धतियाँ अपनाई जाएंगी।

(ङ) पूर्वोक्त नियंत्रणों के संबन्ध मे विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख नियमित तथा व्यवस्थित रूप से रखे जाएगें।

(ii) प्रक्रिया नियंत्रण:—

(क) विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों के लिए विस्तृत प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित करेगा।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकथित प्रक्रिया नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपस्कर और यंत्रीकरण सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी।

(ग) उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रण का सत्यापन संभव हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता पर्याप्त अभिलेख रखेगा।

(iii) उत्पाद नियंत्रण :—

(क) अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद की जांच के लिए या तो विनिर्माता के पास अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या किसी अन्य ऐसे स्थान तक उसकी पहुंच होगी जहां ऐसी परीक्षण सुविधाएं है।

(ख) किए जाने वाले परीक्षण और निरीक्षण के लिए नमूनों का लिया जाना किसी अभिलिखित अन्वेषण पर आधारित होगा।

(ग) नमूने लिए जाने और किए गए परीक्षण के बारे में पर्याप्त अभिलेख नियमित और व्यवस्थित रूप मे रखा जाएगा।

(घ) उत्पाद की जांच करने के लिए नियंत्रण के न्यूनतम स्तर, अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

(iv) परिरक्षण नियंत्रण

भंडारकरण और अभिवहन दोनो के ही दौरान भली भांति परिरक्षित किया जाएगा।

(v) पैकिंग नियंत्रण :—

(क) उत्पाद की पैकिंग के लिए अनुसूची में दिए गए नियंत्रणो की तुष्टि की दृष्टि से पैकिंग विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

अनुसूची I

(1) अल्ट्रामैरीन नील (तकनीकी श्रेणी) के लिए नियंत्रण के स्तर

क्रम सं०	अपेक्षाएं	निर्देश	आवृत्ति
1	रंग	अनुमोदित नमूना	प्रति बैच एक
2	अभिरंजक चूर्ण और टोन	अनुमोदित नमूना	प्रति बैच एक
3.	वाष्पशील पदार्थ	अनुमोदित नमूना	प्रति बैच एक
4.	छानने पर अवशिष्ट	अनुमोदित नमूना	प्रति बैच एक
5	तेल अवशोषण	अनुमोदित नमूना	प्रति बैच एक
6.	क्षारीयता	अनुमोदित नमूना	प्रत्येक परेषण
7.	जल में घुलनशील पदार्थ (भार के अनुसार अधिकतम प्रतिशत)	अनुमोदित नमूना	प्रति बैच एक

(2) पैकिंग के लिए नियंत्रण स्तर—

2.1 अल्ट्रामैरीन नील (तकनीकी श्रेणी) के प्रत्येक परेषण की क्षरणरोधिता, नमी से पर्याप्त बचाव और अभिवहन के दौरान ठीक बने रहने की बाबत जाच की जाएगी।

2.2 प्रत्येक पैकेज पर या उस पर लगाए गए लेबल पर निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा अर्थात्:—

(क) सामग्री का नाम,

(ख) विनिर्माता का नाम तथा व्यापार चिन्ह, यदि कोई है ;

(ग) विनिर्माण का मास तथा वर्ष ,

(घ) सामग्री की मात्रा, और।

(ङ) संकेत मे बैच संख्याक या अन्यथा जिससे कि विनिर्माण बैच का अभिलेख से पता लगाया जा सके।

अनुसूची II

अल्ट्रामैरीन नील (धुलाई श्रेणी) के लिए नियंत्रण स्तर

क्रम सं०	अपेक्षाएं	निर्देश	आवृत्ति
1	रंग आभा	अनुमोदित नमूना	प्रति बैच एक
2	जल में परिक्षेपणता	अनुमोदित नमूना	प्रति बैच एक
3	नील किए गए कपड़े में सफेदी	अनुमोदित नमूना	प्रति बैच एक

2 पैकिंग के लिए नियंत्रण स्तर :—

2.1 अल्ट्रामैरीन नील (धुलाई श्रेणी) के प्रत्येक परेषण की क्षरणरोधिता नमी से पर्याप्त बचाव और अभिवहन के दौरान ठीक बने रहने की बाबत जांच की जाएगी।

2.2 प्रत्येक पैकेज पर या उन पर लेबलकर निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा, अर्थात :—

(क) सामग्री का नाम;
(ख) विनिर्माता का नाम और व्यापार चिन्ह, यदि कोई है;
(ग) विनिर्माण का मास तथा वर्ष;
(घ) सामग्री की मात्रा, और
(ङ) संकेत में बैच संख्यांक या अन्यथा जिससे कि विनिर्माण बैच का अभिलेख से पता लगाया जा सके।

उपाबंध II

1. परीक्षणानुसार निरीक्षण :—

1. अल्ट्रामैरीन नील के परीक्षण का, अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों से उसकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए, निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा।

2. नमूने लेने के बारे में संविदात्मक विनिर्देशों में विनिर्दिष्ट अनुबन्धों के अभाव में, नीचे दी गई सारणी में अधिकथित विनिर्देश लागू होंगे।

सारणी

नमूना लेने का मापदंड

लॉट आकार	नमूना आकार
29 तक	1
21 से 60 तक	2
61 से 150 तक	3
151 से 300 तक	4
301 से 500 तक	5
501 से 1000 तक	6
1001 से 1500 तक	7
1501 से 2000 तक	8
2001 से 3000 तक	9
3001 से 4000 तक	10
4001 से 6000 तक	11
6001 और उससे अधिक	12

टिप्पण :—लॉट :—किसी भी परेषण में, अल्ट्रामैरीन नील के एक ही श्रेणी और आकार के सभी पैकेजों से मिलकर एक लॉट बनेगा।

3. परीक्षण की पद्धतियां राष्ट्रीय मानक के अनुसार होंगी।

[सं 6(40)/72/नि० नि० तथा नि० उ०]

S.O. 92.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government, hereby, makes the following rules, namely :—

1. Short title and commecement—(1) These rules may be called the Export of Ultramarine Blue (Quality Control and Inspection) Rules, 1981;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection Act, 1963 (22 of 1963).
(b) "Agency" means any one of the agencies established under section 7 of the Act at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay, and Delhi;
(c) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;
(d) "Ultramarine Blue" means any or all of the following types, namely :—
(1) Ultramarine Blue (Technical Grade)
(2) Ultramarine Blue (Laundry Grade)
(e) "Schedule" means the Schedule appended to those rules.

3. Basis of inspection—Inspection of ultramarine blue for export shall be carried out with a view to seeing that the ultramarine blue conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) either,—

(a) by ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary in process quality control as specified in Annexure-I,

(b) on the basis of inspection and testing carried out in the manner specified in Annexure-II.

4. Procedure of inspection—(1) An exporter intending to export a consignment of ultramarine blue shall give an intimation in writing to the agency furnishing therein details of the contractual specifications along with a copy of the export contract or order to enable the agency to carry out inspection in accordance with rule 3.

(2) For export of ultramarine blue manufactured by exercising adequate inprocess quality control as laid down in Annexure I and the manufacturing unit adjudged as having adequate inprocess quality control drills by the Council/Panel of experts constituted by the Council for this purpose, the exporter shall also submit along with the intimation mentioned in sub-rule (1) a declaration that the consignment of ultramarine blue intended for export has been manufactured by exercising adequate quality control as laid down in Annexure-I and that the consignment conforms to the standard specifications recognised for the purpose.

(3) A copy of each such intimation or declaration or both shall also be simultaneously endorsed to any of the following offices of the Council which is nearest to the place of inspection, namely :

Head office : Export Inspection Council, World Trade Centre, (14/1B, Ezra Street, (7th floor) Calcutta-1.

Regional offices Export Inspection Council, Aman Chamber, 113, M. Karve Road, Bombay–400 004.
Export Inspection Council, Manohar Buildings, Mahatma Gandhi Road, Ernakulam, Cochin–682 011.
Export Inspection Council, Municipal Market Building, 3, Saraswati Marg, Karol Bagh, New Delhi-5.

(4) The exporter shall also furnish to the agency the identification marks applied on the consignment.

(5) Every intimation under sub-rule (1) and declaration if any, under sub-rule (2) shall be given not less than 7 days prior to the despatch of the consignment from the manufacturers premises.

(6) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the declaration if any, under sub-rule (2), the agency

(a) On satisfying itself that during the proces of manufacture the manufacturer had exercised adequate quality control as laid down in Annexure I and followed the instructions, if any, issued by the Council in this regard to manufacture the product to conform to the standard specifications recognised for the purpose, shall within seven days issue a certificate declaring the consignment of ultramarine blue as export worthy In case where the manufacturer is not the exporter, however the consignment shall be physically verified and such verification and inspection as necessary shall be carried out by the agency to ensure that the above conditions are complied with. The Agency shall, however, conduct, spot checks of some of the consignments meant for export.

(b) In case where the exporter has not declared under sub-rule (2) that adequate quality control as laid down in Annexure I had been exercised, on satisfying itself that the consignment

of ultramarine blue conforms to the standards specification recognised for the purpose on the basis of inspection|testing carried out as laid down in Annexure II or on the basis of both shall within seven days of carrying out such inspection issue a certificate declaring the consignment of ultramarine blue as exportworthy

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of seven days refuse to issue a certificate to the exporter declaring the consignment of ultramarine blue as exportworthy and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

(7) In cases where the manufacturer is not the exporter or the consignment is inspected under sub-rule (6) (b) or in both the cases, the agency shall immediately after completion of the inspection, seal the packages in the consignment in a manner as to ensure that the sealed packages can not be tampered with. In case of rejection of the consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the Agency, but in such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

5. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out either (a) at the premises of the manufacturer of such product or (b) at the premises at which the goods are offered by the exporter provided adequate facilities for the purpose exist therein.

6. Inspection fee.—Subject to minimum of Rs. 50 for each consignment a fee at the rate of forty paise for every one hundred rupees of the FOB value for each such consignment shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee.

7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (6) of rule 4, may within ten days of the receipt of communication of such refusal by, him, prefer an appeal to such panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons as may be constituted by the Central Government for the purpose.

(2) The panel of experts shall consist of at least two thirds of non-officials of the total membership of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel of experts shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of by the panel of experts within fifteen days of it's receipt.

8. Repeal—The Export of Ultramarine Blue (Quality Control and Inspection) Rules, 1977 are hereby repeated.

ANNEXURE-I

(See under rule 3 (a))

Quality Control

The quality control of ultramarine blue shall be ensured by the manufacturer by effecting the following controls at different stages of manufacture, preservation and packing of products as laid down below together with the levels of control as set out in the Schedule appended hereto.

(i) Purchase and raw material control—

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of raw materials to be used.

(b) Either the accepted consignments shall be accompanied by a supplier's test and inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specifications in which case occasional checks shall be conducted at least once in 10 consignments by the purchaser for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test or inspection either in the laboratory within the factory or in an outside laboratory or test house.

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be based on the recorded investigations.

(d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials and for disposal of the rejected materials.

(e) Adequate records in respect of the aforesaid controls shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process Control

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for different stages of manufacture.

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specification.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to ensure the possibility of verifying the controls exercised during the process of manufacture.

(iii) Product Control

(a) The manufacturer shall have either his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to check up whether the product conforms to specifications recognised under section 6 of the Act.

(b) Sampling for test and inspection to be carried out shall be based on the recorded investigation.

(c) Adequate records in respect of sampling and test carried out shall be regularly and systematically maintained.

(d) The minimum levels of control to check the products shall be as specified in the Schedule.

(iv) Preservation Control.

The product shall be well preserved both during the storage and transit.

(v) Packing Control.

Packing specifications shall be laid down with a view to satisfying the controls as mentioned in the Schedule for packing of the products.

SCHEDULE I

(1) Levels of controls for ultramarine blue (Technical Grade)

Sl. No.	Requirement	Reference	Frequency
1.	Colour	Approved sample	One per batch
2.	Staining power and tone.	Approved sample	One per batch
3.	Volatile matter	Approved sample	One per batch
4.	Residue on sieve	Approved sample	One per batch
5.	Oil absorption	Approved sample	One per batch
6.	Alkalinity	Approved sample	One per batch
7.	Matter soluble in water, per cent by weight Max.	Approved sample	One per batch

(2) Levels of control for packing

2.1 Each consignment of ultramarine blue (technical grade) shall be checked for leakproofness, adequate protection against moistrue and handling during transist.

2.2 The following information shall be given on each package or the label applied to it namely :—

(a) Name of the material ;
(b) Manufacturer's name and trade mark, if any;
(c) Month and year of manufacture ;
(d) Quality of the material, and
(e) Batch number in code or otherwise to enable the batch of manufacture to be traced from records.

SCHEDULE—II

(1 Levels of control for ultramine blue (laundary grade)

Sl. No.	Requirement	Refernce	Ferequency
1.	Shade of colour	Approved sample	One per batch
2.	Dispersibility in Water	Approved sample	One per batch
4.	Whitness of the treated cloth	Approved sample	One per batch

(2) Levels of control for packing

2.1 Each consignment of ultramarine blue (laundry grade) shall be checked for leakproofness, adequate protection against moisture and handling during transit.

2.2 The following information shall be given in each package or the label applied to it :—

(a) Name of the material ;
(b) Manufacturer's name and trade mark, if any ;
(c) Month and year of manufacture ;
(d) Quantity of the material ; and
(e) Batch number in code or otherwise to enable the batch of manufacture to be traced from records.

ANNEXURE II

Consignmentwise inspection :—

1. The consignment of ultramarine blue shall be subjected to inspection and testing to ensure conformity of the same to the standard specifications recognised under section 6 of the Act.

2. In the absence of specific stipulation in the contractual specification as regards sampling criteria, the same laid down in Table given below shall be applicable.

TABLE

SCALE OF SAMPLING

Lot size	Sample Size
Upto 20	1
21 to 60	2
61 to 150	3
151 to 300	4
301 to 500	5
501 to 1000	6
1001 to 1500	7
1501 to 2000	8
2001 to 3000	9
3001 to 4000	10
4001 to 6000	11
6001 and above	12

Note :—In any consignment, all the packages containing the same grade and type of ultramarine blue shall be grouped together to constitute a lot.

3. Methods of test will be as per National Standard.

[No. 6(40)/72-FI & EP]

का० आ० 93.—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) तारीख 29 अक्तूबर, 1977 में प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3358 को अधिक्रान्त करते हुए अल्ट्रामैरीन नील का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित अभिकरणों को मान्यता देती है, अर्थात् :—

1. निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कलकत्ता,
'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर'
14/1-बी, एजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल)
कलकत्ता-700001

2. निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मद्रास,
123, माऊंट रोड,
मद्रास -600006

3 निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुम्बई,
अमन चैम्बर्स (चौथी मंजिल),
113, महर्षि कार्वे रोड,
मुम्बई, 400004

4 निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोचीन,
मनोहर बिल्डिंग
महात्मा गांधी रोड,
एरनाकुलम, कोचीन-11

5 निर्यात निरीक्षण अभिकरण दिल्ली,
म्युनिसिपल मार्केट बिल्डिंग,
3, सरस्वती मार्ग, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना में "अल्ट्रामैरीन नील" से निम्नलिखित प्रकारों में से किसी या सभी प्रकार का अल्ट्रामैरीन नील अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(क) अल्ट्रामैरीन नील (तकनीकी श्रेणी)

(ख) अल्ट्रामैरीन नील (धुलाई श्रेणी)

[सं० 6(40)/72-नि०नि० तथा नि०उ०]

सी०बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

S.O. 93.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 3358 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), 29th October, 1977, the Central Government hereby recognised the following agencies for quality control and inspection of ultramarine blue prior to it's export namely :—

1 Export Inspection Agency—Calcutta
World Trade Centre,
14/1B, Ezra Street (8th floor),
Calcutta-700001.

2. Export Inspection Aency—Madras
123, Mount Road,
Madras-600006.

3. Export Inspection Agency—Bombay
Aman Chambers (4th floor),
113, M. Karve Road,
Bombay-400004.

4. Export Inspection Agency—Cochin
Manohar Building,
Mahatma Gandhi Road,
Ernakulam, Cochin-11.

5. Export Inspection Agency—Delhi
Municipal Market Building,
3, Saraswati Marg, Karol Bagh,
New Delhi-110025.

Explanation.—In this notification "Ultramarine Blue" means ultramarine blue of any or all of the following types, namely :—

(a) Ultramarine blue (Technical Grade).

(b) Ultramarine blue (Laundry Grade).

[No. 6(40)/72-FI & EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1980

का०आ० 94.—सर्वश्री शिले इण्डस्ट्रीज, 335, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, बम्बई को माल की संलग्न सूची के अनुसार अप्रैल 77—मार्च, 1978 की अवधि के लिए 3,10,300 रुपए का कच्चा माल और संघटक आयात करने के लिये आयात लाइसेंस संख्या पी/डी/2208289, दिनांक 16-7-77 प्रदान किया गया है।

2. फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल भी उपयोग किए बिना खो गई है, अस्थानस्थ हो गई है। फर्म इस बात के लिए सहमत है और वचन देती है कि यदि बाद में मूल लाइसेंस मिल भी गया तो इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए वापस कर दिया जायगा।

3. अपने तर्क के समर्थन में, फर्म ने आयात निर्यात क्रियाविधि पुस्तक 1980-81 के अध्याय 15 के पैरा 352 के अनुसार यथा अपेक्षित एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2208289, दिनांक 16-7-77 की मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति खो गई है और निदेश देते हैं कि आवेदक को लाइसेंस की सीमा शुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जाए। लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति रद्द कर दी गई है।

4. लाइसेंस की सीमा शुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

लाइसेंस का ब्यौरा

लाइसेंस संख्या एवं दिनांक	माल का ब्यौरा	देश	तक वैध	मूल्य रुपयों में	उपयोग किए गए रूपए	शेष
पी/डी/2208289, 16-7-77	कच्चा माल एवं संघटक	रुपया भुगतान क्षेत्र	15-7 1979	3,10,300	शून्य	3,10,300/-

[मिसिल सं० एम ए सी एच/एस-6(1) ए एम-78/आर एम 4/293]

शंकर चन्द, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

Office of the Chief Controller of Imports & Exports

ORDER

New Delhi, the 22nd December, 1980

S. O. 94.—M/s. Shilay Industries, 335, Abdul Rahman Street, Bombay have been granted import licence No. P/D/2208289 dated 16-7-77 for Rs. 3,10,300/- for the import of Raw Material and Components as per list of goods attached for the period April 77 March, 78.

2. The firms has now requested for the issue of duplicate Customs Purposes Copy of the above licence on the ground that the original Customs Purposes Copy has been lost/misplaced without having been registered with any Customs Authority and utilized at all. The firms agrees and undertakes to return the original licence if traced later to this office for record.

3. In support of their contention the applicant have filed an affidavit, as required in para 352 of Chapter XV of the Hand Book of Import-Export, Procedure 1980-81. The undersigned is satisfied that the original Customs Pruposes Copy of import licence No. P/D/2208289 dated 16-7-77 has been lost and directs that duplicate copy of the Customs Purposes Copy of the licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes Copy of the licence has been cancelled.

4. The duplicate Customs Purposes Copy of the licence is being issued separately.

Particulars of the licence

File No. date	Description of goods	Country	Valid Upto	Value Rs.	Utilized Rs.	Balance Rs.
P/D/2208289-16-7-77	RM & Components	R.P.A.	15-7-79	3 10,300/-	NIL	3,10,300/-

[F. No. MACH/S-6(1) AM-78/RM. 4/293]

SHANKER CHAND, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Chief Controller of Impotts and Expoits.

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1980

का० आ० 95.—सर्वश्री भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० जलाहल्ली, बंगलौर को, स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत, 20,70,000 रुपये का पूंजीगत माल आयात करने के लिये आयात लाइसेंस सं० आई/सी जी/230966/सी/एक्स एक्स/75/एच/80/सी जी-2, दिनांक 15-5-1980 प्रदान किया गया था। फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति खो गई या अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी कहा गया है कि सीमा शुल्क निकासी प्रति को किसी भी सीमा शुल्क

प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और इसीलिए उसके धन राशि का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक, बंगलौर के सामने विधिवत शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूँ कि आयात लाइसेंस सं० आई/सीजी/2030966, दिनांक 15-5-80 की मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति फर्म से खो गई है। अस्थानस्थ हो गई है। यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955, दिनांक 7-12-55 की उपधारा 9 सीसी द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि०, बंगलौर को जारी किए गए आयात लाइसेंस सं० आई/ सीजी /2030966, दिनांक 15-5-80 की उक्त मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[सं० सीजी-2/डीईएफ/1/80-81/1106]

जी० एस० ग्रेवाल, उप-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

ORDER

New Delhi, the 24th December, 1980

S.O. 95.—M/s. Bharat Electronics Ltd., Jalahalli, Bangalore were granted an import licence No. I/CG/2030966/C/XX/75/H/80/CGII dated 15-5-1980 for Rs. 20,70,000 (Rupees Twenty lakhs and seventy thousands only) for import of Capital Goods under Free Foreign Exchange. The firm has applied for issue of Duplicate copy of Customs Purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the Original Customs Purposes copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Customs Purposes copy of the licence was not registered with any Customs Authority and as such the value of Customs Purpose copy has not been utilised at all.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Bangalore. I am accordingly satisfied that the original customs purposes copy of import licence No. I/CG/2030966 dt. 15-5-80 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original customs purposes a copy No. I/CG/2030966 dt. 15-5-80 issued to M/s. Bharat Electronics Ltd., Bangalore is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. CGII/DEF/1/80-81|1106]

G. S. GREWAL, Dy. Chief Controller of Imports and Exports.
for Chief Controller of Imports & Exports

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

मद्रास, 29 नवम्बर, 1980

का० आ० 96.—सर्वश्री लक्ष्मी पेकिंग प्रेवेट लिमिटेड, 38 टाउन रेलवे स्टेशन रोड़, सेलम-63 6001 को रुपये 1,83,100 तक फालतू पुर्जे का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-डी- 2217242-सी- एक्सएक्स-74-एम-79 दिनांक 31-3-80 जारी किया गया था उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति और सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति खो जाने के कारण, उनकी अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए लाइसेंसधारी ने आवेदन किया है।

आवेदक ने अपने तर्क के संमर्थन में एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी-डी-2217242-सी एक्सएक्स-74-एम-79 दिनांक 31-3-80 (मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति तथा सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति) खो दी गयी है और आदेश देता है कि आवेदक को उपयुक्त लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति तथा सीमा शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति) अनुलिपि प्रति जारी की जाए लाइसेंस की मूल प्रति एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

अनुलिपि प्रति लाइसेंस संख्या (मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति तथा सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति) पी-डी-2464685 एवं पी-डी-2464686 दिनांक 4-11-80 अलग जारी किये गये है।

[फा० सं० आईटीसी-डीजीटीडी-433-ईएस-एएम80-एयू1]

Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports

ORDER

Madras, the 29th November, 1980

S.O. 96.—M/s. Lakshmi Packaging Private Ltd., 38, Town Railway Station Road, Salem-636001 were granted licence No. P|D|2217242|C|XX|74|M|79 dt. 31-3-80 for import of spares for Rs. 1,83,100. They have requested for the issue of duplicate copy of the above licence (Exchange Control Purposes Copy & Customs Purposes Copy) which has been lost by them.

In support of their contention the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original copy of the licence No. P|D|2217242|C|XX|74|M|79 dt. 31-3-80 (E.C & C.C.P. Copy of Import Licence) has been lost and directs that a duplicate copy of the said licence (E.C. & C.C.P. Copy of Import Licence) should be issued to them. The original copy of the licence is hereby cancelled.

A duplicate licence (E.C. & C.C.P. Copy of Import Licence) No. P|D|2464685 and 2464686 dt. 4-11-80 has been issued separately.

[F. No.ITC/DGTD/433/ES/AM.80/AU.I]

का० आ० 97.—सर्वश्री वेल लैनर्स, 3, कथिड्रल गार्डन लेन, मद्रास 600034 को, रुपये 1,48,800 तक, एक नम्बर स्टेनकोइम्पोर्ट-यूएसएसआर-माडल 3 एम 185, 400 वोल्ट्स 50 सैकिल्स, 3 फेस, सप्लाई पर उचित प्रचलन के लिए बिजली से सुसज्जित सेन्टरलैस ग्राइंडर का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी- सी जी- 2075283-सी- एक्स एक्स-73-एम-79 दिनांक 2-11-79 जारी किया गया था। लाइसेंसधारी ने उपयुक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इसलिए आवेदन किया है कि उपयुक्त लाइसेंस किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत करवाये बिना और उपयोग में लाये बिना खो दी गयी है।

आवेदक ने अपने तर्क के समर्थन में एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से सन्तुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी-सीजी-2075283 सी एक्स एक्स-73-एम-79 दिनांक 28-11-79 की सीमा शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की मूल प्रति खो दी गयी है और आदेश देता है कि आवेदक को उपयुक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति जारी किया जाए।

सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति का अनुलिपि लाइसेंस संख्या डी-2464837 दिनांक 12-11-80 अलग जारी किया गया है।

[फा० सं० आईटीसी-सीजी-एमएसआई-138-एएम-80-एयू 2]

टी० एन० वेंकटेश्वरन, उप-मुख्य नियन्त्रक,

आयात तथा निर्यात

कृते संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात

S.O. 97.—M/s. Vel Liners, 3, Cathedral Garden Lane, Madras-600034 were granted a licence No. P|CG|2075283|C|XX|73|M|79 dated 28-11-79 for the import of 1 No. Stankoimport/USSR/Model 3M 195 Centreless Grinder equipped with electricals suitable for operation on 400 Volts 50 cycles 3 Phase A.C. supply, for a value of Rs. 1,48,800. They

have requested for the issue of a duplicate of the Customs Purposes Copy of the licence stating that they have misplaced the original Customs Purposes Copy of the licence without registering with any Customs authority or utilising the same

In support of their contention the applicant have filed an affidavit The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes Copy of the licence No P|CG|2075283|C|XX|73|M|79 dated 28-11-79 has been lost and directs that a duplicate copy of the said licence should be issued to them

A duplicate Customs Purposes copy of licence bearing No D/2464687 dated 12 11-80 has been issued separately

[F No ITC/CG/SSI 138/AM 80/AU II]

T N VENKATESWARAN Dy Chief Controller of Imports & Exports

For Joint Chief Controller of Imports and Exports

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली 18 दिसम्बर, 1980

का० आ० 98 —समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह विनियम 1955 के विनियम 3 के उपविनियम (4) के अधीन प्राप्त अधिकारों के अनुसार अनुसूची में जिस IS 2339-1963 के ब्यौरे दिए गए हैं उसके उपबन्धों में मानक चिन्ह के उपयोग में गति लाने के उद्देश्य से परीक्षात्मक रूप में संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के द्वारा भारतीय मानक के अनुरूप बने माल की गुणता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अधिसूचना तुरन्त लागू हो जायगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक जिनके उद्देश्य में संशोधन किए गए हैं	उपबन्ध में किए गए संशोधन के विवरण
1	IS 2339-1963 दोहरे धारकों में सामान्य कार्यों के लिए एलुमिनियम रंग-रोगन की विशिष्टि।	परिवर्तन (आवरण पृष्ठ पृष्ठ 1 और 3)—वर्तमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित कर लीजिए 'सामान्य कार्यों के लिए एलुमिनियम रंग रोगन की विशिष्टि' (पृष्ठ 1 खंड 1 1 पंक्ति 3)—इसमें दोहरे धारकों शब्दों को हटा दीजिए। (पृष्ठ 4, खंड 1 1 पंक्ति 4)—'चेम्बर्स' के स्थान पर 'चेम्बर्स/कंटेनर्स' कर लीजिए। (पृष्ठ 6 खंड 1 उपशीर्षक)—वर्तमान सामग्री के स्थान पर निम्नलिखित कर लीजिए 'सामान्य कार्यों के लिए एलुमिनियम रंग रोगन की अपेक्षाएं' (पृष्ठ 6, खंड 7 1 भराई)—वर्तमान सामग्री के स्थान पर निम्नलिखित कर लीजिए "रंग रोगन दोहरे धारकों में भरा जाएगा फिर भी यदि मध्यम रूप वार्निश 4 लीटर से अधिक हो तो एलुमिनियम पेस्ट अलग पैक किया जा सकता है। अनुवृद्धि (पृष्ठ 5, खंड 5 1)—इस खंड के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ लीजिए 'टिप्पणी—जब मध्यम रूप वार्निश 4 लीटर से अधिक हो तो एलुमिनियम पेस्ट अलग पैक किया जा सकता है।'

[सं० सी एम डी/13 4]

ए० के० गुप्ता, महानिदेशक

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 18 December, 1980

S O 98 In exercise of the powers conferred on me under sub-regulation (4) of regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation, 1955, as amended from time to time modifications to the provisions of IS 2339-1963 details of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have tentatively been made with a view to expediting the use of the Standard Mark, without in any way affecting the quality of goods covered by the relevant Standard This notification shall come into force with immediate effect

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of Indian Standard	the provisions of which have been modified	Particulars of the Modifications made to the provisions
1.	IS : 2339-1963 Specification for aluminium paint for general purposes in dual container.		Alterations (Cover page, Pages 1 and 3 —Substitute the following for the existing title : "SPECIFICATION FOR ALUMINIUM PAINT FOR GENERAL PURPOSES". (Page 4, Clause 1.1, Line 3) —Delete the words "in dual container" (Page 4, Clause 1.1, Line 4) —Substitute "Chambers/containers" for "Chambers" (Page 6, Table 1, Subtitle) —Substitute the following for the existing text : "REQUIREMENTS FOR ALUMINIUM PAINT FOR GENERAL PURPOSES" (Page 6, Clause 7.1, Packing) —Substitute the following for the existing text : "The paint shall be packed in dual container. However, when varnish medium is more than 4 litres, aluminium paste may be packed separately." Addendum (Page 5, Clause 5.1)—Add the following note after this clause : "NOTE—When varnish medium is more than 4 litres, aluminium paste may be packed separately."

[No. CMD/13:4]

A. K. GUPTA, Director General.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1980

का० आ० 99.—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद (प्रक्रिया सबधी) नियम, 1952 के नियम 2,4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को इस आदेश के सरकारी गजट मे प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिये अकार्बनिक रसायन उद्योगों की विकास परिषद के सदस्यों के रूप मे नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अकार्बनिक रसायन उद्योग की विकास परिषद

1 श्री के० वी० रामनाथन, सचिव पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मत्रालय, रसायन और उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2. श्री एस० एम० केलकर, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मत्रालय, रसायन और उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
3 श्री पी० आर० चन्द्रन, उप सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
4 श्री एम० सत्यपाल, सलाहकार, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
5. डा० डी० के० राय, औद्योगिक सलाहकार, औद्योगिक लागत एव मूल्य ब्यूरो, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
6. श्री ए० के० बोस, औद्योगिक सलाहकार (रसायन), डी० जी० टी० डी, उद्योग भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
7 डा० के० अधोरामूर्ति, सलाहकार (रसायन), पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।	सदस्य
8. डा० के० सी० वार्पने, उप महाप्रबन्धक (तकनीकी), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जौली मेकर चैम्बर स 1 227, वेकवे रिक्लेमेशन स्कीम, बम्बई-400021	सदस्य
9 श्री के० एम० शर्मा, अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक, फर्टिलाइजर (योजना और विकास) इंडिया लि०, सिन्दरी।	सदस्य
10. डा० एल के० दोराईस्वामी, निदेशक, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना	सदस्य
11 श्री कल्याण सेन, अध्यक्ष, भारतीय रसायन निर्माता सघ, इंडिया एक्सचेंज, कलकत्ता-1	सदस्य
12 श्री वी० रामादुराई, अध्यक्ष, अल्कली निर्माता संघ, 105, बजाज भवन, नैरीमन प्वाइंट, बम्बई-21	सदस्य
13 श्री पाल पोथेन, तकनीकी विशेषज्ञ, कृषक भारत कोआपरेटिव लि०, रेड रोड, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19	सदस्य
14 श्री सत्यानन्द, कार्यकारी निदेशक, फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया, न्यू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-67	सदस्य

2 विकास परिषद (प्रक्रिया सबधी) नियम 1952 के नियम, 2 के अनुच्छेद (ग) के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विकास परिषद के कार्य का सचालन करने के लिये रसायन और उर्वरक विभाग,

नई दिल्ली के संयुक्त सचिव (उर्वरक) श्री एस० एम० केलकर को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

[फा० सं० 8(9)/77सी०डी०एन०]
लक्ष्मी शंकर केकर, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 23rd December, 1980

S.O. 99.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the industries (Development and Regulation) Act 1951, read with rules 2, 4 and 5 of the Development councils (Procedural) Rules 1952, the Central Government hereby appoints, for a period of two years with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, the following persons to be members of the Development Council for Inorganic Chemicals Industries, namely:—

DEVELOPMENT COUNCIL FOR INORGANIC CHEMICALS INDUSTRIES

1. Shri K.V. Ramanathan, Secretary, Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizers Department of Chemicals & Fertilizers Shastri Bhavan, New Delhi. — Chairman
2. Shri S.M. Kelkar, Joint Secretary, Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizers Department of Chemicals & Fertilizers Shastri Bhavan, New Delhi. — Member
3. Shri P.R. Chandran, Deputy Secretary, Department of Industrial Development, Udyog Bhavan, New Delhi. — Member
4. Shri M. Satyapal, Adviser, Planning Commission, Yojna Bhawan, New Delhi. — Member
5. Dr. D.K. Roy, Industrial Adviser, Bureau of Industrial Costs and prices, Lok Nayak Bhavan, New Delhi. — Member
6. Shri A.K. Bose, Industrial Adviser (Chemicals) DGTD, Udyog Bhavan, New Delhi. — Member
7. Dr. K. Aghoramurthy, Adviser (Chemicals) Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Fertilizers, Shastri Bhavan, New Delhi. — Member
8. Dr. K.C. Varshney, Deputy General Manager (Technical), Industrial Development Bank of India, Jolly Maker Chambers No. 1, 227, Backbay Reclamation Scheme, Bombay — 400021 — Member
9. Shri K.S. Sarma, Chairman & Managing Director, Fertilizer (Planning & Development) India Ltd., Sindri. — Member
10. Dr. L.K. Doraiswamy, Director, National Chemical Laboratory, Poona. — Member
11. Shri Kalyan Sen, President, Indian Chemicals Manufacturers Association, India Exchange, Calcutta-1. — Member
12. Shri V. Ramadurai, President, Alkali Manufacturers Association, 105, Bajaj Bhavan, Nariman point, Bombay-21. — Member
13. Shri Paul pothan, Technical Expert, Krishak Bharat Cooperative Limted, Red Rose, Nehru Place, New Delhi-19. — Member
14. Shri Satyanand, Executive Director, Fertilizer Association of India, Near Jawaharlal Nehru University, New Delhi — 67. Member

2. In pursuance of clause (c) of Rule 2 of the Development councils (Procedural) Rules, 1952 the Central Government hereby appoints Shri S.M. Kelkar, Joint Secretary (Fertilizers) Department of Chemicals & Fertilizers, New Delhi, to carry on the functions of the Member- secretary to the said Development Council.

[File No. 8 (9) /77-CDN]
I. S. KAICKER Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1980

का०आ० 100—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 5 जुलाई, 1980 के पृष्ठ 2388-2391 पर प्रकाशित भारत सरकार के इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 1801 तारीख 20 जून, 1980 में :

पृष्ठ 2388 पर (i) अधिसूचना के पैरा "ख" में "852.82 हैक्टर" के स्थान पर "852 81 हैक्टर" पढ़िए।

(ii) टिप्पण 2 के पैरा 8(1) में "तीन दिन के भीतर" के स्थान पर "तीस दिन के भीतर" पढ़िए।

पृष्ठ 2389 अनुसूची "क" में "पठखेरा कोयला खान" के स्थान पर "पाथरखेरा कोयला खान" पढ़िए तथा जहां कहीं "पठखेरा" आया है उसके स्थान पर "पाथरखेरा" पढ़िए।

पृष्ठ 2391 प्रथम पंक्ति में "बड़गोना ग्राम में अर्जित किए जानेवाले प्लाटों के संख्यांक" के स्थान पर "बगड़ोना ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों के संख्यांक" पढ़िए।

[संख्या 19(7)79-सी एल]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd December, 1980

S.O. 100.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal) No. S.O. 1801 dated the 20th June, 1980 published at pages 2391 — 94 of the Gazette of India, part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 5th July, 1980 :

at page 2391 — In the third line for "S.O. 1449 dated the 16th April 1979" read "S.O. 1449 dated the 18th April, 1979".

at page 2392 (i) In clause (2) of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of

1957) quoted under the heading "Objections to Acquisition" for "Objector and opportunity" read "Objector an opportunity"

(ii) In Schedule 'A' under the heading "plot numbers to be acquired in village Bagdona" for "147 (P), 147(P) read "146 (P), 147 (P)".

at page 2393 -

(i) In the Second line for "meets at point 'A' "read " meets at point 'A1' ".

(ii) In the marginal notes for " I-11-12-13-14-15-16-17-18-19-I-10-J-K" read I-11-12-13-14-15-16-17-18-19-I10-J-K".

[No 19(7)/79-CL]

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1980

का०आ० 101—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 627, दि० 15 मार्च, 1980 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार की पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और मध्यप्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 5900.00 एकड़ लगभग या 2387 61 हेक्टर (लगभग) भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उस अनुसूची में वर्णित 5900.00 एकड़ (लगभग) या 2387 61 हेक्टर (लगभग) भूमि का अर्जन किया जाता है।

2 इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण, कलक्टर सीधी (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में, या कोयला नियंत्रक के 1, कौंसिल हाउस कलकत्ता स्थित कार्यालय में या केन्द्रीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड, (राजस्व अनुभाग), दरभंगा हाउस, रांची बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

दूधीचुआ ब्लाक I

सिंगरौली कोयला क्षेत्र

जिला सीधी (मध्य प्रदेश)

रेखांक संख्या राजस्व 78/79 तारीख 26-10 79
(इसमें अर्जित भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	तहसील संख्या	परगना	जिला क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	करवारी	सिंगरौली	50	सिंगरौली	सीधी	पूर्ण
2.	चूरीडाह	,,	179	,,	,,	भाग
3.	दूधीचुआ	,,	249	,,	,,	पूर्ण
4	मधौली	,,	146	,,	,,	भाग

कुल क्षेत्र 5900.00 एकड़ (लगभग)
या 2387 61 हेक्टर (लगभग)

ग्राम करवारी में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक

1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 1/4, 4/5, 4/6, 4/7 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8 से 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 19/1, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 25/1 25/2 25/3, 26/1 26/2, 27/6, 27/2, 28 से 32 तक।

ग्राम चूरीडाह में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक

9(भाग), 10 (भाग), 11(भाग), 12 (भाग), 13 से 16 तक, 17(भाग), 18 से 45 तक।

ग्राम दूधीचुआ में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक.

1 से 6 तक, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16 से 25 तक, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 34 से 37 तक, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 39/2, 40 से 44 तक, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 46/1, 46/2, 46/3, 47/1, 47/2, 47/3, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 53, 54, 55/1 55/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 58 से 96 तक, 96/1, 96/2, 96/3, 97 से 146 तक, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 149, 150/1, 150/2, 150/3, 151, 152/1, 152/2, 152/3, 153 से 157 तक, 158/1, 158/2, 159 से 202 तक।

ग्राम मधौली के सम्मिलित किए गए प्लाटों के संख्यांक

514 (भाग) 514(भाग) 515, 516 516/1 517 से 521 तक 521/1 521/2 521/3, 521/4 522 (भाग), 525(भाग), 525/1, 526(भाग) 527 534(भाग) 534 535 536, 537(भाग), 538(भाग), 539(भाग), 540(भाग), 592 से 594 (भाग) और 595.

सीमा विवरण

क-ख	रेखा ग्राम मधौली के प्लाट संख्या 514 513, 522, 525 और 525 से होकर जाती है जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 17(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र की सम्मिलित सीमा बनाती है।
ख-ग	रेखा ग्राम मधौली और दूधीचुआ की भागत सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है, जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 17(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र की सम्मिलित सीमा बनाती है।
ग-घ	रेखा ग्राम मधौली के प्लाट संख्या 533 और 540 से होकर जाती है, जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 17(1) के अधीन अर्जित भूमि की सम्मिलित सीमा बनाती है।
घ-ङ-ङ/1	रेखा ग्राम मधौली के प्लाट संख्या 540, 539, 538, 537, 592, 595 और 594 से होकर, ग्राम दूधीचुआ और सरसोंवराजा टोला की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है, जो कोयला अधिनियम की धारा 17(1) के अधीन जबरन कब्जे के लिए अर्जित क्षेत्र की सम्मिलित सीमा बनाती है।
ङ/1-च	रेखा ग्राम दूधीचुआ और सरसोंवराजा टोला की भागत सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है।
च-छ	रेखा ग्राम दूधीचुआ की दक्षिणी और भागतः पूर्वी सीमा होकर (भागतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सीमा के साथ-साथ) जाती है।
छ-ज	रेखा ग्राम खरीडाह की दक्षिणी और पूर्वी सीमा से होकर (भागतः उत्तर प्रदेश रेखा ग्राम चूरीडाह की दक्षिणी और पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है)।
ज-झ	रेखा ग्राम चूरीडाह के प्लाट संख्या 12, 11 10, 9 और 17 से होकर जाती है।
झ-क	रेखा ग्राम करवारी और अगरडा की सम्मिलित सीमा और ग्राम मोली और चटका की भागतः सम्मिलित सीमा से होकर जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं० 19(33)/80-सी०एल०]

New Delhi, the 23rd December, 1980

S.O. 101.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal) No. S.O. 627 dated the 15th March, 1980 under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid and, after consulting the Government of Madhya Pradesh, is satisfied that the lands measuring 5900.00 acres (approximately) or 2387.61 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 5900.00 acres (approximately) or 2387.61 hectares (approximately) described in the said Schedule are hereby acquired.

2. The plans of the area covered by his notification may be inspected in the Office of the Collector, Sidhi, (Madhya Pradesh) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, or in the Office of Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar)

SCHEDULE

Dudhichua Block-I

Singrauli Coalfields

District—Sidhi

Madhya Pradesh

[Drg. No. REV/78/79)]
Dated 26-10-79
(Showing lands acquired)

ALL RIGHTS

Sl. No	Village	Tahsil	Tahsil Number	Pargana	District	Area	Remarks
1.	Karwari	Singrauli	50	Singrauli	Sidhi	-	Full
2.	Churidah	,,	179	,,	,,	—	Part
3.	Dudhichuwa	,,	249	,,	,,	—	Full
4.	Madhauli	,,	446	,,	,,	—	Part

Total area : 5900.00 acres (approximately)
or : 2387.61 hectares (approximately)

Plot numbers acquired in village Karwari :

1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8, to 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 19/1, 20, 20/1, 21, 22, 23, 14/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 25/1, 25/2, 25/3, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28 to 32.

Plot number acquired in village Churidah :

9(Part), 10(Part), 11(Part), 12(Part), 13 to 16, 17(Part), 18 to 45.

Plot numbers acquired in village Dudhichuwa :

1 to 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16 to 25, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 72/4, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 34 to 37, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 39/2, 40 to 44, 47/2, 47/3, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 46/1, 46/2, 46/3, 47/1, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 58 to 96, 96/1, 96/2, 96/3, 97 to 146, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 149, 150/1, 150/2, 150/3, 151, 152/1, 152/2, 152/3, 153 to 157, 158/1, 158/2, 159 to 202.

Plot numbers acquired in village Madhauli :

513 (Part), 514 (Part), 515, 516, 516 516/1, 517 to 521, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 522 (Part), 525(Part), 525/1, 526 (Part), 527, 533 (Part), 534, 535, 536, 537(Part), 538(Part), 539 (Part), 540 (Part), 592 (Part), 594 (Part), 595 (Part).

Boundary description :

A—B	line passes through plot numbers 514, 513, 522, 525 and 526 of village Madhauli which forms common boundary of the area acquired under section 17(1) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957.
B—C	line passes alongwith the part common boundary of villages Madhauli and Dudhichua which forms common boundary of the area acquired under section 17(1)of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957.
C—D	line passes through plot numbers 533 and 540 of village Madhauli which forms common boundary of the area acquired under section 17(1) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957.
D—E E/1	lines pass through plot numbers 540, 539, 538, 537, 592, 595 and 594 of village Madhauli and along part common boundary of villages Dudhichua and Sarsobrajatola which forms common boundary of the area acquired under section 9(1) of the Coal Act for Jayant Block.
E/1—F	line passes along the part common boundary of villages Dudhichua and Sarsobrajatola.
F—G	line passes along the southern and part eastern boundary of village Dudhichua (along part common State boundary of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh).
G—H	line passes along with southern and eastern boundary of village Churidah (along part common State boundary of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh).
H—I	line passes through plot numbers 12, 11, 10, 9 & 17 of village Churidah.
I—A	line passes along the common boundary of villages Karwari and Jhingurda and part common boundary of villages Madhauli and Chatka and meets at starting point 'A'.

[No.19(33)/80—C.L.]

का०आ० 102.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 3554, तारीख 20 नवम्बर, 1978 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्रों की लगभग 4935.00 एकड़ या लगभग 1957.10 हेक्टेयर भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमियों के (लगभग) 4095.00 एकड़ या (लगभग) 1657.16 हेक्टेयर भूमि में कोयला अभिप्राप्य है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उससे संलग्न अनुसूची में वर्णित (लगभग) 4095.00 एकड़ या (लगभग) 1657.16 हेक्टेयर भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देता है।

टिप्पण- 1 इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण कलक्टर, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के कार्यालय या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस राँची (बिहार) के कार्यालय या कोयला नियंत्रक 1, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण- 2 : कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबन्धित है। अर्जन की धारित आपत्तियां :

8. (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई है, करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।

टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक 1, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

कातारी खण्ड

(सिंगरौली कोयला क्षेत्र)

जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)

रेखांकन सं० राजस्व/23/80 तारीख 10-4-80

सभी अधिकार (जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है)

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	परगना	परगना सं०	थाना	जिला क्षेत्र	टिप्पण
1.	काकरी	दुद्धी	सिंगरौली	77	मिश्र (ब्रेरवा)	मिर्जापुर	भाग
2	परासी	,,	,,	,,	,,	,,	भाग
3	रेहटा	,,	,,	,,	,,	,,	पूर्ण
4.	बासी	,,	,,	8	,,	,,	भाग
5.	पंथसागर	,,	,,	8	,,	,,	भाग

कुल क्षेत्र : 1945.00 एकड़ (लगभग)
या 787.10 हेक्टेयर (लगभग)

ग्राम काकरी में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या :

"क" 3(भाग), 4(भाग), 14(भाग), 21(भाग), 22 से 30, 31(भाग), 35(भाग), 36, 37(भाग), 39 से 367, 368(भाग), 382(भाग), 383(भाग), 384(भाग), 385 से 391, 392(भाग), 393(भाग), 394 से 415, 416(भाग), 417, 418, 419, 420, 421(भाग), 436(भाग), 484(भाग), 485(भाग), 486 से 493, 494(भाग), 498, 499(भाग), 500 से 1097, 1098(भाग), 1099(भाग), 1125(भाग), 1129 से 1147, 1148(भाग), 1149(भाग), 1150(भाग), 1151(भाग), 1153(भाग), 1154(भाग), 1155 से 1182, 1183(भाग), 1184 से 1303, 1309, 1310, 1311, 1312।

ग्राम परासी में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या :

"ख" 47(भाग), 89(भाग), 90(भाग), 91(भाग), 92 से 147, 148(भाग), 272(भाग), 273 से 276, 277(भाग), 279(भाग), 280 (भाग), 285(भाग), 286(भाग), 287(भाग), 288(भाग), 289 से 329, 330(भाग), 331(भाग), 332 से 406, 407(भाग), 408 से 418, 419(भाग), 420 से 484, 485(भाग), 486(भाग), 487(भाग), 496(भाग), 3542(भाग), 3543, 3544(भाग), 3545, 3546, 3547(भाग), 3548, 3549(भाग), 3550(भाग), 3551 से 3556, 3557(भाग), 3558(भाग), 3559(भाग), 3594, 3595 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606।

ग्राम रेहटा में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या :
1 से 553 तक।

ग्राम बांसी में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या।

"ग" 1 से 21, 22(भाग), 23(भाग), 24 से 33, 34(भाग), 35(भाग), 37(भाग), 38(भाग), 51, 52(भाग), 53(भाग), 54(भाग), 55(भाग), 58(भाग), 59 से 77, 78(भाग), 79(भाग), 80(भाग), 81 से 97, 98(भाग), 99(भाग), 100 से 179, 185(भाग), 187 से 326, 329(भाग), और 339(भाग)।

पंथसागर में अर्जित की जाने वाली भूमि
पंथसागर (भाग)

सीमा विवरण :

क—ख : रेखा ग्राम काकरी में प्लाट संख्या 3 से होकर जाती है।

ख—ग : रेखा काकरी ग्राम की पश्चिमी सीमा के एक भाग (जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सामान्य सीमा का एक भाग है) से होकर जाती है।

ग—घ : रेखा ग्राम काकरी में प्लाट संख्या 3 से होकर, फिर प्लाट सं० 10 और 339, 10 और 22 की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ प्लाट सं० 339 से होकर, फिर प्लाट सं० 339 और 51 की सम्मिलित सीमा के साथ प्लाट सं० 22, 23, 34, 35, 37, 38, 339 से होकर, प्लाट सं० 339 और 54 की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ प्लाट सं० 52 और 53 से होकर, प्लाट सं० 58 और 78, 339 और 78 की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ प्लाट सं० 54, 55, 58 में से, प्लाट सं० 98 और 99, 100 और 99 की सम्मिलित सीमा

के भाग के साथ प्लाट सं० 339, 78, 79, 80, 98 में होकर, प्लाट सं० 128 और 339, 129 और 339, 132 और 339, 133 और 339, 179 और 339, 179 और 180, 202 से 180, 197 से 180, 196 से 180 की सम्मिलित सीमा के साथ प्लाट सं० 99 और 339 में से प्लाट सं० 182 की उत्तरी सीमा के साथ प्लाट सं० 185 की उत्तरी सीमा के भाग के साथ, प्लाट सं० 187 और 186 की सम्मिलित सीमा के साथ प्लाट सं० 185 में होकर, ग्राम बामी के प्लाट सं० 328 की उत्तरी सीमा के साथ सड़क प्लाट सं० 329 से होकर जाती है।

च—ङ रेखा प्लाट संख्या 327 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ पथसागर क्षेत्र से होकर जाती है।

ङ—च रेखा ग्राम रेहटा और पथसागर की भागत सम्मिलित सीमा से होकर जाती है।

च—छ रेखा पथ सागर से होकर गुजरती है।

छ—ज—झ—ञ रेखा ग्राम रेहटा और पथसागर की भागत सम्मिलित सीमा और पथसागर से होकर जाती है।

ञ—ट रेखा पथसागर और ग्राम परासी के प्लाट सं० 3547, 3549, 3550, 3557, 3558 और 3559 से होकर जाती है।

ट—ठ—ड रेखा ग्राम परासी में प्लाट सं० 2950 की भागत दक्षिणी और भागत पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है।

ड—क रेखा ग्राम परासी में प्लाट सं० 3542, 3541, 485, 486, 187, 419, 496, 407, 331, 330, 285, 286, 287, 288, 280, 279, 277, 272, 148, 90, 91, 89 और 47 से होकर फिर प्लाट सं० 1183 से होकर, फिर प्लाट सं० 1128 की भागत दक्षिणी सीमा और प्लाट सं० 1132 की भागत उत्तरी सीमा से होकर फिर ग्राम काकरी में प्लाट सं० 1125, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1098, 1099, 199, 194, 484, 485, 416, 426, 421, 393, 392, 381, 383, 382, 368, 14, 37, 35, 31, 21, 1 और 3 से होकर जाता है और प्रारम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

अनुसूची

मराक खण्ड

(सिंगरौली कोयला क्षेत्र)

जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)

रेखांकन सं० राज०/24/80 दिनांक 2-5-1980
(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	परगना	परगना संख्या	थाना	जिला	क्षेत्र	टिप्पणी
1	भैरवा	दुद्धी	सिंगरौली	-	मिश्रा (खरवा)	मिर्जापुर	-	भाग
2	मिश्रा	"	"	101	"		-	भाग
3.	काहरोलिया	"		55		"	-	भाग
4	काहराल			54			-	भाग
5	जार्गी चौरा			46			-	भाग
6	मराक	"		91	"		-	पूर्ण
7	परसबार राजा			--			-	भाग
8	खादिया	"	"	115	"	"	-	भाग
9	खिलकन्दर	"	"	49		"	-	भाग

कुल क्षेत्र 2150 00 एकड़ (लगभग)
या 870 09 हेक्टेयर (लगभग)

कुल क्षेत्र 2150 00 एकड़ (लगभग)
या 870 06 हेक्टेयर (लगभग)

ग्राम भैरवा में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की सं० 17 (भाग), 18 से 259 तक।

ग्राम मिश्रा में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की सं० 55 (भाग) 59 से 296 तक।

ग्राम काहरोलिया में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 5 (भाग) 6 (भाग) 7 से 180 तक।

ग्राम काहराल में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 1 (भाग) [illegible] से 1[illegible] तक।

ग्राम जार्गी चौरा में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 1 (भाग) [illegible] से 115 तक।

ग्राम मराक में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या :

1 से 308 तक ।

ग्राम परसवार राजा में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या :

1(भा), 2 से 189 तक ।

ग्राम खादिया में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या :

"च" 244(भाग), 246(भाग), 247(भाग), 248 से 262, 263(भाग), 264, 265, 266, 267(भाग), 268(भाग), 382(भाग), 383 (भाग), 389(भाग), 390, 391, 392(भाग), 393(भाग), 394(भाग), 395(भाग), 396(भाग), 397 से 413, 414(भाग), 415(भाग), 416 से 608, 609(भाग), 610 से 618, 620(भाग), 621, 622, 623, 624(भाग), 625, 626(भाग), 627(भाग), 628(भाग), 635(भाग), 648(भाग), 649(भाग), 705(भाग), 706 से 711, 712(भाग), 713(भाग), 714(भाग), 715 से 734, 735(भाग), 736(भाग), 737(भाग), 738 से 999, 1000(भाग), 1001 से 1009, 1010(भाग), 1011(भाग), 1012 से 1127, 1128(भाग), 1129 से 1137, 1138(भाग), 1139 से 1302, 1303(भाग), 1304 से 1308, 1309(भाग), 1310, 1311(भाग), 1 13(भाग), 1314(भाग), 1315(भाग), 1317(भाग), 1318 से 1723, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732(भाग), 1734 ।

ग्राम चिलकन्दर में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या :

944(भाग), 1801(भाग), 1802(भाग), 1806(भाग), 1842(भाग), 1847(भाग), 1848(भाग), 1849 से 1851, 1852(भाग), 1853 (भाग), 1854(भाग), 1855 से 1979, 1980(भाग), 1981(भाग), 1984(भाग), 1985(भाग), 1986, 1987, 1988(भाग), 1989(भाग), 1990(भाग), 1991, 1992, 1993(भाग), 1994 से 2019, 2020(भाग), 2025(भाग), 2026 से 2200 ।

सीमा विवरण :

क—ख : रेखा ग्राम भैरवा के प्लाट सं 19 से होकर ग्राम जोगी चोरा के प्लाट सं 1 और ग्राम परसवार राजा के प्लाट सं 1 से जाती है ।

ख—ग : रेखा ग्राम परसवार राजा के प्लाट सं० 1 से होकर, ग्राम खादिया के प्लाट सं० 1317, 1315, 1314, 1303, 1311 1313, 1309, 1138, 1128, 1011, 1010, 1011, 1000, 736, 737, 1732, 735, 714, 713, 712, 705, 609, 649, 648, 620, 624, 626, 627, 628, 6 5, 247, 246, 244, 263, 267, 268, 415, 414, 396, 395, 392, 394, 393, 392, 389, 383, 382, से होकर और फिर ग्राम खादिया के प्लाट संख्या 2025, 2020, 2022, 1801, 1802, 1806, 1847, 1842, 1847, 1993, 1990, 1989, 1988, 1984, 1985, 1980, 1981, 1854, 1853, 1852, 1847, 1848, 944 से होकर जाती है ।

ग—घ : रेखा ग्राम चिलकन्दर और कोटा की भागतः सम्मिलित सीमा से होकर जाती है ।

घ—ङ : रेखा ग्राम चिलकन्दर और परसवार चौबे की भागतः सम्मिलित सीमा से होकर जाती है ।

ङ—च : रेखा ग्राम खादिया और परसवार चौबे की भागतः सम्मिलित सीमा से होकर जाती है ।

च—छ : रेखा ग्राम खादिया और परसवार राजा की भागतः सम्मिलित सीमा से होकर जाती है ।

छ—छ/1 : रेखा पंथ सागर क्षेत्र से होकर जाती है ।

छ/1—ज : रेखा पंथ सागर सीमा के साथ पंथ सागर और ग्राम परसवार राजा की सीमा के साथ पंथ सागर ग्राम खादिया की सीमा के साथ ग्राम परसवार राजा की सम्मिलित सीमा बनाती है ।

ज—झ : रेखा पंथ सागर की सीमा के साथ पंथ सागर ग्राम भैरवा की सीमा के साथ पंथ सागर, ग्राम जोगी चोरा की सम्मिलित सीमा के साथ ग्राम मराक की सम्मिलित सीमा बनाती है ।

झ—ञ : रेखा पंथ सागर की सीमा के साथ पंथ सागर ग्राम कोहरोलिया की सीमा के साथ पंथ सागर ग्राम कोहरोल के साथ ग्राम मिश्र की सम्मिलित सीमा बनाती है ।

ञ—ट : रेखा ग्राम धारगारी और कोहरोल की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है ।

ट—ठ : रेखा ग्राम कोहरोलिया के प्लाट संख्या 6, 5, 1, [जो जोगी चोरा ब्लाक विस्तारण के लिए कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र के साथ सम्मिलित सीमा बनाते हैं], से होकर जाती है ।

ठ-ड-ढ-क : रेखा ग्राम कोहरोल में प्लाट संख्या 1 जिला मिश्र में प्लाट संख्या 58 से होकर और ग्राम भैरवा में प्लाट सं० 17 से होकर जाती है [जो जोगी चोरा ब्लाक के लिए कोयला अधिनियम की धारा 8(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है] से होकर जाती है ।

[सं० 19(6)/80-सी एल]

S.O. 102.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 3554 dated the 20th November, 1978, under sub-section (i) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 4935.00 acres (approximately) or 1997.10 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in 4095.00 acres (approximately) or 1657.16 hectares (approximately) of lands, out of the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 4095.00 acres (approximately) or 1657.16 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto;

Note 1.—The plan of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Collector, Mirzapur, (Uttar Pradesh), or at the Office of the Central Coalfields Ltd. (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta

Note 2.—Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, (20 of 1957), which provides as follows :—

8. Objection to acquisition.—"(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation :—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parts cales of such land of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note 3.—The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE

Kakari Block

(Singrauli Coalfield)

District—Mirzapur

Uttar Pradesh

Drg. No. Rev/23/80
Dated 30-4-80

(Showing lands to be acquired)

All rights

Sl. No.	Village	Tahsil	Pargana	Pargana number	Thana	District	Area	Remarks
1.	Kakari	Dudhi	Singrauli	77	Misra (Khairwa)	Mirzapur	—	Part
2.	Parasi	,,	,,	—	,,	,,	—	Part
3.	Rehata	,,	,,	—	,,	,,	—	Full
4.	Banshi	,,	,,	8	,,	,,	—	Part
5.	Panth Sagar	,,	,,	—	,,	,,	—	Part

Total area :—1945.00 Acres (Approximately)
or :—787.10 Hectares (Approximately)

Plot numbers to be acquired in village Kakari :—

3(Part,), 4(Part), 14(Part), 21(Part), 22 to 30, 31(Part), 35(Part), 36, 37(Part), 38 to 367, 368 (Part), 382 (Part), 383 (Part), 384(Part), 385 to 391, 392(Part), 393(Part), 394 to 415, 416 (Part), 417, 418, 419, 420, 421(Part), 426 (Part), 484 (Part), 485 (Part), 486 to 493, 494, (Part), 498, 499(Part), 500 to 1097, 1098 (Part), 1099 (Part), 1125 (Part), 1129 to 1147, 1148(Part), 1149 (Part), 1150 (Part), 1151 (Part) 1153(Part), 1154 (Part), 1155 to 1182, 1183(Part), 1184 to 1308, 1309, 1310, 1311, 1312.

Plot numbers to be acquired in village Parasi:— 47(Part), 89 (Part), 90(Part), 91(Part), 92 to 147, 148 (Part), 272 (Part), 273 to 276, 277 (Part), 279 (Part), 280 (Part), 285 (Part), 286 (Part), 287 (Part), 288 (Part), 289 to 329, 330 (Part), 331 (Part), 332 to 406, 407 (Part), 408 to 418, 419 (Part), 420 to 484, 485 (Part), 486 (Part), 487 (Part), 496 (Part), 3542 (Part), 3543, 3544 (Part), 3545, 3546, 3547 (Part), 3548, 3549 (Part), 3550 (Part), 3551 to 3556, 3557 (Part), 3558 (Part), 3559 (Part), 3593, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606.

Plot numbers to be acquired in village Rehata :—1 to 553.

Plot numbers to be acquired in village Banshi :—1 to 21, 22(Part), 23 (Part), 24 to 33, 34 (Part), 35 (Part), 37 (Part), 38 (Part), 39 to 51, 52 (Part), 53 (Part), 54 (Part), 55 (Part), 58 (Part), 59 to 77, 78 (Part), 79 (Part), 80 (Part), 81 to 97, 98 (Part), 99 (Part), 100 to 179, 185 (Part), 187 to 326, 329 (Part), and 339 (Part).

Land to be acquired in Panth Sagar:—Panth Sagar (Part).

Boundary description

A—B	line passes through plot numbers 3 in village Kakari.
B—C	line passes along the part western boundary of village Kakari (which forms part common boundary with Uttar Pradesh and Madhya Pradesh).
C—D	line passes through plot number 3 in village Kakari then through plot number 339 along part common boundary of plot numbers 10 & 339, 10 & 22 then through plot numbers 22, 23, 34, 35, 37, 38, 339 along common boundary of plot numbers 339 & 51 through plot numbers 52, 53, along part common boundary of plot numbers 339 & 54 through plot numbers 54, 55, 58 along part common boundary of plot numbers 58 & 78, 339 & 78 through plot numbers 39, 78, 79, 80 98 along part common

	boundary of plot number 98 & 99, 100 & 99 through plot numbersf 99 & 339 along common boundary of plot numbers 128 & 339, 129 & 339, 132 & 339, 133 & 339, 179 & 339, 179 & 180, 202, 180, 197, & 180, 196 & 180 along Northern boundary of plot number 182 along part northern boundary of plot number 185, through plot number 185 along common boundary of plot numbers 187 & 186 through Road plot number 329 along northern boundary of plot number 328 of village Banshi.
D—E	line passes along the western boundary of plot number 327 and through Panth Sagar area
E—F	line passes along the part common boundary of villages Rehat and Panth Sagar.
F—G	line passes through Panth Sagar.
G—H—I—J	line passes along the part common boundary of villages Rehata and Panth Sagar and through Panth Sagar.
J—K	line passes through Panth Sagar and through plot numbers 3547, 3549, 3550, 3557, 3558, and 3559 in village Parasi.
K—L—M	lines pass along the part southern and part eastern boundary of plot number 2950 in village Parasi.
M - A	line passes through plot numbers 3542, 3544, 485, 486, 487, 419, 496, 407, 331, 330, 285, 286, 287, 288, 280, 279, 277, 272, 148, 90, 91, 89 and 47 in village Parasi, then through plot number 1183 then along the part southern boundary of plot number 1128 and part northern boundary of plot number 1132 then through plot numbers 1125, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1098, 1099, 499, 494, 484, 485, 416, 426, 421, 393, 392, 384, 383, 382, 368, 14, 37, 35, 31, 21, 4 and 3 in village Kakari and meets at starting point A.

SCHEDULE
Marrak Block
(Singrauli Coalfield)
District—Mirzapur
Uttar Pradesh

Drg. No. Rev/24/80
Dated 2-5-80
(Showing lands to be acquired)

All rights

Serial number	Village	Tahsil	Pargana	Pargana number	Thana	District	Area	Remarks
1.	Bhairwa	Dudhi	Singrauli	—	Misra (Khairwa)	Mirzapur	—	Part
2.	Mishra	,,	,,	101	,,	,,	—	,,
3.	Kaharoulia	,,	,,	85	,,	,,	—	,,
4.	Kaharoul	,,	,,	84	,,	,,	—	,,
5.	Jogichoura	,,	,,	46	,,	,,	—	,,
6.	Marrak	,,	,,	91	,,	,,	—	Full
7.	Paraswar Raja	,,	,,	—	,,	,,	—	Part
8.	KHADIA	,,	,,	115	,,	,,	—	,,
9.	Chilkadanr	,,	,,	49	,,	,,	—	,,

Total area :—2150.00 acres (approximately)
or :—870.06 heactares (approximately)
Plot numbers to be acquired in village Bhairwa :—17 (Part),18 to259.

Plot numbers to be acquired in village Mishra :—58(Part), 59 to 296

Plot numbers to be acquired in village Kaharoulia :—1(Part), 5 (Part), 6 (Part), 7 to 180
Plot numbers to be acquired in village Kahraul :—1(Part), 2 to 194
Plot numbers to be acquired in villag e Jogichoura :—(1Part), 2 to 165
Plot numbers to be acquired in village Marrak :—1 to 308
Plot numbers to be acquired in village Paraswar Raja :—1 (Part), 2 to 189

Plot numbers to be acquired in village Khadia :—244(Part), 246 (Part), 247 (Part), 248 to 262, 263 (Part), 264, 265, 266, 267, (Part) 268 (Part), 382 (Part), 383 (Part), 389 (Part), 390, 391 392, (Part), 393 (Part), 394 (Part),395)(Part), 396 (Part), 397 to 413, 414 (Part) 415 (Part) 416 to 608, 609 (Part), 610 to 618, 620 (Part), 621, 622, 623, 624 (Part), 625, 626 (Part), 627 (Part), 628 (Part), 635 (Part), 648 Part), 649 (Part) 705 (Part), 706 to 711, 712 (Part), 713 (Part), 714 (Part), 715 to 734, 735 (Part), 736 (Part), 737 (Part), 738 to 999, 1000 (Part), 1001 to 1009) 1010 (Part), 1011 (Part) 1012 to 1127, 1128 (Part), 1129 to 1137, 1138 (Part), 1139 to 1302, 1303 (Part), 1304 to 1308, 1309 (Part) 1310, 1311 (Part), 1313 (Part) 1314 (Part), 1315 (Part), 1317 (Part), 1318 to 1723, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732 (Part), 1734

Plot numbers to be acquired in villag e Chilkadanr :—944 (Part), 1801 (Part), 1802 (Part), 1805 (Part), 1842 (Part), 1847 (Part), 1848 (Part), 1849 to 1851, 1852 (Part), 1853 (Part) 1854)(Part), 1855 to 1979, 1980 (Part), 1981 (Part), 1984 (Part), 1985 (Part), 1986, 1987 1988 (Part), 1989 (Part), 1990 (Part), 1991, 1992, 1993 (Part), 1994 to 2019, 2020 (Part), 2025 (Part), 2026 to 2230.

Boundary description :

A-B	line passes through plot numbers 19 in village Bhairwa along plot western boundary and, through plot number 1 of village Jogichowra through plot number 1, of village Paraswar Raja.
B-C	line passes through plot number 1 of village Paraswar Raja through plot numbers 1317, 1315, 1314, 1303, 1311, 1313, 1309, 1138, 1128, 1011, 1010, 1011, 1000, 736, 737, 1732, 735, 714, 713, 712, 705, 609, 649, 648, 620, 624, 626, 627, 628, 635, 247, 246, 244, 263, 267, 268, 415, 414, 396, 395, 392, 394, 393, 392, 389, 383, 382, in village Khadia, through plot numbers

	2025, 2020, 2022, 1801, 1802, 1806, 1847, 1842, 1847, 1993 1990, 1989, 1988, 1984, 1935, 1930, 1981, 1854,1853, 1852, 1847, 1848, 944 in village Chilkadanr.
C-D	line passes along the part common boundary of villages Chilkadanr and Kota
D-E	line passes along the common boundary of villages Chilkadanr and Paraswar Choube
E-F	line passes along the common boundary of villages Khadia and Paraswar Choube.
F-G	line passes along the part common boundary of villages Khadia and Paraswar Raja.
G-G/1	line passes through Panth Sagar area.
G/1-H	line forms common boundary of villages Paraswar Raja with the boundary of Panth Sagar village Khadia with the boundary of Panth Sagar and village Paraswar Raja with the boundary Panth Sagar.
H-I	line forms common boundary of village Marrak with the boundary of Panth Sagar, villages Jogichoura with the boundary Panth Sagar village Bhairwa with the boundary of Panth Sagar.
I-J	line forms common boundary of village Mishra with the boundary of Panth Sagar, village Koharoul with the boundary of Panth Sagar village Kahroulia with the boundary of Panth Sagar.
J-K	line passes along the part common boundary of village Dharsari & Kaharoul.
K-L	line passes through plot numbers 6, 5, 1, of village Kaharoulia which forms common boundary with the area acquired under Section (1) of the Coal Act for Jogichoura Block Extension.
L-M-N-A	lines pass through plot number 1 in village Kaharoul through plot number 58 in village Mishra, and through Plot number 17 village Bhairwa which forms common boundary with the area acquired u/s 9(1) of the coal act for Jogichoura Block.

[No. 19(6)/80-CL]

का०आ० 103.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957(1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के इस्पात, खान और कोयला ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 543, तारीख 8 मार्च, 1980 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 320 00 एकड़ (लगभग) या 129. 50 हेक्टर (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राय है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 320 एकड़ (लगभग) या 129 50 हेक्टर (लगभग) माप वाली भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है।

टिप्पण —1 इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण जिला मजिस्ट्रेट ढेनकानाल (उड़ीसा) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 के कार्यालय में अथवा सेन्ट्रल कोल फील्डस लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), दरभंगा हाउस रांची-834001, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण —2 कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबन्धों की ओर इसके द्वारा ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबन्ध किया गया है, अर्थात् :—

"8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी, और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों को सुनने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के सम्बन्ध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशें और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।"

टिप्पण :—3. केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-1 को अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

अनुसूची

दक्षिणी बालन्दा विस्तार

तलचर कोयला क्षेत्र

जिला ढेनकानाल (उड़ीसा)

रेखांकन सं० ख०/36/80

दिनांक : 24-5-80

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार

क्र०सं०	ग्राम	थाना	उपखण्ड	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	घण्टापारा	कोयलाखान	तलचर	—	ढेनकानाल	—	नीचे वर्णित प्लाट संख्यांक

कुल क्षेत्र : 320.00 एकड़ (लगभग)

या

129.50 हेक्टर (लगभग)

ग्राम घंटापारा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक

1(भाग), 2(भाग), 3 से 13, 14(भाग), 27 सड़क(भाग) 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 6890, 6902, 6907(भाग), 7005(भाग), 7344 और 7345 ।

सीमावर्णन :

क--ख : रेखा बालन्दा और घंटापारा, हीरापुर और घंटापारा ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है ।

ख-ग-घ-ङ-च : रेखाएं घंटापारा ग्राम के प्लाट सं० 39 की आंशिक पश्चिमी और दक्षिणी सीमा, प्लाट सं० 36, 34 और 33 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है ।

च--छ : रेखा घंटापारा ग्राम के प्लाट सं० 33, 14 और 6907 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ तथा सड़क (प्लाट सं० 27) में से होकर जाती है ।

छ--ज : रेखा घंटापारा ग्राम के प्लाट सं० 6907 और 14 में से होकर जाती है [जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित दक्षिणी बालन्दा की सीमा के साथ सामान्य सीमा बनती है]

ज--झ : रेखा घंटापारा और डेरा ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है [जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अधिसूचित दक्षिणी बालन्दा की सामान्य सीमा बनती है]

झ--क : रेखा घंटापारा ग्राम के प्लाट सं० 1, 2 और 7005 में से होकर जाती है [जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अधिसूचित दक्षिणी बालन्दा की सामान्य सीमा बनती है ।]

[सं० 19(50)/80 सी एल०]

S.O. 103.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Steel, Mines and Coal, (Department of Coal) No. S.O. 543 dated the 8th March, 1980 under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 320.00 acres (approximately) or 129.50 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification.

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the said lands measuring 320.00 acres (approximately) or 129.50 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto;

Note 1.—The plan of the area covered by this notification may be inspected in the office of the District Magistrate, Dhenkanal (Orissa) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-700001 or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi-834001, Bihar.

Note 2.—Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, (20 of 1957), which provides as follows :—

"8(1) Any person interested in ny land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation:—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendation on the objections together with the record of the proceedings held by him for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note 3.—The Coal Controller, I, Council House Street, Calcutta-1 has been apointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE

South Balanda Extn.

Talcher Coalfield

District- Dhenkanal (Orissa)

Drg. No. Rev /36/80
Dated : 24-5-80

(Showing lands to be acquired)

All rights

Serial number	Village	Police Station	Sub-Division	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Ghantapara	Colliery	Talcher	—	Dhenkanal	—	Plot numbers described below.

Total area :—320.00 acres (approximately)
or 129 50 hectares (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Ghantapara :—

1 (Part), 2 (Part), 3 to 13, 14 (Part), 27 Road (Part) 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 6890, 6902, 6907 (Part), 7005 (Part), 7344 & 7345

Boundary description :—

A-B	line passes along the part common boundary of villages Balanda and Ghantapara, Hirapur and Ghantapara.
B-C-D-E-F	lines pass along the part western and southern boundary of plot number 39, southern boundary of plot numbers 36, 34 & 33 of village Ghantapara
F-G	line passes along the Eastern boundary of plot numbers 33, 14 and 6907 and through Road (plot number 27) of village Ghantapara.
G-H	line passes through plot numbers 6907 and 14 of village Ghantapara [which forms common boundary with the boundary of south Balanda acquired U/s. 9 (1) of the Coal Act].
H-I	line passes along the part common boundary of villages Ghantapara & Dera [which forms common boundary of South Balanda notified under section 9(1) of the Coal Act].
I-A	line passes through plot numbers 1, 2 and 7005 of village Ghantapara [which forms common boundary of South Balanda notified under section 9 (1) o the Coal Act].

[No. 19(50)/80-CL]

का० आ० 104.—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस बाबत इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 1 सितम्बर, 1979 के पृष्ठ 2427 से 2432 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2960, तारीख 17 अगस्त, 1979, को विखण्डित करती है।

[सं० 19(6)/80-सी एल]

S.O. 104.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and of all other power enabling it in this behalf, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in Ministry of Energy, (Department of Coal) No. S.O. 2960 dated the 17th August, 1979, published at pages 2427 to 2432 in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 1st September, 1979.

[No. 19(6)/80-CL]

का० आ० 105.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ,

2. इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण सेन्ट्रल कोलफिल्डस लिमिटेड का कार्यालय, राजस्व अनुभाग, दरभंगा हाउस, रांची में या उपायुक्त का कार्यालय हजारीबाग (बिहार) में अथवा कोयला नियंत्रक का कार्यालय 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी, सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची को भेजेंगे

माडू ब्लाक

उपब्लाक I और उप ब्लाक II

पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र

जिला-हजारी बाग, बिहार

रेखांकन संख्या खे/55/80
तारीख 2-8-80
(पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शित करते हुए)

उपब्लाक I

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला क्षेत्र	टिप्पणियां
1	माडू	मांडू	114	हजारी बाग	भाग
2	काकेबसौड़ा	मांडू	115	हजारी बाग	भाग
3	कासीखान	मांडू	123	हजारी बाग	भाग
4	कोरबंडा	मांडू	124	हजारी बाग	भाग
5	टोपा	मांडू	126	हजारी बाग	भाग
6	बनवार	मांडू	127	हजारी बाग	भाग
		कुल क्षेत्र	1960.00 एकड़ (लगभग) या 793.17 हेक्टर (लगभग)		

सीमावर्णन :

क--ख-- रेखा ग्राम मांडू में से होकर जाती है ।

ख--ग-- रेखा ग्राम सेमरा की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है।

ग--घ-- रेखा--सेमरा और कारेबंडा ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है।

घ--ङ-- रेखा कारेबंडा, कासीखाप और टोपा ग्रामों में से होकर जाती है।

ङ--च-- रेखा बनवार ग्राम में से होकर जाती है ।

च--छ-- रेखा बनवार और कासीखाप ग्रामों में से होकर जाती है (जो कुजु कोयला खान के साथ आंशिक सामान्य सीमा बनती है) ।

छ--ज-- रेखा, कासीखाप और हेसागोरा ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है। (जो हेसागोरा कोयला खान के साथ आंशिक सामान्य सीमा बनती है))।

ज--झ-- रेखा हेसागोरा और मांडू ग्रामो की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है (जो हेसागोरा कोयला खान के साथ आंशिक सामान्य सीमा बनती है)

झ--ञ-- रेखा मांडू और काकेबसौडी ग्रामो में से होकर जाती है [जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित पुण्डी ब्लाक के साथ सामान्य सीमा बनती है] ।

ञ--क-- रेखा काकेबसौडी और मांडू ग्रामो में से होकर जाती है और आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है ।

उप ब्लाक II

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला क्षेत्र	टिप्पणीयां
1	कुजु	मांडू	154	हजारीबाग	भाग
2	पोखरिया	माडू	121	हजारीबाग	भाग
			कुल क्षेत्र--	95.00 एकड़ (लगभग) या 38.44 हेक्टर (लगभग)	

सीमावर्णन :

ड--ढ-- रेखा ग्राम कुजु में से होकर जाती है (जो कुजु कोयला खान के साथ सामान्यतः सीमा बनती है)

ढ--ण--त-- रेखा कुजु और पोखरिया ग्रामों में से होकर जाती है (जो सूरवा कोयला खान के साथ आंशिक सामान्य सीमा बनती है)

त--थ-- रेखा आरा और पोखरियां ग्रामो की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है ।

थ--द-- रेखा, नदी की मध्य रेखा के साथ-साथ जाती है (जो पोखरिया और बोंगहारा ग्रामो की सामान्य सीमा बनाती है) ।

द--ड-- रेखा नदी की आंशिक मध्य रेखा के साथ जाती है (जो कुजु और हेसागारा ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा बनाती है) और हेसागारा कोयला खान सीमा के साथ-साथ जाती है और आरंभिक बिन्दु 'ड' पर मिलती है ।

[सं० 19(54)/80-सी०एस]
स्वर्ण सिंह, अवर सचिव

S.O. 105.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the schedule hereto annexed ,

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein ,

2 The plan of the area covered by this notification can be inspected in the office of the Central Coal fields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi, or in the Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar), or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coal Fields Limited, Darbhanga House, Ranchi, within 90 days from the date of publication of this notification

SCHEDULE

Mandu Block

Sub-block-I and Sub-block-II

West Bokaro Coalfield

Distt Hazaribagh

Bihar

Sub-Block-I

Drg No Rev/55/80
dated 2-8-80
(Showing lands notified for prospecting)

Serial number	Village	Thana	Thana No	District	Area	Remarks
1	Mandu	Mandu	114	Hazaribagh	—	Part
2	Kekebasaudi	-do-	115	-do-	—	,,
3.	Kasikhap	-do-	123	-do-	—	,,
4	Karebanda	-do-	124	-do-	—	,,
5	Topa	-do-	126	-do-	—	,,
6	Banwar	-do-	127	-do-	—	,,
			Total area	1960 00 acres (approx)		
			or	793 17 hec (approx)		

Boundary description —

A-B	line passes through village Mandu
B-C	line passes along the part eastern boundary of village Semra
C-D	line passes along the part common boundary of villages Semra & Karebandi
D-E	line passes through villages Karebanda, Kasikhap & Topa
E-F	line passes through village Banwar
F-G	line passes through villages Banwar & Kasikhap (which forms part common boundary with Kuju Colliery)
G-H	line passes along the part common boundary of villages Kasikhap & Hesagora which forms part common boundary with Hesagora colliery)
H-I	line passes along the part common boundary of villages Hesagora & Mandu which forms part common boundary with Hesagora Colliery.
I-J-K	lines pass through villages Mandu and Kekebasandi [which forms common boundary with Pundi Block acquired u/s 9(1) of the Coal Act]
K-A	line passes through villages Kekebasandi and Mandu and meets at starting point 'A'

Sub-Block-II

Serial No.	Village	Thana	Thana No	District	Area	Remarks
1.	Kuju		Mandu	154	Hazaribagh	Part
2	Pokharia		-do-	121	-do-	,,
			Total area	95 00 acres (approx)		
			or	38 44 hec (approx)		

Boundary description —

M-N	line passes through village Kuju (which forms common boundary with Kuju Colliery)
N-O-P	lines pass through villages Kuju & Pokharia (which forms part common boundary with Murpa Colliery)
P-Q	line passes along the part common boundary of villages Ara & Pokharia
Q-R	line passes along the Central line of the River (which forms common boundary of villages Pokharia & Bongahara)
R-M	line passes along the part central line of the River (which forms part common boundary of villages Kuju & Hesagora and also along part Hesagora Colliery boundary) and meets at starting point 'M'

[No. 19 (54)/80-CL]
SWARAN SINGH, Under Secy

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1980

का० आ० 106.—जबकि, प्राप्त सूचना के आधार पर, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि गलती, भूल अथवा अपविवरण के कारण "न्यू धरमाबन्द" (जे-23) कोकर कोयला खान के स्वामी का नाम कोकर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36) की प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि सं० 36 पर कालम 4 के सामने शेठिया माइनिंग ऐंड मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड" के स्थान पर "शेठिया माइनिंग ऐंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड" दर्ज हो गया है ;

और जबकि उपर्युक्त कोकर कोयला खान का उक्त स्वामित्व विवादग्रस्त नहीं है। अतः अब, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उपर्युक्त कोकर कोयला खान के संबंध में स्वामी का नाम सही करके "शेठिया माइनिंग ऐंड मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड" करती है।

[सं० 48016/1/79-सी०ए०]

ल० ना० लद्दा, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 23rd December, 1980

S.O. 106.—Whereas, upon the information received, the Central Government is satisfied that due to error, omission or misdescription, the name of owner in relation to the Coking Coal Mine, namely "New Dharmaband (J-23)" has been entered as 'Sethia Mining and Manufacturing Company Limited' instead of 'Shethia Mining and Manufacturing Corporation Limited' in column 4 against the entry at serial No. 36, of the First Schedule to the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (36 of 1972);

And whereas the said ownership of the coking coal mines is not in dispute. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 4 of the said Act, the Central Government hereby corrects the name of the owner in relation to the said mine as 'Shethia Mining and Manufacturing Corporation Limited.'

[No. 48016/1/79-CA]

L. N. LADDHA, Jt. Secy.

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर 1980

का० आ० 107.—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 80 की उप-धारा (5) के अनुसरण में भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) की अधिसूचना का० आ० 2705, दिनांक 25 सितम्बर, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उपर्युक्त अधिसूचना में, प्रस्तावना में आए "1 अक्टूबर, 1980" अंकों और शब्दों के स्थान पर" 1 जनवरी, 1981" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फाइल संख्या 21/24/77-यी एण्ड बी/डी-III]

एन० एल० खन्ना, उप सचिव

(Department of Power)

New Delhi, the 23rd December, 1980

S.O. 107.—In pursuance of sub-section (5) of section 80 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Power) No. S.O. 2705, dated the 25th September, 1980, namely :—

In the said notification, in the preamble, for the figures and words "1st October, 1980", the figures and words "1st January, 1981" shall be substituted.

[File No. 21/24/77-B & B/D.III]

N. L. KHANNA, Dy. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1980

का० आ० 108.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली (अधिनियम, 1971 (1971) का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, तारीख 26 जनवरी, 1974 में प्रकाशित, भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 232, तारीख 21 दिसम्बर, 1973 को अधिक्रांत करते हुए, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है तथा निदेश देती है कि उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के सरकारी स्थानों की बाबत अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त, अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारियों का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
1. नगर प्रशासक, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो सिटी, जिला धनबाद (बिहार) 2. उप नगर प्रशासक, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी, जिला धनबाद (बिहार) 3. प्रबन्धक (सम्पदा) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट बोकारो स्टील सिटी जिला धनबाद (बिहार) 4. ज्येष्ठ भूमि और सम्पदा अधिकारी, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट बोकारो स्टील सिटी, जिला धनबाद (बिहार) 5 सम्पदा अधिकारी, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट बोकारो स्टील सिटी, जिला धनबाद (बिहार) 6. भूमि अधिकारी, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट बोकारो स्टील सिटी, जिला धनबाद (बिहार)	बोकारो स्टील सिटी, जिला धनबाद में स्थित स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थान ।
7. कार्मिक अधिकारी, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, मेघहतुबुरू लोह अयस्क परियोजना, डाकघर मेघहतुबुरू, जिला सिंघभूम (बिहार) 8. मुख्य इंजीनियर, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, किरिबुरू लोह अयस्क परियोजना, डाकघर किरिबुरू, जिला सिंघभूम (बिहार)	मेघहतुबुरू, जिला सिंघभूम (बिहार) में स्थित स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थान /जिला सिंघभूम (बिहार) के किरिबुरू में और जिला कोंझर (उड़ीसा) में स्थित स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थान ।

[फा० सं० 6(58)/79-एस० ए० आई० एल० (I)]

यशवंत ल० राजवाड़े, निदेशक

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 22nd December, 1980

S.O. 108—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel) S.O. No. 232 dated 21st December, 1973, published in the Gazette of India dated the 26th January, 1974, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officers equivalent to the rank of Gazetted officers of Government, to be Estate Officers for the purposes of the said Act and further directs that the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdictions, in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of officers	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1	2
1. Town Administrator, Steel Authority of India Limited Bokaro Steel Plant, Bokaro Steel City, District Dhanbad (Bihar) 2. Deputy Town Administrator, Steel Authority of India Limited, Bokaro Steel Plant, Bokaro Steel City District Dhanbad (Bihar).	Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited, situated at Bokaro Steel City in the District of Dhanbad.
3. Managing Estate Steel Authority of India Limited Bokaro Steel Plant, Bokaro Steel City, District Dhanbad (Bihar). 4 Senior Land and Estate Officer, Steel Authority of India Limited, Bokaro Steel Plant, Bokaro Steel City, District Dhanbad (Bihar) 5. Estate Officer, Steel Authority of India Limited, Boka Bokaro Steel Plant, Bokaro Steel City, District Dhanbad (Bihar). 6. Land Officer, Steel Authority of India Limited, Bokaro Steel Plant, Bokaro Steel City, District Dhanbad (Bihar).	Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited situated at Bokaro Steel city in the District Dhanbad.
7. Personnel Officer, Steel Authority of India Limited Meghahatuburu Iron Ore Project, P.O. Meghahatuburu, District Singhbhum (Bihar).	Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited, situated at Meghahatuburu, in the District of Singhbhum (Bihar).
8. Chief Engineer, Steel Authority of India Limited, Kiriburu Iron Ore, Project, P.O. Kiriburu District Singhbhum (Bihar)	Premises belonging to, and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited situated at Kiriburu in the District of Singhbhum (Bihar) and in the District of Keonjhar Orissa)

[File No. 6(58)/79-SAIL-I]
Y. L. RAJWADE, Director.

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1981

का०आ० 109.—ग्राम श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1980 का एक प्रारूप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 106, तारीख 29 दिसम्बर, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग, 2, खण्ड 3 उपखण्ड (ii), तारीख 12 जनवरी, 1980 के पृष्ठ 141-149 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी,

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 19 जनवरी, 1980 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्राम श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1981 है।

(2) ये भारत में उत्पादित ग्रामों को लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) कृषि विपणन सलाहकार से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकृत पैकर से ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति—निकाय अभिप्रेत है जिसे कृषि विपणन सलाहकार ने, नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार, वस्तु को श्रेणीकृत कराने या एगमार्क चिह्न लगवाने के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र दिया है;

(घ) "प्रमाणपत्र" से प्राधिकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ङ) "स्कन्ध" से फल की कपुनी (गर्दन) के चारों ओर का भाग अभिप्रेत है।

3. श्रेणी अभिधान . आमों की क्वालिटी उपदर्शित करने वाला श्रेणी अभिधान वह होगा जो अनुसूची 2 से 14 तक के स्तम्भ 1 में उपवर्णित है।

4. क्वालिटी की परिभाषा :—श्रेणी अभिधानों द्वारा उपदर्शित क्वालिटी वह होगी जो अनुसूची 2 से 14 तक के स्तम्भ 2 और 3 में, प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने उपवर्णित है ।

5. श्रेणी अभिधान चिन्ह :—श्रेणी अभिधान चिह्न एक ऐसा लेबल होगा जिसमें श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और ऐसी डिजाइन (जिसमें भारत का रेखाचित्र, एगमार्क शब्द और "भारतीय उत्पाद " शब्दों सहित उगते सूर्य का चित्र होगा) बनी होगी, जो अनुसूची 1 में दिए गए चिह्न के सदृश होगी।

6. चिह्नांकन-पद्धति :—(1) श्रेणी अभिधान चिह्न, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से, प्रत्येक पेटी/पैकेज पर मजबूती से चिपकाया जाएगा।

(2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां भी स्पष्टतः दी जाएंगी.

(i) किस्म का नाम;

(ii) फलों की संख्या;

(iii) शुद्ध भार;

(iv) पैक करने वाले केन्द्र का नाम;

(v) पैक करने की तारीख, और

(vi) कोई अन्य विशिष्टियां, जो कृषि विपणन सलाहकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(3) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् आधान पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न, उक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से अंकित कर सकेगा परन्तु यह तब जब कि प्राइवेट व्यापार, चिह्न, इन नियमों के अनुसार आधान पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा आमों की उपदर्शित क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न क्वालिटी या श्रेणी उपदर्शित न करें।

7. पैक करने की पद्धति :—(1) आमों को लकड़ी के ऐसे क्रेटों में या टोकरियों में अथवा किसी अन्य प्रकार के आधान में तथा ऐसी रीति में पैक किया जाएगा जो समय-समय पर कृषि विपणन सलाहकार विनिर्दिष्ट करें ;

(2) पैकिंग सामग्री स्वच्छ और शुष्क होगी, फफूंदी या कीड़े लगी नहीं होगी और दुर्गन्ध मुक्त होगी;

(3) हर एक पैकेज में एक ही किस्म के और एक ही श्रेणी अभिधान के आम होंगे और सबसे उपर की परत वाले आम आकार, परिपक्वता, रंग-रूप में पैकेज में रखे गए समस्त अन्य आमों के समान ही होंगे और स्पष्ट दोषों की दृष्टि से मुक्त होंगे।

(4) प्रत्येक पैकेज को कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विहित रूप में सुरक्षित रूप से बन्द और सील बन्द किया जाएगा।

8 प्राधिकरण प्रमाणपत्र की विशेष शर्तें—प्रत्येक पैकर, साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1937 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त कृषि विपणन सलाहकार के समाधानप्रद रूप में निम्नलिखित विशेष शर्तों का भी पालन करेगा, अर्थात :—

(1) प्राधिकृत पैकर आमों के परीक्षण के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जो कृषि विपणन सलाहकार, समय-समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारियों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो इन नियमों के अधीन उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हैं।

9. निरसन और व्यावृत्ति—(1) निम्नलिखित नियमों को निरसित किया जाता है :—

(1) अल्फांसो आम (निर्यात) श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1938

(2) अल्फांसो आम (देश में उपभोग) श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1939

(3) कंचन (बधुवा) आम (देश में उपभोग) श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1955

(4) ऐसा निरसन निरसित नियमों के अधीन सम्यकतः की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची 1
(नियम 5 देखिए)
श्रेणी अभिधान चिह्न

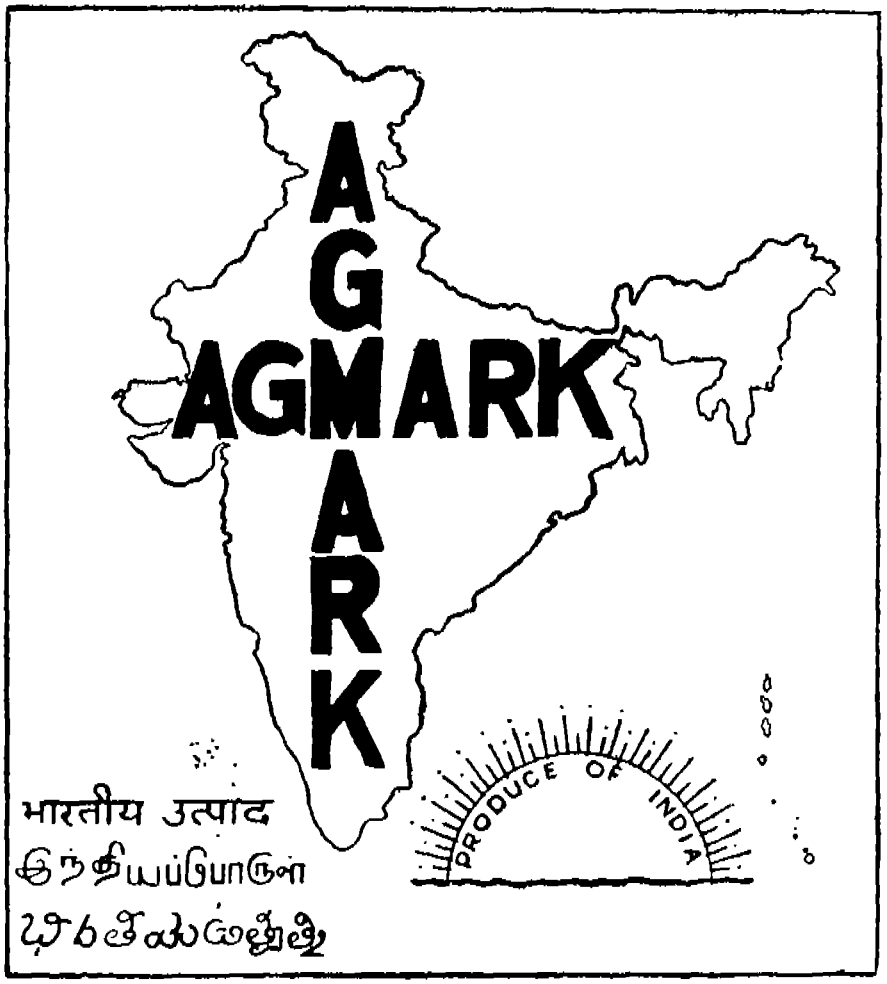

अनुसूची 2
(नियम 2, 3 और 4 देखिए)
अल्फांसो के किस्म के भारतीय आमों का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा	
	विशेष लक्षण प्रत्येक फल का न्यूनतम भार†	साधारण लक्षण
1	2	3
श्रेष्ठ	280 ग्राम	1. प्रत्येक आम :
विशेष	230 ग्राम	(क)*परिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि पश्चात् परिवहन और विपणन के मामूली अनुक्रम में वह पक सकता हो ;
अच्छा	160 ग्राम	(ख)*अपनी किस्म के लक्षण के अनुसार रंग का हो, अर्थात् पकने पर पीला लाल छिलका हो गया हो और पैक में सभी फल युक्तियुक्त रूप से समान रंग के होंगे ;
मानक	120 ग्राम	(ग)*उसी किस्म के सामान्य आकार का हो और विकृति मुक्त हो ;
		(घ) अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो और रोग, युक्तियुक्त रूप से विकसित और अच्छी दशा में हो।
		(ङ) फलों के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले रोगों, कीटाणुओं या क्षति के कारण होने वाले दोषों से मुक्त हो।
		2. हवा से गिरे हुए और कौटिल फल पैक नहीं किए जाएंगे।
		3 ‡ऐसे धब्बे अनुज्ञात होंगे जो आमों के टिकाऊपन को प्रभावित करते हों परन्तु यह तब जब कोई भी एक धब्बा 1.6 वर्ग स० मी० से बड़ा न हो।
		4. डंठल को फल के पास से हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खींच कर निकाला नहीं जाएगा।

†ऐसे फलों के, जो विनिर्दिष्ट भार सीमा से 30 ग्राम तक कम है, श्रेणीकरण की आवश्यक आकस्मिक त्रुटियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी।
*श्रेणीकरण में आकस्मिक त्रुटियों के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी।
‡धब्बों के अन्तर्गत फफूंदी के रोग, कीटाणु और नाशक जीवी अधंड़, छिड़काव आदि के कारण पड़े धब्बे भी है।

अनुसूची 3

(नियम 2, 3 और 4 देखिए)

दशहरी किस्म के भारतीय आमों का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा	
	विशेष लक्षण प्रत्येक फल का न्यूनतम भार*	साधारण लक्षण
1	2	3
श्रेष्ठ विशेष अच्छा	250 ग्राम 150 ग्राम 100 ग्राम	1. प्रत्येक आम : 55 (क) **परिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि तत्पश्चात परिवहन और विपणन के मामूली अनुक्रम में वह पक सकता हो; (ख) **अपनी किस्म के लक्षण के अनुसार रंग का हो, अर्थात पकने पर पीला/लाल छिलका हो गया हो और उसी किस्म के सामान्य आकार का हो; (ग) **अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो और ठोस, युक्तियुक्त रूप से विकसित और अच्छी दशा में हो, (घ) फलों के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतियों, रोगों, कीटाणुओं या क्षति के कारण होने वाले दोषों से मुक्त हों। 2. हवा से गिरे हुए और चोटिल फल पैक नहीं किए जाएंगे। 3. डंठल को फल के पास से हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खींच कर निकाला नहीं जाएगा। 4. †ऐसे धब्बे अनुज्ञात होंगे जो आमों के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हों परन्तु यह तब जब कि कोई भी एक धब्बा 1.6 वर्ग से०मी० से बड़ा न हो।

*ऐसे फलों के, जो विनिर्दिष्ट भार सीमा से 30 ग्राम तक कम है, श्रेणीकरण की बाबत आकस्मिक त्रुटियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

**श्रेणीकरण में आकस्मिक त्रुटियों के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

†धब्बों के अन्तर्गत, फफूंदी के रोग, कीटाणु और नाशक जीवों, अंधड़, छिड़काव आदि के कारण पड़े धब्बे भी है।

अनुसूची 4

(नियम 2, 3 और 4 देखिए)

रूमानी, नीलम, पैरी, रूमपुरी और नादुनाली किस्म के भारतीय आमों का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा	
	विशेष लक्षण प्रत्येक फल का न्यूनतम भार*	साधारण लक्षण
1	2	3
श्रेष्ठ विशेष अच्छा	235 ग्राम 175 ग्राम 115 ग्राम	1. प्रत्येक आम : (क) **परिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि तत्पश्चात परिवहन और विपणन के मामूली अनुक्रम में वह पक सकता हो, (ख) **अपनी किस्म के लक्षण के अनुसार रंग का हो और उसी किस्म के सामान्य आकार का हो ; (ग) **अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो और ठोस, युक्तियुक्त रूप से विकसित और अच्छी दशा में हो ; (घ) फलों के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतियों, रोगों, कीटाणुओं या क्षति के कारण होने वाले दोषों से मुक्त हो। 2. हवा से गिरे हुए और चोटिल फल पैक नहीं किए जाएंगे। 3. डंठल को फल के पास से हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खींच कर निकाला नहीं जाएगा। 4. †ऐसे धब्बे अनुज्ञात होंगे जो आमों के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हों, परन्तु यह तब जबकि कोई भी एक धब्बा 1.6 वर्ग सें०मी० से बड़ा न हो।

*ऐसे फलों के जो विनिर्दिष्ट भार सीमा से 30 ग्राम तक कम है, श्रेणीकरण की बाबत आकस्मिक त्रुटियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

**श्रेणीकरण में आकस्मिक त्रुटियों के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

†धब्बों के अन्तर्गत, फफूंदी के रोग, कीटाणु और नाशक जीवों, अंधड़, छिड़काव आदि के कारण पड़े धब्बे भी है।

अनुसूची 5

(नियम 2, 3 और 4 देखिए)

बंगलौरा, तोतापरी और कलेक्टर किस्म के भारतीय आमों के श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा	
	विशेष लक्षण प्रत्येक फल का न्यूनतम भार*	साधारण लक्षण
1	2	3
श्रेष्ठ	410 ग्राम	1 प्रत्येक आम :
विशेष	350 ग्राम	(क) **परिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि तत्पश्चात् परिवहन और विपणन के मामूली अनुक्रम में वह पक सकता हो ;
अच्छा	290 ग्राम	(ख) **अपने किस्म के लक्षण के अनुसार रंग का हो, और उसी किस्म के सामान्य आकार का हो ;
		(ग) **अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो और ठोस, युक्तियुक्त रूप से विकसित और अच्छी दशा में हो ,
		(घ) फलों के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतियों, रोगों, कीटाणुओं या क्षति के कारण होने वाले दोषों से मुक्त हो ।
		2. हवा से गिरे हुए और चोटिल फल पैक नहीं किए जाएंगे ।
		3. डंठल को फल के पास से हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खींच कर निकाला नहीं जाएगा
		4. †ऐसे धब्बे अनुज्ञात होंगे जो आमों के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हो परन्तु यह तब जब कि कोई भी एक धब्बा 1 6 वर्ग सें०मी० से बड़ा न हो।

*ऐसे फलों के, जो विनिर्दिष्ट भार सीमा से 30 ग्राम तक कम है, श्रेणीकरण की बाबत आकस्मिक त्रुटियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी ।

**श्रेणीकरण में आकस्मिक त्रुटियों के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

†धब्बों के अन्तर्गत, फफूंदी के रोग, कीटाणु और नाशक जीवों, अंधड़, छिड़काव आदि के कारण पड़े धब्बे भी हैं।

अनुसूची 6

(नियम 2, 3 और 4 देखिए)

सफेदा किस्म के भारतीय आमों का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा	
	विशेष लक्षण प्रत्येक फल का न्यूनतम भार *	साधारण लक्षण
1	2	3
श्रेष्ठ	165 ग्राम	1. प्रत्येक आम :
विशेष	130 ग्राम	(क) **परिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि तत्पश्चात् परिवहन और विपणन के मामूली अनुक्रम में वह पक सकता हो ;
अच्छा	95 ग्राम	(ख) **अपनी किस्म के लक्षण के अनुसार रंग का हो और उसी किस्म के सामान्य आकार का हो ;
		(ग) **अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो और ठोस, युक्तियुक्त रूप से विकसित और अच्छी दशा में हो ;
		(घ) **फलों के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतियों रोगों, कीटाणुओं या क्षति के कारण होने वाले दोषों से मुक्त हो ।
		2. हवा से गिरे हुए और चोटिल फल पैक नहीं किए जाएंगे ।
		3. डंठल को फल के पास से हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खींच कर निकाला नहीं जाएगा।
		4. †ऐसे धब्बे अनुज्ञात होंगे जो आमो के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हो परन्तु यह तब जबकि कोई भी एक धब्बा 1.6 वर्ग से०मी० से बड़ा न हो ।

*ऐसे फलों के जो विनिर्दिष्ट भार सीमा से 30 ग्राम तक कम है, श्रेणीकरण की बाबत आकस्मिक त्रुटियो के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी ।

**श्रेणीकरण में आकस्मिक त्रुटियों के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

†धब्बों के अन्तर्गत, फफूंदी के रोग, कीटाणु और नाशक जीवो, अंधड़ छिड़काव आदि के कारण पड़े धब्बे भी है।

अनुसूची 7

(नियम 2, 3 और 4 देखिए)

फसली किस्म के भारतीय आमों का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा	
	विशेष लक्षण प्रत्येक फल का न्यूनतम भार*	साधारण लक्षण
1	2	3
श्रेष्ठ	935 ग्राम	1. प्रत्येक आम :
विशेष	670 ग्राम	(क) **परिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि तत्पश्चात् परिवहन और विपणन के मामूली अनुक्रम में वह पक सकता हो ;
अच्छा	465 ग्राम	(ख) **अपनी किस्म के लक्षण के अनुसार रंग का हो और उसी किस्म के सामान्य आकार का हो,
मानक	290 ग्राम	(ग) **अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो और ठोस, युक्तियुक्त रूप से विकसित और अच्छी दशा में हो,
		(घ) फलों के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतियों, रोगों, कीटाणुओं या क्षति के कारण होने वाले दोषों से मुक्त हो ।
		2. हवा से गिरे हुए और चोटिल फल पैक नहीं किए जाएंगे ।
		3. डंठल को फल के पास से हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खींच कर निकाला नहीं जाएगा ।
		4. †ऐसे धब्बे अनुज्ञात होंगे जो आमों के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हों परन्तु यह तब जबकि कोई भी एक धब्बा 1.6 वर्ग से०मी० से बड़ा न हो ।

*ऐसे फलों के, जो विनिर्दिष्ट भार सीमा से 30 ग्राम तक कम हैं, श्रेणीकरण की बाबत आकस्मिक त्रुटियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी ।

**श्रेणीकरण में आकस्मिक त्रुटियों के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी ।

† धब्बों के अन्तर्गत, फफूंदी के रोग, कीटाणु और नाशक जीवों, अंधड़, छिड़काव आदि के कारण पड़े धब्बे भी हैं ।

अनुसूची 8

(नियम 2, 3 और 4 देखिए)

बगानाफली, खाजरी और मिश्रो किस्म के भारतीय आमों का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा	
	विशेष लक्षण प्रत्येक फल का न्यूनतम भार*	साधारण लक्षण
1	2	3
श्रेष्ठ	410 ग्राम	1. प्रत्येक आम—
विशेष	350 ग्राम	(क) **परिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि तत्पश्चात् परिवहन और विपणन के मामूली अनुक्रम में वह पक सकता हो ;
अच्छा	290 ग्राम	(ख) **अपनी किस्म के लक्षण के अनुसार रंग का हो और उसी किस्म के सामान्य आकार का हो ;
मानक	235 ग्राम	(ग) **अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो और ठोस, युक्तियुक्त रूप से विकसित और अच्छी दशा में हो ;
		(घ) फलों के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतियों, रोगों, कीटाणुओं या क्षति के कारण होने वाले दोषों से मुक्त हो ।
		2 हवा से गिरे हुए और चोटिल फल पैक नहीं किए जाएंगे ।
		3. डंठल को फल के पास से हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खींच कर निकाला नहीं जाएगा ।
		4. †ऐसे धब्बे अनुज्ञात होंगे जो आमों के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हों परन्तु यह तब जब कि कोई भी एक धब्बा 1.6 वर्ग से०मी० से बड़ा न हो ।

*ऐसे फलों के, जो विनिर्दिष्ट भार सीमा से 30 ग्राम तक कम है, श्रेणीकरण की बाबत आकस्मिक त्रुटियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी ।

**श्रेणीकरण में आकस्मिक त्रुटियों के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी ।

†धब्बों के अन्तर्गत, फफूंदी के रोग, कीटाणु और नाशक जीवों, अंधड़, छिड़काव आदि के कारण पड़े धब्बे भी है ।

अनुसूची 9

(नियम 2, 3 और 4 देखिए)

गोपालभोग, आगरा मोहन भोग, मुशापेट, लक्ष्मणभोग, कृष्णपहाड़ी और भारती किस्म के भारतीय आमों का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा	
	विशेष लक्षण प्रत्येक फल का न्यूनतम भार †	साधारण लक्षण
1	2	3
श्रेष्ठ	350 ग्राम	1. प्रत्येक आम—
विशेष	290 ग्राम	(क) * परिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि तत्पश्चात् परिवहन और विपणन के सामूली अनुक्रम में वह पक सकता हो ;
अच्छा	235 ग्राम	(ख) * अपनी किस्म के लक्षण के अनुसार रंग का हो और उसी किस्म के सामान आकार का हो।
मानक	175 ग्राम	(ग) * अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो और ठोस, युक्तियुक्त रूप से विकसित और अच्छी दशा में हो।
		(घ) फलों के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतियों, रोगों, कीटाणुओं या क्षति के कारण होने वाले दोषों से मुक्त हो।
		2. हवा में गिरे हुए और चौटिल फल पैक नहीं किए जाएंगे।
		3. डंठल को फल के पास से हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खींच कर निकाला नहीं जाएगा।
		4. @ऐसे धब्बे अनुज्ञात हैं जो आमों के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हों, परन्तु यह तब जब कि कोई भी एक धब्बा 1.6 वर्ग से० मी० से बड़ा न हो।

† ऐसे फलों के जो विनिर्दिष्ट भार सीमा से 30 ग्राम तक कम हैं, श्रेणीकरण की यावत् आकस्मिक त्रुटियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

* श्रेणीकरण में आकस्मिक त्रुटियों के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

@ धब्बों के अन्तर्गत, फफूंदी के रोग, कीटाणु और नाशक जीवों, अधड़, छिड़काव आदि के कारण पड़े धब्बे भी हैं।

अनुसूची 10

(नियम 2, 3 और 4 देखिए)

स्वर्णरेखा और मुंडप्पा किस्म के भारतीय आमों का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा	
	विशेष लक्षण प्रत्येक फल का न्यूनतम भार †	साधारण लक्षण
1	2	3
श्रेष्ठ	290 ग्राम	1. प्रत्येक आम—
विशेष	235 ग्राम	(क) * परिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि तत्पश्चात् परिवहन और विपणन के सामूली अनुक्रम में वह पक सकता हो,
अच्छा	175 ग्राम	(ख) * अपनी किस्म के लक्षण के अनुसार रंग का हो और उसी किस्म के सामान्य आकार का हो ;
		(ग) * अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो और ठोस युक्तियुक्त रूप से विकसित और अच्छी दशा में हो,
		(घ) फलों के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतियों, रोगों, कीटाणुओं या क्षति के कारण होने वाले दोषों से मुक्त हो।
		2. हवा में गिरे हुए चौटिल फल पैक नहीं किए जाएंगे।
		3. डंठल को फल के पास से हटा दिया जाएगा, किन्तु उसे खींच कर निकाला नहीं जाएगा।
		4. @ऐसे धब्बे अनुज्ञात होंगे जो आमों के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हों परन्तु यह तब जबकि कोई भी एक धब्बा 1.6 वर्ग से० मी० से बड़ा न हो।

† ऐसे फलों के, जो विनिर्दिष्ट भार सीमा से 30 ग्राम तक कम है, श्रेणीकरण की यावत् आकस्मिक त्रुटियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

* श्रेणीकरण में आकस्मिक त्रुटियों के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

@ धब्बों के अन्तर्गत फफूंदी के रोग, कीटाणु और नाशक जीवों अधड़, छिड़काव आदि के कारण पड़े धब्बे भी है।

अनुसूची 11

(नियम 2, 3 और 4 देखिए)

मालदा किस्म के भारतीय आमों का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा।

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा	
	विशेष लक्षण प्रत्येक फल का न्यूनतम भार†	साधारण लक्षण
1	2	3
श्रेष्ठ	350 ग्राम	1. प्रत्येक आम—
विशेष	290 ग्राम	(क) * अपरिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि तत्पश्चात परिवहन और विपणन के मामूली अनुक्रम में वह पक सकता हो ;
अच्छा	235 ग्राम	(ख) * अपनी किस्म के लक्षण के अनुसार रंग का हो, और उसी किस्म के सामान्य आकार का हो ;
		(ग) * अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो और ठोस, युक्तियुक्त रूप से विकसित और अच्छी दशा में हो ;
		(घ) फलों के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतियों, रोग, कीटाणुओं या क्षति के कारण, होने वाले दोषों से मुक्त हो।
		2. हवा में गिरे हुए चौटिल फल पैक नहीं किए जाएंगे।
		3. डंठल को फल के पास से हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खींच कर निकाला नहीं जाएगा।
		4. @ऐसे धब्बे अनुज्ञात होंगे जो आमों के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हों परन्तु, यह तब जबकि, कोई भी एक धब्बा 1.6 वर्ग से० मी० से बड़ा न हो।

† ऐसे फलों के, जो विनिर्दिष्ट भार सीमा से 30 ग्राम तक कम हैं, श्रेणीकरण की बाबत आकस्मिक त्रुटियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

* श्रेणीकरण में आकस्मिक त्रुटियों के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

@ धब्बों के अन्तर्गत फफूंदी के रोग, कीटाणु और नाशक जीवों, अंधड़ छिड़काव आदि के कारण पड़े धब्बे भी हैं।

अनुसूची 12

(नियम 2, 3 और 4 देखिए)

मालगोआ किस्म के भारतीय आमों का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा	
	विशेष लक्षण प्रत्येक फल का न्यूनतम भार†	साधारण लक्षण
1	2	3
श्रेष्ठ	450 ग्राम	1. प्रत्येक आम :—
विशेष	390 ग्राम	(क) * अपरिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि तत्पश्चात परिवहन और विपणन के मामूली अनुक्रम में वह पक सकता हो ;
अच्छा	330 ग्राम	(ख) * अपनी किस्म के लक्षण के अनुसार रंग का हो और उसी किस्म के सामान्य आकार का हो ;
		(ग) * अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो और ठोस, युक्तियुक्त रूप से विकसित और अच्छी दशा में हो ;
		(घ) फलों के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतियों रोग, कीटाणुओं या क्षति के कारण होने वाले दोषों से मुक्त हो।
		2. हवा से गिरे हुए और चौटिल फल पैक नहीं किए जाएंगे।
		3. डंठल को फल के पास से हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खींच कर निकाला नहीं जाएगा।
		4. @ऐसे धब्बे अनुज्ञात होंगे जो आमों के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हों परन्तु यह तब जब कि कोई भी एक धब्बा 1.6 वर्ग से० मी० से बड़ा न हो।

† ऐसे फलों के, जो विनिर्दिष्ट भार सीमा से 30 ग्राम तक कम हैं, श्रेणीकरण की बाबत आकस्मिक त्रुटियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

* श्रेणीकरण में आकस्मिक त्रुटियों के लिए 5 प्रतिशत तक छूट की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

@ धब्बों के अन्तर्गत, फफूंदी के रोग, कीटाणु और नाशक जीवों अंधड़, छिड़काव आदि के कारण पड़े धब्बे भी हैं।

अनुसूची 13

(नियम 2, 3 और 4 देखिए)

लगडा किस्म के भारतीय आमो का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा	
	विशेष लक्षण प्रत्येक फल का न्यूनतम भार†	साधारण लक्षण
1	2	3
श्रेष्ठ	250 ग्राम	1 प्रत्येक आम— (क) परिपक्वता की ऐसी स्थिति म पहुच गया हो कि तत्पश्चात् परिवहन और विपणन के मामूली अनुक्रम मे व पक सकता हो , (ख) अपनी किस्म के लक्षण के अनुसार रग का हो, और उसी किस्म क सामान्य आकार का हो , (ग) * अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो और ठोस, युक्तियुक्त रूप मे विकसित और अच्छी दशा मे हो (घ) फलो के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतिया रोगो, कीटाणुओ या क्षति के कारण होने वाले दाणो से मुक्त हो। 2 हवा से गिरे हुए और चोटिल फल पैक नही किए जाएगे। 3 डठल फल के पास मे हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खीच कर निकाला नही जाएगा। 4 @ऐसे धब्बे अनुज्ञात होगे जो आमो के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हो परन्तु यह तब जबकि कोई भी एक धब्बा 1 6 वर्ग से० मी० से बडा न हो।
विशेष	200 ग्राम	

† ऐसे फलो के जो विनिर्दिष्ट भार सीमा से 30 ग्राम तक कम है, श्रेणीकरण की बाबत आकस्मिक त्रुटियो के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

* श्रेणीकरण मे आकस्मिक त्रुटियो के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

@ धब्बो के अन्तर्गत, फफूदी के रोग, कीटाणु और नाशक जीवो, अवड, छिडकाव आदि के कारण पडे धब्बे भी है।

अनुसूची 14

(नियम 2, 3 और 4 देखिए)

कचन (बथुआ) किस्म के भारतीय आमो का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा	
	विशेष लक्षण प्रत्येक फल का न्यूनतम भार †	साधारण लक्षण
1	2	3
श्रेष्ठ	290 ग्राम	1 प्रत्येक आम— (क) * परिपक्वता की ऐसी स्थिति मे पहुच गया हो कि तत्पश्चात परिवहन और विपणन के मामूली अनुसार मे वह पक सकता हो (ख) * अपनी किस्म के लक्षण के अनुसार रग का हो, और उसी किस्म के सामान्य आकार का हो , (ग) * अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो और ठोस, युक्तियुक्त रूप से विकसित और अच्छी दशा मे हो, (घ) फलो के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतियो, रोगो कीटाणुओ या क्षति के कारण होने वाले दाणो से मुक्त हो। 2 हवा से गिरे हुए और चोटिल फल पैक नही किए जाएगे, 3 डठल को फल के पास मे हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खीच कर निकाला नही जाएगा 4 @ऐसे धब्बे अनुज्ञात होगे जो आमो के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हो परन्तु यह तब जब कि कोई भी एक धब्बा 1 6 वर्ग से० मी० मे बडा न हो।
विशेष	235 ग्राम	
अच्छा	175 ग्राम	

† ऐसे फलो के, जो विनिर्दिष्ट भार सीमा से 30 ग्राम तक कम है श्रेणीकरण की बाबत आकस्मिक त्रुटियो के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

* श्रेणीकरण मे आकस्मिक त्रुटियो के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

@ धब्बो के अन्तर्गत फफूदी के रोग कीटाणु और नाशक जीवो अवड छिडकाव आदि के कारण पडे धब्बे भी है।

[स० 10-6/79-ए० एम०]

क० एल० गुप्ता अवर सचिव

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

New Delhi, the 7th January, 1981

S.O 109.—Whereas certain draft of the Mangoes Grading and Marking Rules, 1979, was published, as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking), Act, 1937 (1 of 1937) in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th January, 1980, at pages 146 to 156 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Rural Reconstruction, No S O 106, dated the 29th December, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of fortyfive days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette,

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 19th January, 1980,

And whereas, objections and suggestions received in respect of the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely —

RULES

1. Short title application and commencement —(1) These rules may be called the Mangoes Grading and Marking Rules 1981

(2) They shall apply to Mangoes produced in India.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. Definitions —In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "Schedule' means a schedule appended to these rules,

(c) "Authorised packer means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation by the Agricultural Marketing Adviser, for getting the commodity graded and Agmarked in accordance with grade standards and procedure prescribed under the rules,

(d) Certificate" means certificate of authorisation,

(e) "Shoulder" means the part of the fruit around the neck

3 Grade designations —The grade designation to indicate the quality of the Mangoes shall be as set out in column 1 of Schedule II to XIV

4 Definition of quality —The quality indicated by the grade designations shall be as set out against each grade designations in columns 2 and 3 of Schedule II to XIV

5 Grade designation mark —The grade designation mark shall consist of a label specifying the grade designation and bearing a design (consisting of outline map of India with the word "AGMARK" and figure of the rising sun with the words "Produce of India" and "भारतीय उत्पाद" resembling the mark as set out in Schedule I

6 Method of marking —(1) The grade designation mark shall be securely affixed to each case/package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser

(2) In addition to the grade designation, the following particulars shall also be clearly marked on the label,

(i) Name of the variety,

(ii) Number of fruits,

(iii) Net weight,

(iv) Name of the packing station,

(v) Date of packing, and

(vi) Any other particulars as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser from time to time

(3) The authorised packer may, after obtaining the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private trade mark on a container in a manner approved by the said officer provided that the private trade mark does not represent a quality or grade of mangoes different from that indicated by the grade designation mark affixed to the container in accordance with these rules

7 Method of packing —(1) Mangoes shall be packed in wooden crate or baskets or any other type of container and in such manner as may be specified from time to time by the Agricultural Marketing Adviser,

(2) Packing material shall be clean and dry, free from fungus and insect attack and obnoxious smell,

(3) Each package shall contain Mangoes of the same variety and of the same grade designation, and the top layer shall be representative of the entire contents of the package in respect of size, maturity, colour, shape and freedom from visible defects,

(4) Each package shall be securely closed and sealed in the manner prescribed by the Agricultural Marketing Adviser

8 Special conditions of certificate of authorisation —In addition to the conditions specified in the rule 4 of the General Grading and Marking Rules 1937, the following special conditions shall be observed by the packers to the satisfaction of the Agricultural Marketing Adviser namely -

(1) An authorised packer shall make such arrangements for testing Mangoes as the Agricultural Marketing Adviser may specify by general or special order from time to time

(2) An authorised packer shall provide such facilities to the inspecting officers duly authorised by the Agricultural Marketing Adviser in this behalf as may be necessary for them to discharge their duties under these rules

9 Repeal and Saving —(1) The following rules are hereby replaced .

(i) Alphonso Mangoes (Export) Grading and Marking Rules, 198

(ii) Alphonso Mangoes (Home Consumption) Grading and Marking Rules, 1939

(iii) Kanchan (Bathua) Mangoes (Home Consumption) Grading and Marketing Rules, 1955

(2) Such repeal shall not affect anything duly done or suffered under the repealed rules

Schedule I
(See rule 5)
Grade designation mark

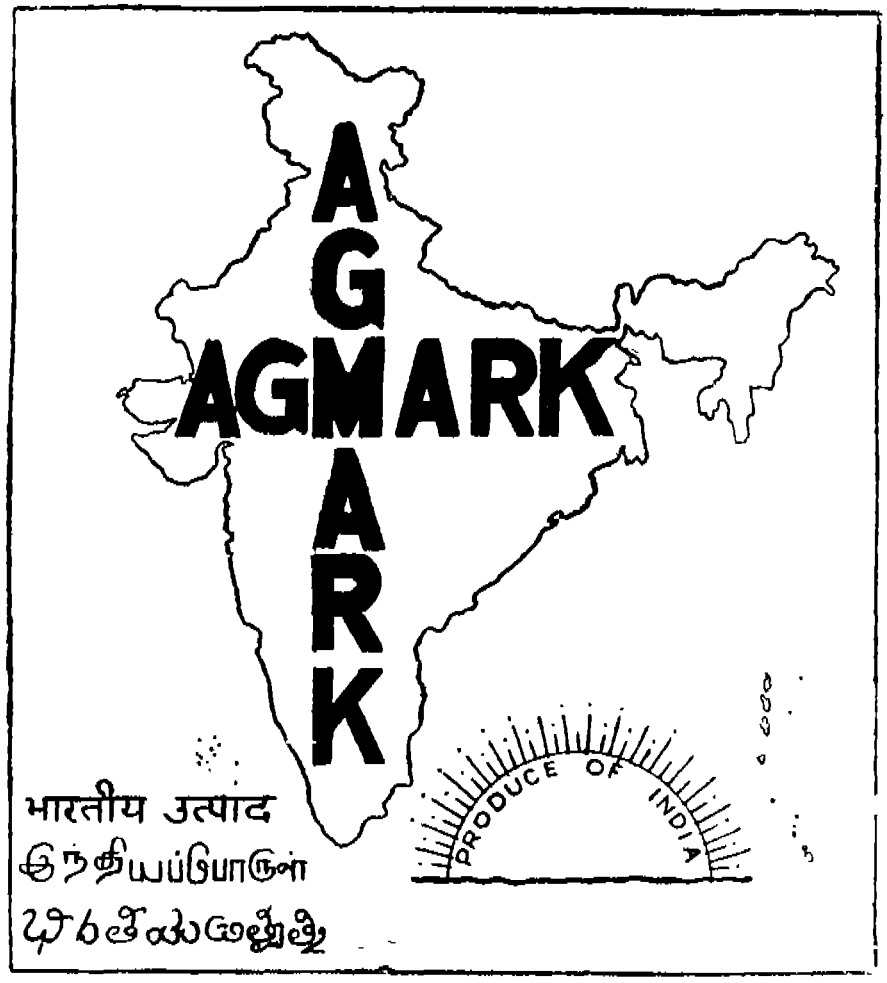

SCHEDULE II
(See rules 2, 3 and 4)
Grade designation and definition of quality of the ALPHONSO Variety of Indian Mangoes

Grade Designation	Definition of quality	
	Special characteristics Minimum weight of each fruit*	General characteristics
1	2	3
Choice	280 gms.	1. Each Mango shall :
Special	230 gms.	(a) (a) have reached a stage of maturity which will permit the subsequent completion of ripening in the ordinary course of transport and marketing;
Good	160 gms.	(b) (a) have developed the characteristics colour of the variety, viz., yellow-red skin when ripe, and all the fruits shall be reasonably uniform in colour throughout the pack;
Standard	120 gms	(c) (a) have the shape normal to the variety and be free from mal-formation;
		(d) have good keeping quality and be firm, reasonably developed and in good condition;
		(e) be free from the defects due to diseases or insects or injury affecting the keeping quality of the fruits;
		2. Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed.
		3 = Blemishes not affecting the keeping quality shall be permitted, provided no single mark is larger than 1.6 sq. cm. in area.
		4 The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out.

* A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruits which are below the specified limit of weight to the extent of 30 gms.

(a) A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading.

= Blemishes include marks due to fungus diseases, insect-pests, hail-storm, spray, etc.

SCHEDULE III

(See rules 2, 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of the DASHEHRI variety of Indian Mangoes

Grade Designation	Definition of quality	
	Special characteristics Minimum weight of each fruits*	General characteristics
1	2	3
Choice Special Good	250 gms. 150 gms. 100 gms.	1. Each Mango shall : (a) @ have reached a stage of maturity which will permit the subsequent completion of ripening in the ordinary course of transport and marketing ; (b) @ have developed the characteristics colour of the variety, viz., yellow/red skin when ripe, and the shape normal to the variety ; (c) @ have good keeping quality and be firm, reasonable developed and in good condition ; (d) @ be free from mal-formation, and the defects due to diseases, insects, or injury affecting the keeping quality ; 2. Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed. 3. The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out. 4. = Blemishes not affecting the keeping quality shall be permitted, provided no single mark is larger than 1.6 sq. cm. in area.

*A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruits which are below the specified limit of weigh to the extent of 30 gms.

@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading.

= Blemishes include marks due to fungus diseases, insect-pests, hail-storm, spray etc.

Schedule IV

(See rules 2, 3, and 4)

Grade designation and definition of quality of the RUMANI, MEELAM, PAIRI, RASAPURI AND NADUSALI varieties of Indian Mangoes.

Grade designation	Definition of quality	
	Special characteristics Minimum weight of each fruit*	General characteristics
1	2	3
Choice Special Good	235 gms. 175 gms. 115 gms	1. Each Mango shall : (a) @ have reached a stage of maturity which will permit the subsequent completion of ripening in the ordinary course of transport and marketing ; (b) @ have developed the characteristic colour of the variety and the shape normal to the variety ; (c) @ have good keeping quality and be firm, reasonably developed and in good condition ; (d) be free from mal-formation and the defects due to diseases, insects or injury affecting the keeping quality ; 2. Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed. 3. The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out. 4. = Blemishes not affecting the keeping quality shall be permitted, provided no single mark is larger than 1.6 sq. cm. in area.

*A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruits which are below the specified limit of weight to the extent of 30 gms.

@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading.

= Blemishes include marks due to fungus diseases, insect-pests, hail-storm, spray, etc.

SCHEDULE V

(See rules 2, 3, and 4)

Grade designation and definition of quality of the BANGALORA- TOTAPURI and COLLECTOR varieties of Indian Mangoes.

Grade Designation	Definition of quality	
	Special characteristics Minimum weight of each fruit*	General Characteristics
1	2	3
Choice	410 gms.	1. Each Mango Shall :
Special	350 gms.	(a) @ have reached a stage of maturity which will permit the subsequent completion of ripening in the ordinary course of transport and marketing ;
Good	290 gms.	(b) @ have developed the characteristic colour of the variety and the shape normal to the variety ;
		(c) @ have good keeping quality and be firm, reasonably developed and in good condition ;
		(d) @ be free from mal-formation and the defects due to diseases, insects or injury affecting the keeping quality of the fruits.
		2. Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed.
		3. The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out.
		4. = Blemishes not affecting the keeping quality shall be permitted provided no single mark is larger than 1.6 sq. c.m. in area.

* A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruits which are below the specified limit of weight to the extent of 30 gms.

@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading.

= Blemishes include marks due to fungus diseases, insect-pests hail-storm, spray, etc.

SCHEDULE VI

(See rules 2, 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of the SAFEDA variety of Indian Mangoes

Grade Designation	Definition of quality	
	Special characteristics Minimum weight of each fruit*	General Characteristics
1	2	3
Choice	165 gms.	1. Each Mango shall :
Special	130 gms.	(a) @ have reached a stage of maturity which will permit the subsequent completion of ripening in the ordinary course of transport and marketing ;
Good	95 gms.	(b) @ have developed the characteristic colour of the variety and the shape normal to the variety ;
		(c) @ have good keeping quality and be firm, reasonably developed and in good condition ;
		(d) @ be free from mal-formation and the defects due to diseases, insect, or injury affecting the keeping quality of the fruits ;
		2. Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed.
		3. The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out.
		4. = Blemishes not affecting the keeping quality shall be permitted provided no single mark is larger than 1.6 sq. cm. in area.

* A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruits which are below the specified limit of weight to the extent of 30 gms.

@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading.

= Blemishes include marks due to fungus diseases, insect-pests, hail-storm, spray, etc.

SCHEDULE VII

(See rules 2, 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of the FAZLI variety of Indian Mangoes.

Grade Designation	Definition of quality	
	Special characteristics Minimum weight of each fruit*	General characteristics
1	2	3
Choice	935 gm.	1. Each Mango shall :
Special	670 gms.	(a) @ have reached a stage of maturity which will permit the subsequent completion of ripening in the ordinary course of transport and marketing.
Good	465 gms.	(b) @ have developed the characteristic colour of the variety and the shape normal to the variety ;
Standard	290 gms.	(c) @ have good keeping quality and be firm, reasonably developed and in good condition ;
		(d) be free from mal-formation and the defects due to diseases insects, or injury affecting and keeping quality.
		2. Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed.
		3. The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out.
		4. = The blemishes not affecting the keeping quality shall be permitted, provided no single mark is larger than 1.6 sq. cm. in area.

* A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruits which are below the specified limit of weight to the extent of 30 gms.

@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading.

= Blemishes include marks due to fungus diseases, insect-pests, hail-storm, spray, etc.

SCHEDULE VIII

(See rules 2, 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of the BANGANAPALLI, KHAJRI and MIGGO varieties of Indian Mangoes.

Grade Designation	Definition of quality	
	Special characteristics Minimum weight of each fruit.*	General characteristics
1	2	3
Choice	410 gms.	1. Each Mango shall :
Special	350 gms.	(a) @ have reached a stage of maturity which will permit the subsequent completion of ripening in the ordinary course of transport and marketing;
Good	290 gms.	(b) @ have developed the characteristic colour of variety and the shape normal to the variety ;
Standard	235 gms.	(c) @ have good keeping quality and be firm, reasonably developed and in good condition ;
		(d) be free from mal-formation and the defects due to diseases, insects or injury affecting the keeping quality.
		2. Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed.
		3. the stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out.
		4. = Blemishes not affecting the keeping quality shall be permitted provided no single mark is larger than 1.6 sq. cm. in area.

* A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruits which are below the specified limit of weight to the extent of 30 gms.

@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading.

= Blemishes include Marks due to fungus diseases, insect-pests, hail-strom, spray, etc.

SCHEDULE IX

(See rules 2, 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of the GOPALBHOG, AGRA MOHAN BHOG, MURSHAPET, LAKSHMAN BHOG KOSPAHARI and BHARATI varieties of Indian mangoes.

Grade Designation	Definition of quality	
	Special characteristics Minimum weight of each fruit*	General characteristics
1	2	3
Choice	350 gms.	1. Each mango shall :
Special	290 gms.	(a) @ have reached a stage of maturity which will permit the subsequent completion of ripening in the ordinary course of transport and marketing;
Good	235 gms.	(b) @ have developed the characteristic colour of the variety and the shape normal to the variety;
Standard	175 gms.	(c) @ have good keeping quality and be firm, reasonably developed and in good condition;
		(d) be free from mal-formation and the defects due to diseases, insects or injury affecting the keeping quality.
		2. Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed.
		3. The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out.
		4. = Blemishes not affecting the keeping quality shall be permitted, provided no single mark is larger than 1.6 sq. cm. in area.

* A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruits which are below the specified limit of weight to the extent of 30 gms.

@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading.

= Blemishes include marks due to fungus diseases, insect pests, hail-storm, spray, etc.

SCHEDULE X

(See Rules 2, 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of SWARANREKHA and MUNDAPPA varieties of Indian Mangoes.

Grade Designation	Definition of quality	
	Special characteristics Minimum weight of each fruit*	General charactristics
1	2	3
Choice	290 gms.	1. Each mango shall :
Special	235 gms.	(a) @ have reached a stage of maiurity which will permit the subsequent completion of ripening t in the ordinary course of transport and marketing;
Good	175 gms.	(b) @ have developed the characteristic colour of the variety and the shape normal to the variety;
		(c) @ have good keeping quaity and be firm, reasonably developed and in good condition;
		(d) be free from mal-formation and the defects due to diseases, insects or injury affecting the keeping quality.
		2. Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed.
		3. The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out.
		4. = Blemishes not affecting the keeping quality of the fruit shall be permitted provided no single mark is larger than 1.6 sq. cm. in area.

* A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruits which are below the specified limit of weight to the extent of 30 gms.

@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading.

= Blemishes include marks due to fungus diseases, insect pest, hail-storm, spray, etc.

SCHEDULE XI

(See rules 2, 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of the MALDA variety of Indian Mangoes

Grade designation	Definition of quality	
	Special characteristics Minimum weight of each fruit*	General characteristics
1	2	3
Choice	350 gms	1 Each mango shall
Special	290 gms.	(a) @ have reached a stage of maturity which will permit the subsequent completion of ripening in the ordinary course of transport and marketing,
Good	225 gms	(b) @ have developed the characteristic colour of the variety and the shape normal to the variety,
		(c) @ have good keeping quality and be firm, reasonably developed and in good condition,
		(d) be free from all mal-formation and the defects due to diseases, insects or injury affecting the keeping quality
		2 Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed
		3 The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out
		4. = Blemishes not affecting the keeping quality of the fruit shall be permitted, provided no single mark is larger than 1 6 sq cm. in area.

* A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruits which are below the specified limit of weight to the extent of 30 gms.

@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading

= Blemishes include marks due to fungus diseases, insect-pests, hail storm, spray, etc

SCHEDULE XII

(See rules 2, 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of the MALGOA variety of Indian Mangoes

Grade designation	Definition of quality	
	Special characteristics Minimum weight of each fruit*	General characteristics
1	2	3
Choice	450 gms.	1 Each Mango shall .
Special	390 gms	(a) @ have reached a stage of maturity which will permit the subsequent completion of ripening in the ordinary course of transpoit and marketing,
Good	330 gms	(b) @ have developed the characteristic colour of the variety and the shape normal to the variety,
		(c) @ have good keeping quality and be firm, reasonably developed and in good condition,
		(d) be free from mal-formation and the defects due to diseases, insects or injury affecting the keeping quality
		2 Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed
		3. The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out
		4 = Blemishes not affecting the keeping quality of the fruit shall be permitted provided no single mark is larger than 1 6 sq cm in area

* A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruits which are below specified limit of weight to the extent of 30 gms

@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading

= Blemishes include marks due to fungus diseases, insect pests, hail-storm, spray, etc

SCHEDULE XIII

(See rules 2, 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of the LANGRA variety of Indian mangoes.

Grade designation	Definition of quality	
	Special characteristics Minimum weight of each fruit*	General characteristics
1	2	3
Choice Special	250 gms. 200 gms.	1. Each Mango shall : (a) @ have reached a stage of maturity which will permit the subsequent completion of ripening in the ordinary course of transport and marketing; (b) @ have developed the characteristic colour of the variety and the shape normal to the variety; (c) @ have good keeping quality and be firm, reasonably developed and in good condition; (d) be free from mal-formation and the defects due to diseases, insects or injury affecting the keeping quality. 2. Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed. 3. The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out. 4. £ Blemishes not affecting the keeping quality of the fruit shall be permitted provided no single mark is larger than 1.6 sq. cm. in area.

* A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruit which are below the specified limit of weight to the extent of 30 gms.

@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading.

£ Blemishes include marks due to fungus diseases, insect-pests, hail-storm, spray, etc.

SCHEDULE XIV

(See rules 2, 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of the KANCHAN (BATHUA) variety of Indian Mangoes.

Grade designation	Definition of quality	
	Special characteristics Minimum weight of each fruit*	General characteristics
1	2	3
Choice Special Good	290 gms. 205 gms. 175 gms.	1. Each mango shall : (a) @ have reached a stage of maturity which will permit the subsequent completion of ripening in the ordinary course of transport and marketing; (b) @ have developed the characteristics colour of the variety and the shape normal to the variety; (c) @ have good keeping quality and be firm, reasonably developed and in good condition; (d) be free from mal-formation and the defects due to diseases, insect or injury affecting the keeping quality. 2. Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed. 3. The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out. 4. £ Blemishes not affecting the keeping quality of the fruit shall be permitted, provided no single mark is larger than 1.6 sq. cm. in area.

* A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruits which are below the specified limit of weight to the extent of 30 gms.

@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading.

£ Blemishes include marks due to fungus, diseases, insect-pests, hail-storm, spray, etc.

[No. 10-6/79-AM]

K.L. GUPTA, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1980

का० आ० 110—यत केन्द्रीय सरकार का दिल्ली के लिए बृहत योजना क्षेत्रीय विकास योजना मे यहां नीचे बतलाये गये क्षेत्र के बारे मे सशोधन करने का जो प्रस्ताव है, उसको दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के अन्तर्गत, 1 सितम्बर, 1979 के नोटिस स० एफ० 20 (11)/77 एम० पी० के द्वारा उक्त नोटिस से 30 दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित किया गया था जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 11ए० की उपधारा (3) मे अपेक्षित है।

और यत. उपर्युक्त सशोधनो के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अब यत उक्त अधिनियम की धारा 11 ए० की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार जिस तारीख को यह अधिसूचना भारत के राजपत्र मे छपेगी उस तारीख से दिल्ली की उक्त बृहत योजना क्षेत्रीय विकास योजना मे निम्नलिखित सशोधन करती है नामत :

संशोधन

कनाट प्लेस (भीतरी परिधि रोड), रेडियल रोड न० 8, कनाट सर्कस रोड (बाह्य परिधि) तथा रेडियल रोड न० 1, से घिरे लगभग 1.821 हेक्टेयर (4 5 एकड़) के क्षेत्र का भू प्रयोग "मनोरजन" से "वाणिज्यिक" (भूमिगत विपणन केन्द्र) मे बदला गया है।

[सख्या के० 13016/62/76-यू० डी०-II ए०]

एस० बालाकृष्णन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 24th December, 1980

S.O. 110.—Whereas certain notification which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the area mentioned hereunder, was published with Notice No F. 20(11)/77-MP dated the 1st September 1979, in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub section (3) of section 11A of the said Act, within thirty days from the date of said Notice ;

And whereas no objection or suggestion has been received with regard to the aforesaid modification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, namely :—

Modification :

"The land use of an area measuring about 1 821 hect. (4 5 acres), bounded by Connaught Place (Inner Circle Road), Radial Road No 8, Connaught Circus Road (Outer Circle) and Radial Road No. 1, is changed from 'Recreational' to 'Commercial' (Underground Shopping Centre)"

[No K-13016/62/76-UD/IIA]

S. BALAKRISHNAN, Desk Officer

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1980

का० आ० 111—अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एयर वाइस मार्शल पी० सी० डेरे को, उस तारीख से जिससे कि वे पद का कार्यभार ग्रहण करें, पूर्णकालिक सदस्य (परिचालन) नियुक्त करती है।

[सं० ए० वी० 24012/1/80-ए० ए०]

वी० तुलसीदास, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 24th December, 1980

S O. 111.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971) the Central Government hereby appoints AIR VICE MARSHAL P S. DERE as whole-time Member (Operations), with effect from the date he assumes charge of the office.

[No AV-24012/1/80-AA]

V THULASI DAS, Under Secy

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर 1980

का० आ० 112—निष्क्रान्त हिस (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 (1951 का XIV) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना सख्या 14((6)/77-एस० एस०-11 दिनाक 30-5-1978 द्वारा श्री ए० जी० वासवानी, सेवानिवृत्ति बदोबस्त आयुक्त की, केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली के लिए, सक्षम अधिकारी के रूप मे की गई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

[सख्या 14(6)/77-एस० एच०-1]

एम० एम० वाधवानी, अवर सचिव

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 22nd December, 1980

S.O. 112—The appointment of Shri A. G. Vaswani, Retired Settlement Commissioner, as Competent Officer for Union Territory of Delhi made by the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 4 of the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (XIV of 1951) vide Notification No 14(6)/77-SS.II, dated 30-5-1978 is terminated with immediate effect

[No. 14(6)/77-SS.II]

N. M. WADHWANI, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1980

का० आ० 113—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1980 (1890 का 9) की धारा 47 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, रेल पर्यटक अभिकर्ताओ की नियुक्ति की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमो का सक्षिप्त नाम रेल पर्यटक अभिकर्ता नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाए,—इन नियमो, जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "व्यक्ति" के अन्तर्गत, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भागीदारी फर्म, कम्पनी अधिनियम,

1956 के अधीन निगमित कोई कम्पनी और भारत से बाहर के किसी देश में निगमित ऐसी कम्पनी, जिसका शाखा कार्यालय भारत में हो, आती है।

(ख) "सरकार" से भारत की केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है।

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो उनके भारतीय रेल अधिनियम 1890 में हैं।

3. रेल पर्यटक अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति की शर्तें.—रेल के पर्यटक अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों/अपेक्षाओं का समाधान करना चाहिए, अर्थात्—

(1) उसके पास भारत में पर्यटक अभिकर्ता का कारबार चलाने के लिए सक्षम अधिकारी से प्राप्त व्यवसाय अनुज्ञप्ति होनी चाहिए, (2) वह वित्तीय रूप से सुदृढ़ होना चाहिए तथा उसके पास भारत में आय-कर प्राधिकारी से प्राप्त नवीनतम आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र होना चाहिए। वह व्यक्ति, जिसके पास न्यूनतम एक लाख रुपए की समादत्त पूंजी है, वित्तीय रूप से सुदृढ़ समझा जाएगा; (3) उसने सरकार से यात्रा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की मान्यता प्राप्त की हो, (4) वह न्यूनतम एक वर्ष की अवधि से यात्रा अभिकर्ता का कारबार चला रहा हो, (5) उसके पास भारत में विदेशी मुद्रा के व्योहार/संभालने के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त धन परिवर्तन अनुज्ञप्ति हो; (6) उसके पास नगर में किसी केन्द्रीय स्थान पर पर्याप्त सुविधाओं सहित उचित रूप से अनुरक्षित कार्यालय और परिसर होना चाहिए जिससे कि वह पर्याप्त संख्या में ग्राहकों से मिल सके और उन्हें युक्तियुक्त सुविधाएं दे सके।

4. वह प्राधिकारी जिसे नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना है.—रेल के पर्यटक अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए सम्बद्ध रेल के महाप्रबंधक (वाणिज्य) को सम्बोधित करके किया जाएगा और वह इस साक्ष्य से सम्यकतः समर्थित होगा कि सम्बद्ध व्यक्ति आवेदन नियम 3 में अधिकथित पात्रता की शर्तों/अपेक्षाओं का समाधान करता है और उन्हें पूरा करता है।

5. रेल प्रशासन का रेल के पर्यटक अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करने का अधिकार.—रेल प्रशासन को पूर्वोक्त नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को आवेदन को, यदि वह व्यक्ति पात्रता की सभी या किसी शर्त का समाधान नहीं करता या उसे पूरा नहीं करता है और उसे अपने समाधानप्रद रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् रद्द करने का अधिकार होगा। रेल प्रशासन को किसी व्यक्ति को किसी कारण से जो उसे संक्षिप्त रूप से संसूचित किया जाएगा पर्यटक अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुज्ञा देने का पूर्ण अधिकार होगा, यदि उसकी राय में वह व्यक्ति रेल के पर्यटक अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त या योग्य व्यक्ति नहीं है।

रेल प्रशासन को, कारण बताओ सूचना देने के पश्चात पहले से मंजूर की गई अनुज्ञा को किसी भी समय रद्द या प्रतिसंहृत या प्रत्याहृत करने का भी अधिकार होगा। रेल प्रशासन, रेल के पर्यटक अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुज्ञा के रद्दकरण, प्रतिसंहरण या प्रत्याहरण के परिणामस्वरूप पर्यटक अभिकर्ता द्वारा सहन की गई या की जाने वाली अथवा उसे कारित या कारित होने वाली किसी हानि/नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

6.—पर्यटक अभिकर्ता द्वारा रेल प्रशासन से करार का निष्पादन—उस व्यक्ति को, जो रेल के पर्यटक अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, रेल प्रशासन से प्ररूप "क" पर एक करार का निष्पादन करना होगा।

7. पर्यटक अभिकर्ता के कार्यालय का सक्षम और प्रशिक्षित कर्मचारिवृन्द द्वारा अनुरक्षण.—पर्यटक अभिकर्ता, पर्यटक अभिकरण के कारबार के संचालन के सम्बन्ध में अपने कार्यलय में सक्षम और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति करेगा जो, अन्य बातों के साथ-साथ रेल के कार्यकरण से सुपरिचित होगा और जो ग्राहकों को गाडियों में स्थानों की सुविधा की उपलब्धता की बाबत अद्यतन और सही जानकारी दे सकने योग्य होगा।

8— रेल प्रशासन और पर्यटक अभिकर्ता के बीच करार से और उसके सम्बंध में उत्पन्न होने वाले विवादों, मतभेदों का निपटारा.—रेल प्रशासक और पर्यटक अभिकर्ता के बीच करार में और या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले और या करार से संबंधित किसी विवाद, मतभेद आदि का विनिश्चय महा प्रबंधक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा मध्यस्थ का पचांट अंतिम और दोनो पक्षकारों पर आबदकर होगा। मध्यस्थम कार्यवाहिया माध्यस्थम अधिनियम, 1940 और/या उसके अधीन बनाए गए समय समय पर प्रवृत्त नियमों और/या आदेशों के उपबन्धो द्वारा शासित होगी। माध्यस्थम का स्थान वह होगा, जो मध्यस्थ द्वारा नियत किया जाए। माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट किसी विवाद के होते हुए भी, दोनो पक्षकार, यदि यह अन्यथा सम्भव हो तो करार, के अधीन अपनी बाध्यताओं का निर्वहन जारी रखेंगे। -

9. पर्यटक अभिकर्ता द्वारा प्रतिभूति का निक्षेप—पर्यटक अभिकर्ता ऐसी रकम, जो रेल प्रशासन इस प्रयोजन के लिए अनुबद्ध अवधि के भीतर, करार के उपबंधो और पर्यटक अभिकर्ता के रूप में करार के अधीन उसकी बाध्यताओं की सम्यक पूर्ति के लिए समय-समय पर नियत करे, जमा करेगा और उसका प्रतिभूति निक्षेप बनाए रखेगा प्रतिभूति निक्षेप करार की किसी शर्त के भंग होने की दशा में समपहृत हो जाएगा।

10. रेल प्रशासन का पर्यटक अभिकर्ता के परिसर/कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार—रेल प्रशासन को, पर्यटक अभिकर्ता के कार्यालय और/या परिसर का पर्यटक अभिकर्ता के कारबार के समय के दौरान किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए रेल प्रशासन को अपने अधिकारियो और अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक और उपयुक्त समझे, प्रतिनियुक्ति करने की स्वतंत्रता होगी।

[सं० टी० सी०-II/2895/78/नियम]

के० बालचन्द्रन, सचिव
और पदेन संयुक्त सचिव

प्ररूप-क (नियम 6)

पर्यटक अभिकर्ताओं द्वारा रेल के साथ निष्पादित किए जाने वाले करार का नमूना प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में मैसर्स..... जिसे इसमें आगे अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं और दूसरे पक्षकार के रूप में मुख्य .....अधीक्षक,..... रेल के माध्यम से कार्य करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इसमें आगे सरकार कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, के बीच आज तारीख .. ..को किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी को इसमें यथा उपबन्धित संलग्न अनुसूची (अनुसूचियों) में उल्लिखित रेल टिकटों के विक्रय के लिए सरकार के पर्यटक अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

अब अनुज्ञप्तिधारी और सरकार द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :—

1. सरकार अनुज्ञप्तिधारी को रेल टिकटों के विक्रय के लिये इसमें और इसकी अनुसूचियों में जो इस करार का भाग होंगी अन्तर्विष्ट निबंधों और शर्तों पर सरकार के पर्यटक अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति करती है। अनुज्ञप्तिधारी अनुसूचियों में उल्लिखित सभी या किन्हीं टिकटों के, उनमें

विनिर्दिष्ट शर्तों और नियमों पर और आई इंडियन रेलवे कान्फ्रेंस एसोसियेशन कोचिंग टैरिफ और अन्य प्रकाशनों या रेल के अनुदेशों में समय समय पर अधिसूचित उन से संबंधित नियमों के अधीन रहते हुए, जारी करने का जिम्मा लेता है।

2 अनुज्ञप्तिधारी सलग्न अनुसूचियों में उल्लिखित टिकट केवल निम्नलिखित स्थानों पर अपने कार्यालयों से जारी करेगा, किसी अन्य स्थान से नहीं —

1. . . . . 4 . .
2. . . . 5 . .
3 . . . 6. . . . . .

3 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रय किये जाने वाले कूपन, विशेष और अन्य टिकट उस प्रारूप रंग आदि में होंगी, जो रेल प्रशासन समय-समय पर विहित करे और सरकार उनकी अनुज्ञप्तिधारी के खर्चे पर व्यवस्था करेगी। ऐसी टिकटों की मांग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रेल द्वारा समय-समय पर विहित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

4. रेल स्टेशनों पर प्रयुक्त बहियों और प्रारूपों का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टिकटों के स्टाक और विक्रय के संबंध में लेखा रखने के लिये प्रयोग किया जाएगा। ऐसी बहियों और प्रारूपों का प्रदाय सरकार अनुज्ञप्तिधारी को निःशुल्क करेगी।

5. अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वर्ग के लिये रेल द्वारा विहित चालू किराये से कम या अधिक पर टिकट जारी नहीं करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक टिकट पर उस के लिये धारित किराये की रकम दर्शित करेगा।

6 लेखाओं के समायोजनों के प्रयोजन के लिये, अनुज्ञप्तिधारी . . . . . रेल के उपमुख्य लेखा अधिकारी यातायात लेखा को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के पश्चात् पांच कार्य दिवस के भीतर उस अवधि के दौरान जारी की गई टिकटों की विशिष्टियां दर्शाते हुए लेखा या विवरण भेजेगा। अनुज्ञप्तिधारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रेषण विहित रेल कार्यालयों में विनिर्दिष्ट तारीखों को नियमित रूप से मिल रहे हैं। फर्क और विवादयुक्त मदों का समायोजन विवरणों की जांच हो जाने के पश्चात् किया जायगा।

यदि किसी 15 दिन की अवधि के दौरान कोई यातायात नहीं होता, तो हस्तगत टिकटों की समाप्त संख्या दर्शाते हुए शून्य विवरण उप मुख्य लेखा अधिकारी (यातायात लेखा), रेल को भेजा जायगा।

7. जांच पड़ताल और निरीक्षण के प्रयोजन के लिए, अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालयों का निरीक्षण लेखा/वाणिज्य विभाग और कानूनी लेखा परीक्षा के प्रतिनिधि और सरकार के ऐसे अन्य प्रतिनिधि ऐसे अन्तरालों पर कर सकेंगे, जो सरकार विनिश्चित करे। अनुज्ञप्तिधारी सभी सुविधाएं देने का भार अपने ऊपर लेगा और सभी सुसंगत अभिलेखों तक पूर्ण पहुंच की अनुज्ञा देगा तथा उनकी जांच पड़ताल और निरीक्षण के लिए ऐसी सभी आवश्यक सहायता देगा जिसकी ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा अपेक्षा की जाए। अनुज्ञप्तिधारी अपनी लागत और व्यय पर पर्यटकों का टिकटों आदि के विक्रय के लिए अपने अभिकरण कार्यालय को इस प्रकार रखेगा, जैसी रेल प्रशासन द्वारा अपेक्षा की जाए।

8 अनुज्ञप्तिधारी उन सभी हानियों या नुकसानियों के लिए सम्पूर्णतः और पूर्णतः उत्तरदायी होगा, जो सरकार द्वारा अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं के किसी कार्य या लोप के कारण उठाई गई हों और यह सरकार की सभी ऐसी हानियों या नुकसानियों या खर्चों, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में या उनकी बाबत जो सरकार ने उपगत किए हों क्षतिपूर्ति करेगा और उसे क्षतिपूरित तथा हानिरहित बनाए रखेगा।

9. (क) अनुज्ञप्तिधारी इसमें इसके पश्चात् उपबंधित नियंत्रणों और शर्तों पर नकद में, बैंक निक्षेप, सरकारी प्रतिभूतियों, किसी बैंकर के प्रत्याभूति बंधपत्र, बीमा कम्पनी के बंधपत्र के रूप में . . . रु० की राशि का प्रतिभूति निक्षेप रेल के पास रखेगा।

प्रतिभूति निक्षेप की रकम उन सभी टिकटों की बाबत, जो इसके अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किए जाएं, एक मास के सव्यवहार के कुल मूल्य के आधार पर, समय समय पर बढ़ाई जा सकेगी।

(ख) सरकार द्वारा मांगी गई कोई अतिरिक्त प्रतिभूति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रकम की जाने की तारीख से 14 दिन से अनधिक की अवधि के भीतर नकद या बीमा कम्पनी के प्रत्याभूत बंधपत्र को छोड़कर प्रतिभूति निक्षेप के स्वीकृत तरीकों में से किसी में दी जाएगी।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सरकार को देय किसी रकम के सदाय लेखे, जिसमें शास्तियां भी सम्मिलित है, समायोजित किया जा सकेगा या प्राप्त किया जा सकेगा और जहां ऐसा किया जाता है वहां अनुज्ञप्तिधारी को, सरकार के विवेकानुसार, विक्रय आरम्भ करने के लिए सभी अनुज्ञान किया जा सकेंगे जब अनुज्ञप्तिधारी ने अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप की सपूर्ण रकम के बराबर और प्रतिभूति निक्षेप दे दिया हो तथा भविष्य के लिए उपयुक्त प्रत्याभूतियां दे दी हों। सरकार प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का सदाय करने के लिए दायी नहीं होगी।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त किया जाने वाला प्रतिभूति निक्षेप निम्नलिखित एक या अधिक रूपों में होगा :—

क. नकद

ख. सरकारी प्रतिभूतियां

सरकारी प्रतिभूतियां उनके बाजार मूल्य से 5 प्रतिशत कम में स्वीकार की जाएंगी।

ग निक्षेप

(i) भारतीय स्टेट बैंक की जमा रसीदें

(ii) डाकघर बचत बैंक में निक्षेप, और

(iii) डाक या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में निक्षेप

घ. बैंक गारंटी

अनुसूचित बैंकों से विहित प्रारूप में बैंक गारंटी

ङ बीमा कम्पनी की प्रत्याभूति

किसी राष्ट्रीयकृत कम्पनी से उपबंधित विहित प्रारूप में बीमा कम्पनी की प्रत्याभूति किन्तु सरकार से यह बताने के लिए कहा जाएगा कि प्रतिभूति निक्षेप का कितना भाग बीमा कम्पनी की प्रत्याभूति के रूप में होगा और कितना भाग किसी अन्य रूप में होगा।

(ङ) प्रतिभूति निक्षेप का, टिकटों के विक्रय आगमों, शक्तियों के रूप में या अन्यथा, जो कुछ भी हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सरकार को देय सभी रकमों का उगमे से विनियोजन करने या वसूल करने के पश्चात् प्रतिदाय किया जाएगा और लेखाओं का समायोजन किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस संबंध में सरकार को देय रकम के बारे में सरकार का विनिश्चय अंतिम और अनुज्ञप्तिधारी पर आबद्धकर होगा।

10 अनुज्ञप्तिधारी कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए रेल बुकिंग से संबंधित सभी अभिलेखों का परिरक्षित रखेगा। किन्तु जहां किसी भी कारण से सरकार द्वारा अभिलेखों का और अधिक अवधि के लिए रखा जाना अपेक्षित हो वहां अनुज्ञप्तिधारी उन्हें ऐसी अवधि के लिए परिरक्षित रखेगा जो सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

11 अनुज्ञप्तिधारी . . . . . रेल के कूपन टिकटों और विशेष या अन्य टिकटों के वास्तविक रूप से जारी किए जाने के पूर्व . . . . . रेल के उपमुख्य लेखा अधिकारी (यातायात लेखा) को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें स्टाक में रखे टिकटों की वास्तविक संख्या दर्शित होगी। अनुज्ञप्तिधारी प्रतिवर्ष 31 मार्च और 30 सितम्बर के पश्चात् 15 दिन के भीतर ऐसा विवरण भी देगा जिसमें 31 मार्च तथा 30 सितम्बर को समाप्त होने वाले प्रत्येक अर्ध वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न वर्गों के कूपन टिकटों और विशेष टिकटों की संख्या तथा चालू शृंखला दर्शित होगी।

12. अनुज्ञप्तिधारी को इस करार के अधीन या अनुसरण में किसी व्यक्ति से प्राप्त सभी धन उसके द्वारा सरकार के न्यासी के रूप में रखा जाएगा और वह इसके खण्ड 6 के अधीन रहते हुए, ऐसा धन सरकार को तुरन्त और नियमित रूप से भेजेगा।

13. यदि अनुज्ञप्तिधारी नियत तारीख को कोई प्रेषण करने में असफल रहता है या नियत तारीखों को लेखा तथा जारी की गई टिकटों और स्टाक की विशिष्टियां दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है या इस करार अथवा इससे उपाबद्ध अनुसूचियों के निबंधनों और शर्तों में से किसी एक का भंग करता है तो सरकार किन्हीं अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किन्तु उसके अतिरिक्त इसके अधीन किन्हीं टिकटों आदि का विक्रय तुरन्त बन्द करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को कहने और तालिका बनाने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के पास रखे टिकटों आदि के स्टाक का अभिग्रहण करने की हकदार होगी। सरकार करार को तुरन्त पर्यवसित करने की भी हकदार होगी। पर्यवसान पर, ऐसी संपूर्ण रकम, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सरकार को संदेय हो सके, तुरन्त संदेय हो जाएगी और अनुज्ञप्तिधारी ऐसी रकम का तुरन्त संदाय करेगा। इस बारे में कि अनुज्ञप्तिधारी ने कोई भंग किया है या नहीं, सरकार या उसके ...... रेल के प्राधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय अन्तिम और अनुज्ञप्तिधारी पर आबद्धकर होगा।

14. अनुज्ञप्तिधारी रेल आरक्षण कार्यालयों से सीधे अपने व्यवहारियों की ओर से सभी श्रेणियों के लिए टिकट खरीदने और शायिकाओं/सीटों का आरक्षण प्राप्त करने के लिए भी प्राधिकृत होगा। किन्तु यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी की होगी कि उसका कोई भी कर्मचारी शायिकाओं/सीटों के एकाधिकारात्मक क्रय करने या अप्राधिकृत अंतरण करने में लगे या उस पर लगने का संदेह न हो। ऐसा करने में असफल रहने पर सरकार इस करार का तुरन्त पर्यवसित करने की हकदार होगी। यदि इस करार के चालू रहने के दौरान भारत सरकार का पर्यटन विभाग अनुज्ञप्तिधारी की मान्यता प्रदान करना बन्द कर देता है तो भी सरकार इस करार को पर्यवसित करने की हकदार होगी। इन दशाओं में से किसी के भी संबंध में सरकार का विनिश्चय अंतिम और अनुज्ञप्तिधारी पर आबद्धकर होगा। अनुज्ञप्तिधारी सरकार को शोध्य और संदेय संपूर्ण रकम का संदाय तुरन्त करने का दायी होगा मानो यह करार इसके पूर्वगामी खण्ड 13 के अधीन पर्यवसित किया गया है।

15. इस करार के अधीन या विधि में सरकार के किन्हीं अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना सरकार को अपने पूर्ण विवेकानुसार अनुज्ञप्तिधारी पर अनियमित या विलंब से प्रेषणों या विक्रय विवरण प्रस्तुत करने में विलम्ब या किसी अन्य अनियमितता के लिए एक ही समय में .... रु० से अनधिक की परिनिर्धारित नुकसानी अधिरोपित करने का हक होगा और अनुज्ञप्तिधारी ऐसी रकम का संदाय तुरन्त करेगा।

16. यह करार, इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए .... से प्रवृत्त होगा और .... को पर्यवसित हो जाएगा। परन्तु कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को जिससे लेखा समायोजित किया जाएगा, तीन मास की सूचना देकर करार को पर्यवसित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. इसके पक्षकारों के अपने अपने अधिकारों और बाध्यताओं के बारे में और इन विलेखों या उसके किन्हीं अनुच्छेदों या शर्तों के सही आशय और अर्थान्वयन के बारे में सरकार और अनुज्ञप्तिधारी के बीच मतभेद होने की दशा में ऐसा मतभेद महाप्रबन्धक द्वारा तत्समय नियुक्त किसी अधिकारी के एकमात्र माध्यस्थम् को निर्देशित किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम, निश्चायक और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

18. इस संविदा में यथाअन्यथा उपबन्धित के अधीन रहते हुए, भारत के राष्ट्रपति की ओर से की जाने वाली सभी सूचनाएं और उनकी ओर से की जाने वाली सभी अन्य कार्यवाइयां मुख्य ...... अधीक्षक ...... अधीक्षक, ... रेल या सरकार नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा उसी प्रकार दी या की जा सकेंगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप .... रेल के .... ने भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से और उक्त ...... के .... ने ऊपर लिखी तारीख को उस पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

————	भारत के राष्ट्रपति के लिए और
————	उनकी ओर से
————रेल के	हस्ताक्षर और पदनाम
हस्ताक्षर का साक्षी	————रेल
अनुज्ञप्तिधारी के	अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर
हस्ताक्षर का साक्षी	

अनुसूची 1

विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट

अनुज्ञप्तिधारी को विदेशी राष्ट्रिकों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत सरकार की रेलों में यात्रा के लिए सभी वर्गों में स्थान देने के लिए निम्नलिखित वर्णन के टिकटों का स्टाक रखने और उन्हें जारी करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है :—

(क) एकल यात्रा विदेशी पर्यटक कूपन टिकट

(ख) आरक्षित सवारी डिब्बा, पर्यटन यानों और विशेष रेलगाड़ियों को बुक करने लिए के विशेष टिकट

(ग) इन्ड-रेल पास टिकट

2. अनुज्ञप्तिधारी ऊपर वर्णित टिकट उस समय भी जारी कर सकता है जब यात्राएं उस स्थान से जहां से अनुज्ञप्तिधारी इन टिकटों को जारी करने के लिए प्राधिकृत है, भिन्न स्थानों से आरम्भ/समाप्त होती है।

3. साथ में यात्रा कर रहे वातानुकूलित और प्रथम श्रेणी टिकट-धारक भारत के निवासियों को अनुसूची 2 में उपदर्शित निबन्धनों और शर्तों पर द्वितीय श्रेणी के लिए परिचर टिकट जारी किए जा सकते है।

टिप्पण—एक ही रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे पर्यटकों के दलों के साथ कंडक्टरों को निम्नलिखित मापमान के अनुसार निःशुल्क यात्रा के लिए अनुज्ञात किया जाता है :

6—35 पर्यटकों के दलों के साथ	एक कन्डक्टर
36—59 पर्यटकों के दलों के साथ	दो कंडक्टर
59 से अधिक पर्यटकों के दलों के साथ	तीन कंडक्टर

4. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किए गए टिकट पर प्रतिदाय का ठहराव करते समय भाड़े का कोई प्रतिशत प्रतिधारित किया जाता है तो इस प्रकार प्रतिधारित प्रतिशत विद्यमान नियमों के अनुसार प्रतिदाय को प्राधिकृत करने वाली रेल को भेजा जाएगा, वातानुकूलित और प्रथम श्रेणी के टिकटों के रद्दकरण प्रभार का 50 प्रतिशत रखने वाला अनुज्ञप्तिधारी रद्दकरण प्रभारों के अपने अंश के लिए प्रति टिकट अधिकतम 2 रु० रखेगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी किसी बिचौलिये को इस करार के अधीन टिकटों के विक्रय द्वारा उसको अभिप्राप्त आरक्षित सवारी डिब्बों, पर्यटक यानों या विशेष रेलगाड़ियों या किसी स्थान को पुनः आबंटित नहीं करेगा।

इस शर्त का कोई उल्लंघन, करार के खण्ड 13 और 14 के प्रयोजन के लिए, करार के निबन्धनों का भंग माना जाएगा।

6. इन्डरेल पास टिकट अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तभी स्टाक किए और जारी किए जा सकते है जबकि उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त निर्बन्धित मुद्रा-परिवर्तक अनुज्ञप्ति (रेस्ट्रिक्टेड मनीचेन्जर्स लाइसेंस) हो। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन टिकटों के लिए भुगतान सपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा (करेंसी) में ही स्वीकार किया जा सकेगा है। (ऐसी क्षेत्रीय रेलें जो इन्डरेल पास टिकट का स्टाक नहीं कर रही है, पूर्वोक्त खंड काट देंगी)।

7 कमीशन.

(क) सरकार अनुज्ञप्तिधारी को इस अनुसूची में उल्लिखित सभी टिकटों के लिए 10 प्रतिशत कमीशन देगी। किन्तु निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई कमीशन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :—

(i) भाड़े में सम्मिलित तीर्थ-यात्री, नगरपालिक या अन्य कर।

(ii) आरक्षण टिकट।

(iii) रेल और रोड टिकटों पर रेल भाड़ा।

(iv) ऐसे टिकट जिन पर रेल प्रशासन द्वारा पूर्ण प्रतिहाय अनुज्ञात किया जाता है।

अनुसूची 2

भारत में निवासियों को टिकट

1. अनुज्ञप्तिधारी को भारत सरकार की रेलों में यात्रा करने के लिए भारत में निवासियों को निम्नलिखित प्रकार के टिकटों का स्टाक करने और जारी करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है :

टिकटों का वर्णन	स्थान की श्रेणी जिसके लिए टिकट जारी किया जा सकेगा
(क) सरकार द्वारा अनुमोदित मानक प्रारूपों में कूपन टिकट	वातानुकूलित और प्रथम श्रेणी
(i) स्टीमरों या वायुयानों के सम्बन्ध में, समुद्र पत्तनों या विमानपत्तनों को या से	
(ii) देश के अंदर विमान यात्रा के सम्बंध में	
(ख) मुद्रित कार्ड टिकट, जो रेल स्टेशनों द्वारा जारी किए गए टिकटों के समरूप है	वातानुकूलित श्रेणी और प्रथम श्रेणी
(ग) इकहरी और वापसी यात्रा पेपर टिकट जो रेल स्टेशनों द्वारा जारी पेपर टिकटों के समरूप है।	वातानुकूलित श्रेणी और प्रथम श्रेणी
(घ) रेल द्वारा जारी किए गए रियायती आदेशों के बदले में टिकट	प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी
(ङ) आरक्षित सवारी डिब्बों, पर्यटक यानों और विशेष रेल गाड़ियों के लिए विशेष टिकट	वातानुकूलित श्रेणी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी
(च) परिक्रमा पर्यटन टिकट	प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी
(छ) परिचर टिकट	द्वितीय श्रेणी

परिचर टिकटें, वातानुकूलित श्रेणी और प्रथम श्रेणी के यात्रियों के वास्तविक परिचरों के लिए ही है।

टिप्पण—एक ही रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे पर्यटन दलों के साथ कंडक्टरों को निम्नलिखित मान के अनुसार निःशुल्क यात्रा के लिए अनुज्ञात किया जाता है.—

6—35 के दलों के साथ	एक कंडक्टर
36—59 के दलों के साथ	दो कंडक्टर
59 से अधिक के दलों के साथ	तीन कंडक्टर

2 अनुज्ञप्तिधारी इसमें जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, टिकट जारी करने के स्थान से आरम्भ होने वाली यात्राओं के लिए ही टिकट जारी कर सकते है। किन्तु ऊपर खंड 1 (ङ) और (च) में वर्णित टिकटों के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारी टिकट उस समय भी जारी कर सकता है जब कि यात्राएं उस स्थान से, जहां से अनुज्ञप्तिधारी टिकटों को जारी करने के लिए प्राधिकृत है, भिन्न स्थानों से आरम्भ होती हो।

3. अनुज्ञप्तिधारी ऊपर खंड 1(ख), (ग) और (घ) के अधीन जारी किए गए टिकटों पर 1 प्रतिशत से अनधिक सेवा प्रभार उद्ग्रहीत कर सकेगा और सेवा प्रभार के प्रति संग्रहीत रकम के लिए यात्रियों को एक पृथक रसीद जारी करेगा। किन्तु इस प्रकार संग्रहीत रकम पार्टी को जारी की गई टिकट में दर्ज नहीं की जानी चाहिए।

4. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किए गए टिकट पर प्रतिहाय का ठहराव करते समय भाड़े का कोई प्रतिशत प्रतिधारित किया जाता है तो इस प्रकार प्रतिधारित प्रतिशत विद्यमान नियमों के अनुसार प्रतिहाय को प्राधिकृत करने वाली रेल को भेजा जाएगा, अन्तर्नुकूलित और प्रथम श्रेणी के टिकटों के रद्दकरण प्रभार का 50 प्रतिशत रखने वाला अनुज्ञप्तिधारी रद्दकरण प्रभारों के अपने अंश के लिए प्रति टिकट अधिकतम 2 रु० रखेगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी किसी बिचौलिये को इस करार के अधीन टिकटों के विक्रय द्वारा उसको अभिप्राप्त आरक्षित सवारी डिब्बों, पर्यटक यानों या विशेष रेल गाड़ियों या किसी स्थान को पुनः आवंटित नहीं करेगा।

इस शर्त का कोई उल्लंघन, करार के खंड 14 और 15 के प्रयोजन के लिए करार के निबन्धनों का भंग माना जाएगा।

6. कार्ड, पेपर या विशेष टिकटों के विक्रय के लिए कमीशन की दरें खंड 1(क), (ख) और (ग) के अधीन जारी किए गए टिकटों के लिए 3 प्रतिशत और खंड 1(ङ) और (च) के लिए 50 प्रतिशत होगी। खंड 1(च) और (छ) के अधीन जारी किए गए टिकटों के लिए या निम्नलिखित के लिए कोई कमीशन देय नहीं होगा :—

(i) आरक्षण टिकट

(ii) भाड़े में सम्मिलित किए गए तीर्थयात्रा, नगरपालिक और अन्य कर

(iii) रेल और रोड टिकटों पर रोड भाड़ा।

(iv) ऐसे टिकट जिन पर रेल प्रशासन द्वारा पूर्ण प्रतिहाय अनुज्ञात किया जाता है।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 29th December, 1980

S.O. 113.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of secton 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules for regulating the method of appointment of Railway Tourist Agents namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Appointment of Railway Tourist Agent Rules, 1980 and

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these Rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Person" includes a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932, a company incorporated under the Companies Act, 1956 and a company incorporated in a country outside India and having its branch office in India.

(b) "Government" means the Central Government of India.

(c) Words and terms not defined in these Rules shall have the same meaning as assigned to them in the Indian Railways Act, 1890.

3. Conditions for appointment as a Railway Tourist Agent.—A person applying for appointment as a Tourist Agent on Railways must satisfy the following conditions/requirements, namely (1) should possess a trade licence from the competent authority to carry on the business of a tourist agent in India; (2) must be financially sound and should possess the latest Income Tax Clearance Certificate from the Income Tax authority in India. The person having a minimum paid up capital of not less than Rupees one lakh shall be deemed to be financially sound; (3) should have obtained recognition to act as a travel agent from the Government; (4) should have been carrying out the business of a travel agent for a minimum period of one year; (5) should possess a Money Changer's licence from a competent authority to deal with/handle the foreign exchange in India; (6) must have an office and the premises properly maintained with adequate conveniences at a central place in the city so as to accommodate the visit of sufficient number of customers and to provide them with the reasonable conveniences

4. Authority to whom the application for appointment be submitted.—An application for appointment as a Tourist Agent on Railways shall be addressed and made to the General Manager (Commercial) of the concerned Railway duly supported by the evidence that the person concerned satisfies and fulfils the conditions/requirements of eligibility as laid down in rule 3.

5. Right of the Railway Administration to refuse permission to act as a tourist agent on Railways.—The Railway Administration shall have the right to reject any application of a person for the aforesaid appointment if he does not satisfy or fulfil all or any of the conditions of eligibility after giving him an opportunity to produce evidence to its satisfaction. The Railway Administration shall have the absolute right not to accord permission to a person to act as a tourist agent, if in its opinion, the person is not a proper or a fit person to act as a tourist agent on the Railways for any reason to be briefly communicated to him.

The Railway Administration shall also have the right to cancel or revoke or withdraw at any time the permission granted earlier after giving a show cause notice. The Railway Administration shall not be responsible for any loss/damage suffered or to be suffered by or caused or to be caused to the tourist agent as a result of the cancellation, revokation or the permission to act as a tourist agent on the Railways.

6. Execution of the Agreement by the tourist agent with the Railway Administration.—A person who is appointed as a tourist agent on the Railways shall have to execute with the Railway Administration an agreement on the Form-A The stamp duty and other costs for executing the agreement shall be borne and paid for by a tourist agent.

7 Maintenance of the office of a tourist agent by competent and trained staff.—the tourist agent shall appoint competent and sufficiently trained staff in his office in connection with the conduct of the business of a tourist agency, who shall inter alia be well conversant with the working of the railway and should be able to give an up-to-date and an accurate information with regard to the availability of accommodation facility on the trains to the customers

8. Settlement of disputes, differences arising out of and in connection with the agreement between the Railway Administration and the tourist agent.—Any dispute, difference etc., arising out of and/or in connection with the agreement between the Railway Administration and the tourist agent shall be decided by a sole arbitrator to be appointed by the General Manager The award of the arbitrator shall be final and binding on the parties. The arbitration proceedings shall be governed by the provisions of the Arbitration Act, 1940, the rules and/or order made thereunder as are in force from time to time. The venue of arbitration shall be such as is fixed by the arbitrator. Notwithstanding any dispute referred to arbitration, the parties shall, if it is otherwise possible, continue to discharge their obligations under the agreement.

9 Security deposit by a tourist agent.—A tourist agent shall deposit and maintain a security deposit of such amount as may be fixed within the period stipulated for the purpose by the Railway Administration from time to time for due fulfilment of the provisions of the agreement and his obligation under the agreement as a tourist agent, The security deposit shall be liable to be forfeited in the event of the breach of any of the conditions of the agreement.

10. Right of the ailway Administration to inspect the premises/office of the tourist agent—The Railway Administration shall have the right to inspect the office and/or the premises of a tourist agent at any time during the business hours of the tourist agent and for this purpose it shall be open to the Railway Administration to depute its officers as well as any other person as it deems fit and proper.

[No. TCII/2895/78/Rules]

K. BALACHANDRAN, Secy.

Railway Board and ex-officio Jt. Secy.

FORM—A (Rule-6)

SPECIMEN FORM OF AGREEMENT TO BE EXECUTED BY THE TOURIST AGENTS WITH RAILWAYS

AN AGREEMENT made on the ... ...

19 between Messrs ... . hereinafter called the Licensee, which expression shall include their successors and assignees of the one part and the President of India, hereinafter called the Government acting through Chief————— Superintendent, ———— Railway—which expression shall include his successors and assignees of the other part.

Whereas the licensee has been appointed as Tourist Agent of the Government for sale of Railway Tickets mentioned in the attached schedule(s) as herein provided.

It is now hereby Agreed By and Between The Licensee And The Government as follows :—

1. The Government hereby appoints the Licensee as Tourist Agent of the Government for sale of Railway tickets on the terms and conditions contained herein and the schedule hereto which shall form part of this agreement. The Licensee undertakes to issue all or any of the tickets mentioned in the schedules, on the conditions and rules specified therein and further subject to the rules relating to them notified from time to time in the Indian Railway Conference Association Coaching Tariff and other publications or instructions of the Railway.

2. The Licensee shall issue the tickets mentioned in the attached schedules only from their offices at the following places and not from any other place :

1	4
2	5
3	6

3. The coupon, special and other tickets to be sold by the Licensee shall be in the form, colour etc. prescribed from time to time by the railway administration and shall be provided by the Government at the cost of the licensee. Indenting of such tickets will be done by the licensee according to the procedure prescribed by......... ....Railway from time to time.

4. Books and forms in force at Railway stations shall be used for the maintenance of accounts in relation to stock and sale of tickets by the licensee. Such books and forms will be supplied by the Government to the licensee free of cost.

5. The licensee shall not issue a ticket for less or more than current fare prescribed by the Railway for each class

and the licensee shall show on each ticket the amount of the fare charge for the same.

6. For the purpose of the adjustments of accounts, the licensee shall submit to the Deputy Chief Accounts Officer (Traffic Accounts) of the..... ...Railway within five working days after the close of each bi-monthly period an account or statement showing particulars of tickets issued during the period. It shall be the responsibility of the licensee to ensure that the remittances are received in the prescribed Railway offices regularly on the specified dates. Discrepancies and items in dispute shall be adjusted after the statements have been checked.

If there be no traffic during any 15 days period, a nil statement showing the closing number of tickets on hand will be sent to the Dy. Chief Accounts Officer (TA) of the————————Railway.

7. For the purpose of checking and inspection, the offices of the licensee are liable to be inspected by the representatives of the Accounts/Commercial Departments and the Statutory Audit or such other representatives of the Government at such intervals as the Government may decide. The licensee shall undertake to provide all facilities and permit full access to all relevant records and render all necessary assistance for their check and inspection as may be required by such representatives. The licensee shall maintain at his own cost and expense his agency office for sale of tickets etc. to tourists as may be required by the railway administration.

8 The licensee shall be entirely and wholly responsible for all losses or damages that may be suffered by the Government by any act or omission of the licensee or his servants or agents and shall indemnify and keep indemnified and harmless the Government against or in respect of all such losses or damages or costs, if any, incurred by the Government in regard thereto.

9. (a) The licensee shall maintain with the..... ..... Railway a security deposit on the terms and conditions hereinafter provided in cash, bank deposit, Government securities, a banker's guarantee bond, insurance company's guarantee bond of the sum of Rupees————————The amount of the security deposit may be increased from time to time on the basis of total value of one months transactions in respect of all tickets which may be issued by the licensee hereunder.

(b) Any additional security demanded by the Government shall be furnished by the licensee within a period of not exceeding 14 days from the date of demand in cash or in one of the accepted modes of security deposit other than insurance company's guarantee bond.

(c) The security deposit is liable to be adjusted or realised towards payment of any amount due to the Government by the licensee including penalties and where this is done the licensee may, at the discretion of the Government, be allowed to commence sales only after the licensee has provided further security deposit equal to the entire amount of security deposit required and on giving suitable guarantees for the future. The Government shall not be liable to pay interest on the security deposit.

(d) The security deposit to be received from the licensee shall be in one or more of the following forms :—

A. Cash.

B. Government Securities

Government securities to be accepted at 5 per cent below the market value.

C. Deposits

(i) Deposit receipts of State Bank of India.

(ii) Deposits in the Post Office Savings Bank, and

(iii) Deposits in Postal or National Savings Certificates.

D. Bank Guarantee.

Bank guarantee from scheduled banks in the prescribed form.

E. Insurance Company's Guarantee.

Insurance company's guarantee from any nationalised company in the prescribed form provided, however, the Government would be called to stipulate what portion of the security deposit may be in the form of Insurance company's guarantee and what portion in any other form.

(e) The security deposit shall be refunded after appropriating or realising therefrom all amounts due by the licensee to the Government either as sale proceeds of tickets, penalties or otherwise howsoever and accounts adjusted The decision of the Government as to the amount due to the Government by the licensee on this account shall be final and binding on the licensee.

10. The licensee shall preserve all records connected with the railway booking for a period not less than 5 years. Where, however, the records are required to be kept for a longer period by the Government for any reason whatsoever, the licensee shall preserve them for such period as is required by the Government.

11. Before actual commencement of the issue of coupon tickets and special or other tickets of the..... .....Railway, the licensee will submit to the Deputy Chief Accounts Officer (T.A.) of the. .. ..Railway a statement showing the actual number of tickets kept in stock. The licensee will also furnish within 15 days after the 31st March and 30th September each year a statement showing the number of coupon tickets and special tickets of different classes and series in hand at the end of each half year ending 31st March and 30th September.

12 All money received by the licensee from any person under or in pursuance of this agreement shall be held by the licensee as trustee for the Government and shall remit such money to the Government promptly and regularly, subject to clause 6 hereof.

13 If the licensee fails to make any remittances on the due date or fails to submit the accounts and statement showing particulars of tickets issued and the stock on the due dates or commits a breach of any of the terms and conditions of this agreement or of the schedules hereto annexed, the Government shall, without prejudice to any other rights but in addition thereto, be entitled to call upon the licensee to forthwith stop the sale of any tickets etc. hereunder and to seize after making an inventory, the stock of tickets etc. lying with the licensee. The Government shall also be entitled to terminate the agreement forthwith. On termination, the entire amount that may be payable by the licensee to the Government shall become payable forthwith, and the licensee shall forthwith pay such amount. The decision of the Government or its authorised officer of. . .. ... .Railway as to whether the licensee has committed any breach or not shall be final and binding on the licensee.

14. The licensee shall also be authorised to buy tickets and obtain reservations of berths/seats for all classes on behalf of its clients directly from railway reservation offices. However, it will be the responsibility of the licensee to enable that none of its employee indulges or is suspected of indulging in cornering or unauthorised transfer of berths/seats. Failure to do so shall entitle the Government to terminate this agreement forthwith. The Government will also be entitled to terminate this agreement if recognition of licensee by Department of Tourism, Government of India is discontinued during the currency of this agreement. The decision of the Government in regard to either of the events shall be final and binding on the licensee who shall be liable to pay to the Government forthwith the entire amount due and payable to it as if this agreement has been terminated under the foregoing clause 13 hereof.

15 Without prejudice to any other rights and remedies of the Government under this agreement or in law, the Government shall have the right to impose at its sole discretion liquidated damages on the licensee not exceeding Rs..... at time for irregular or delayed remittances or delays in submission of sales statements or any other irregularity and the licensee shall forthwith pay such amount.

16. This agreement shall, subject to the provisions herein contained, remain in force on and from............and terminate on. .... provided that either party shall be at liberty to terminate the same by giving three months' notice to the other wherefrom the accounts shall be adjusted.

17. In the event of any difference of opinion between the Government and the Licensee as to the respective rights and obligations of the parties hereunder or as to the true intent and meaning of these presents or any articles or conditions thereof such difference of opinion shall be referred to the sole arbitration of an officer appointed by the General Manager for the time being whose decision shall be final, conclusive and binding on the parties.

18. Subject as otherwise provided in this contract, all notices to be given on behalf of the President of India and all other actions to be taken on his behalf may be so given or taken by the Chief............ ..Supdt.,............ Railway or any other officer appointed by the Government.

In witness whereof...............of the ... ...Railway for and on behalf of the President of India and.............. of the said..........have hereunto set their hands the day and year above written.

Witness to the Signature of the	For and on behalf of the President of India
————————	
————————	Signature & Designation
————Railway.	
	————Railway.
Witness to the Signature of the Licensee.	Signature of the Licensee

SCHEDULE I

Tickets to Foreign Tourists

The licensee is allowed to stock and issue to foreign nationals and Indians residing abroad the following descriptions of teikets for all classes of accommodation for journeys over Indian Government Railways :—

(a) Single journey overseas tourist coupon tickets.

(b) Special tickets for booking of reserved carriages, tourist cars and special trains.

(c) Indrail Pass tickets.

2 The licensee can issue the above mentioned tickets even when the journeys originate/terminate from places other than the place from which the licensee is authorised to issue these tickets.

3. Residents of India accompanying holders of Air-conditioned and First Class tickets may be issued attendant tickets for Second Class on the terms and conditions indicated in Schedule II.

Note : Conductors with parties of tourists travelling by the same train are allowed to travel free according to the following scale :—

With parties of 6-35	One conductor
With parties of 36-59	Two conductors
With parties of over 59	Three conductors

4. In case a percentage of fare is retained when arranging refund on a ticket issued by the Licensee the percentage so retained as per extent rules shall be remitted to the Railway authorising the refind, the licensee retaining 50% of the cancellation charges of Airconditioned and First class tickets subject to a maximum of Rs. 2 per ticket towards his share of cancellation charges

5. The licensee shall not re-allot to middlemen reserved carriages, tourist cars or special trains or any accommodation obtained by him by the sale of tickets under this agreement. Infringement of this condition shall be deemed a breach of the terms of the agreement for the purpose of Clauses 14 and 15 of the agreement.

6. Indrail Pass tickets can be stocked and issued by the licensee only if he holds Restricted Money Changer's License from Reserve Bank of India. Payment for these tickets can be accepted by the licensee only in a convertible foreign currency. (Zonal Railways which are not stocking Indrail Pass tickets shall delete the aforesaid clause).

7. Commission:—(a) The Government will allow the licensee 10% commission for all the tickets mentioned in this schedule No commission will, however, be allowed in regard to the following :—

(i) Pilgrim, Municipal or other taxes included in the fare.

(ii) Reservation tickets.

(iii) Road fare on rail-cum-road tickets

(iv) Tickets on which refund are allowed in full by the Railway Administration.

SCHEDULE II

Tickets to Residents in India

1. The licensee is allowed to stock and issue the following types of tickets to residents in India for journeys over Indian Government Railways : –

Description of tickets	Class of accommodation for which the tickets may be issued
1	2
(a) Coupon tickets in the standard forms approved by the Government.	Air-conditioned and First class.
(i) To or from seaports or Air-ports, in connection with steamers or aeroplanes;	
(ii) in connection with air travel within the country.	
(b) Printed Card tickets, similar to those issued by Railway station.	Air-conditioned Class & First Class.
(c) Single & return journey paper tickets similar to those issued by Railway stations.	Air-conditioned Class and First Class.
(d) Tickets in exchange for concessional orders issued by Railways.	First Class and Second Class.
(e) Special tickets for reserved carriages, tourists cars and special trains.	Air-conditioned Class, First Class and Second Class.
(f) Circular tour tickets	First Class and Second Class.
(g) Attendant tickets	Second Class

The Attendants tickets are for bonafide attendants of the holders of Air-conditioned class and First Class passengers only.

Note: —Conductors with parties of tourists travelling by the same train are allowed to travel free according to the following scale :—

With parties of 6 35	One conductor
With parties of 36–59	Two conductors
With parties of over 59	Three conductors.

2. the licensee can issue tickets only for journeys commencing from the place of tickets, unless otherwise provided therein. In respect of tickets mentioned in clause 1(e) and (f.) above, however, the licencesee can issue tickets even if the journey originates from a place other than the place from which the licensee is authorised to issue tickets.

3 The licensee may, levy a Service charge not exceeding 1% on the tickets issued under Clause 1(b), (c) and (d) above and shall issue a separate receipt to the passengers for the amount collected towards service charge. The amount so collected should not, however, be entered in the tickets issued to the party

4. In case a percentage of fare is retained when arranging refund on a ticket issued by the licensee, a percentage so retained as per extent rules shall be remitted to the Railway authorising the refund, the licensee retaining 50% of the cancellation charges of Air-conditioned and First Class tickets subject to a maximum of Rs. 2/- per ticket towards his share of cancellation charges.

5. The licensee shall not re-allot to middlemen reserved carriages, tourist cars, or special trains or any accommodation obtained by him by the sale of tickets under this agreement. Infringement of this condition shall be deemed a breach of the terms of the Agreement for purposes of Clauses 14 & 15 of the agreement.

6. The rates of commission for the sale of card, paper or special tickets shall be 3% for tickets issued under Clause 1(a), (b) and (c) and 5% for clauses 1(e) and (f). No commission will be payable for tickets issued under clause 1(d) and (g) or for the following :—

(i) Reservation tickets.
(ii) Pilgrim, Municipal or other taxes included in the fare.
(iii) Road fare on rail-cum-road tickets
(iv) Tickets on which refunds are allowed in full by the Railway Administration.

ORDER

New Delhi, the 5th February, 1980

S.O. 114.—Whereas an Industrial Dispute exists between the management of Sripur Area of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Sripur, Dist. Burdwan and their workman represented by Koyala Mazdoor Congress (HMS), Gorai Mansions, G.T. Road, Asansol ;

And whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under Sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to a Central Government a copy of the said arbitration agreement ;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of Section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement which was received by it on the 19th January, 1980.

ANNEXURE 'A'

AGREEMENT

Under section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947.

BETWEEN

Name of Parties :

Representing the Employer—1. Sri B. M. Mukherjee, General Manager, Sripur Area, M/s Eastern Coalfields Ltd. P.O. Sripur (Burdwan).

2. Sri K. L. Bose, Agent, Girimint Colliery P.O. Charanpur (Burdwan).

Representing the Workmen.—1. Sri Shiv Kant Pandey, Secretary, Koyala Mazdoor Congress (HMS) Gorai Mansions, G.T. Road, Asansol.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Sri A. B Shah, Director (Technical) M/s. Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, P.O. Dishergarh, Distt Burdwan

(i) Specific matters in dispute .

"Whether the claims of underground loaders of Pit Nos. 2 and 3 of Girimint Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd that the mine cars used by the management are of higher cubical contents than 144 cft. for which wages are paid at present and workmen's contention that they have to load more coal in terms of 40.5 cft. Units is justified ? If not,, to what relief the workmen are entitled ? To and from what date?".

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the Establishment or undertaking involved :

(1) Girimint Colliery under Sripur Area of M/s. Eastern Coalfields Ltd. P.O. Charanpur (Burdwan).

(2) The General Secretary, Koyala Mazdoor Congress (HMS) Gorai Mansions, G.T. Road, Asansol.

(iii) Total No. of workmen employed in the undertaking affected Approximately 2400.

(iv) Estimated No of workmen affected or likely to be affected by the dispute :

About 514

The arbitrator shall make his award within a period of one hundred and twenty days or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing, from the date of publication of this Agreement in the Gazette of the Government of India.

Sd/-
(B. M. MUKHERJEE)
(K. L. Bose)
(Representing the Employer)

Sd/-

(SHIV KANT PANDEY)

(Representing the Workmen)

WITNESSES :

1. Sd/-
2 Sd/ – 2-1-80

Dated the 2-1-1980

I agree

Sd/

A. B. SHAH, Director (Technical)

M/s Eastern Coalfields Ltd, Sanctoria

[No. L-19011(8)/78-D. IV(B)]

SHASHI BHUSAN, Desk Officer

ANNEXURE 'B'

ARBITRATION PROCEEDING

Proceeding of 11th March, 1980

From the Workmen side Shiv Kant Pandey is present From the Management side Shri K. L Bose, Agent is present.

The worker's representative also presented Shri Ramchij Koeri and Shri Bikha Ram underground loaders of Girimint Colliery as their witnesses Then statements as well as cross examination done by Shri K. L. Bose, Agent are typed in separate sheets and duly thumb impressioned by LTI of both Shri Ramchij Koeri and Shri Bikha Ram on their respective statements and cross examination are enclosed. It was decided that both parties will submit their written statement to Arbitrator and will simultaneously give one copy to each other parties and thereafter both parties may submit rejoinder and will similarly simultaneously give one copy to each other parties. It was also agreed that the parties will give their evidence in support of their case and thereafter

site inspection will be done if necessary. Thereafter after hearing the parties the Arbitrator will give his Award

A. B SHAH, Arbitrator

K. L. BOSE, Agent.

SHIV KANT PANDAY, Secretary.

ANNEXURE 'C'

Arbitration under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 arising out of a dispute between the management of Sripur Area of M/s. Eastern Coalfields Limited, P.O. Kalipahari, Dist. Burdwan and their workmen represented by Koyala Mazdoor Congress (HMS), Gorai Mansions G.T. Road, Asansol.

Recorded evidence given by Sri Vikha Ram, S/o. of Sri Mohan Ravi Das, who is working as U/g. loader since 1957 at Girimint Colliery and who is a permanent resident of village Chhamani, Post Office and Distt. Unnao (UP).

There are two types of tubs at Girimint Colliery. Small tubs are being used at No. 1 pit for which loaders receive payment of one tonne. Bigger tubs are used in Pit No. 3 for loading of which loaders get payment for 3.5 tonnes although these tubs contain 5 tonnes of coal. These bigger tubs were introduced at Girimint Colliery 3 pit in the year 1969 and since then loaders are receiving payment of 3.5 tonnes for loading these tubs.

One tonne tubs were being used at Kothee No. 3 seam We noticed that contains of six small tubs were being accommodated in the big tubs. Considering on the way there were some spillage of coal we estimate that the capacity of bigger tubs is 5 tonnes.

Cross Examination by Shri K. L. Bose, Agent, Girimint Colliery.

1. Q. How the coal moves from the bunker ?

   A. Through main belt

2. Q. When six tubs of coal was unloaded in the bunker was the bunker empty ?

   A. No the bunker was empty.

3. Q. From where the belts starts ?

   A. The belt starts from Poniati in-bye section.

4. Q. When six tubs of coal was unloaded in the bunker was there any other coal in the bunker ?

   A. No, the bunker was empty.

5. Q. When you used to dump six tubs of coal whether the belt was also empty ?

   A. No belt was empty.

6. Q. Why the above exercise was done ?

   A. This exercise was done to measure the content of the mine car.

7. Q. When the above exercise was done who the persons present at the site ?

   A. Loaders and Trammers were present when the above exercise was done There was nobody other than the above two categories of workers.

8. Q. Are you aware whether payments are made on the basis of volume of loading or weight of coal loaded ?

   A. Payments are made on tonnage basis i.e., on weighment basis.

9. Q. Did you ever measure small tubs or big tubs ?

   A. Payments are made on tonnage basis i.e., on weigh- the management measured these tubs.

Sd/-LTI of
BHIKHA RAM,
Underground Loader Girimint Colliery
Sripur Area.

Dated :—the 11th March, 1980.

Arbitration under section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 arising out of a dispute between the management of Sripur Area of M/s. Eastern Coalfields Limited, P.O. Kalipahari, Dist Burdwan and their workmen represented by Koyala Mazdoor Congress (HMS), Gorai Mansions, G.T. Road, Asansol

Recorded evidence given by Sri Ram Chij Koeri, S/o. Sri Ram Dhari Koeri, who is working as U/g Loader since 1956 at Girimint Colliery and who is a permanent resident of village Kotholwia, P.O Musharbazar Dist. Chhapra (Bihar).

Mine cars are used in No. 3 pit of Girimint Colliery These mine cars were introduced in the year 1969. Loaders were of the impression that the mine cars can contain more than 4 nos of small tub, coal but when small tubs were being used in Koithee No. 3 section we found that contains of six small tubs were being accommodated in a mine car. In my opinion the capacity of mine car is 6(six) tonnes.

Loaders are getting wages for loading 3-1/2 tonnes for loading a mine car. A mine car was filled up on the surface in presence officers when it was found that coal contains of 4-1/2 tubs can be transferred to the mine car. In the underground when these mine cars are loaded through belt, contains of six small tubs are accommodated in this mine car.

Cross-Examination by Mr. K. L Bose, Agent, Girimint Colliery.

1. Q. How do you know small cars contains one tonne of coal ?

   A. In all quarries such small tubs are used and we know these tubs contain one tonne of coal.

2. Q. Whether are you aware of the fact that mine ore is being used in other collieries of ECL ?

   A. I am not aware

3. Q Have you ever measured the small tubs or a mine car by measuring tape ?

   A. I have never done this.

4. Q. Are you aware of the procedure on which basis payment is made ? Is it on the basis of weighment or volumatic ?

   A. I do not know the procedure.

Sd/-LTI of
RAMCHIJ KOERI,
U/g loader, Girimint Colly.

11th March, 1980.

ANNEXURE 'D'

Minutes of conciliation proceedings held in the Office of the Asst. Labour Commissioner (Central) Asansol in the matter of strike over alleged non-fulfilment of grievances of the U/g. Loaders.

27th May, 1978.

The parties present are : Representing the Employer :—

Sri N. N. Gautam, Sub Area Manager, Girimint Sub Area. Sri S. C. Mallik, Dy. CPO, Sripur Area and Sri S. C. Koar, Asst. CPO. The workmen on behalf of the u/g. loaders at Girimint Colliery (1) Sri Kalpoo Yadav (2) Sri Madan (3) Dhaneswar Prasad (4) Ramdas Koiri (5) Sukhraj Harijan (6) Mondan Mondal (7) Mishri Harijan (8) Seamrath Harijan (9) Meghu Pashi (10) Sahdeo Dhobi (11) Sundar Harijan and (12) Billoo Harijan.

The above workmen it is reported were selected in the general meeting of U/g. loaders at Girimint Colliery numbering about 650. This body was authorised to negotiate on their behalf on the issues as placed at item Nos. 1, 2 and 3 of the present charter of demand placed before the employer. They shall file the papers on the next date. The Conciliation proceedings were resumed.

The worker's representatives stated that the first two items of demands in their notice dated 16-5-78 are the most burning issues and the workmen will be anxious to settle out the same. In case of honourable settlement is reached on those two items the rest of the items of demands may not be perused for

The discussions were started and the employers representative stated that in the midst of strikes which has already

commenced from the 26th May, 1978, they would not like to agree on any issue under pressure. He was, however, requested to contribute his efforts to the AWC(C) so that some contention could be created which would be the basis of breaking the impasses.

Reiterating their demand, the workmen representatives stated that if they were paid to the extent of 20 per cent of the actual raising on account of reloading of fallen coal that would be acceptable to them

As regards the demand at item No. 1 of the charge, this issue was discussed in detail Both the parties were of the opinion that 1st the measurement of the mine cars be done by the Asstt. Labour Commissioner (C) in presence of the parties concerned on any day and the findings will be acceptable to them.

It was felt by the parties that in the event of final settlement of the issue they shall be effective from the 1st of April, 1978.

Both the parties jointly requested for a little time to be allowed to examine the above suggestion and discuss these amongst their own bodies with a view to resolve the matters.

The case is accordingly adjourned on 29th May, 1978 at 3 P.M. the parties are requested to note. No notices to be issued.

Sd/-
S. C. MALLIK
27th May, 1978.
Sd/-
S. C. KOAR,
27th May, 1978.
Sd/-
N. N GAUTAM,
27th May, 1978.

Sd/-
MADAN MONDAL
RAMDAS KOIRI
SUKHRAJ HARIJAN
BHUNESWAR
RAMNATH
DULU
Sd-
SUNDAR.
Sd/-
V. SINHA
27th May, 1978.

ANNEXURE 'F'

Before the Arbitrator appointed under Section 10A of the Industrial Dispute Act, 1947

In the matter of an Industrial Dispute.

BETWEEN

The management of Sripur Area of Eastern Coalfields Limited P.O. Sripur, Dist. Burdwan

AND

Their workmen represented by Koyala Mazdoor Congress (HMS), Gorai Mansions, G.T. Road, Asansol.

AND

In the matter of an Arbitration under Sec. 10A of the Industrial Disputes Act, 1947.

Written Statement on behalf of the workmen most respectfully Sheweth :

(1) That the aforesaid Dispute arose due to introduction of bigger size of tubs—known as Mine cars, since 1969. At present there are two types of tubs at Girimint Colliery, small tubs are being used at No. 1 Pit for which loaders received payment of one tonne Bigger tubs are used in pit No. 3 for loading of which loaders get payment for 3.5 tonnes although the said tubs contain at least 5 tonnes for coal

(2) That the said bigger tubs i.e. Mine cars were introduced at Girimint Colliery No 3 Pit in the year 1969 and since then the loaders of the said colliery are receiving payment of 3.5 tonnes for loading those big tubs.

(3) That it may be mentioned in this connection that one tonnes tubs were being used at Kothee No 3 Seam. It was noticed that contains of six small tubs were being accommodated in the big tubs Considering the fact that there might be some spillage of coal on the way (which can not be more than one tonne) the said big tubs contain at least 5 tonnes of coal. In this connection it may be mentioned that when the test was made, six tubs of coal were unloaded in the empty bunker. The coal moves from the bunker through the main belt and the belt starts from Poniati in-bye section.

(4) That the management is aware of the entire position. There cannot be any dispute regarding the quantum of coal containing capacity of the big tubs and the management could have measured the same when the dispute arose. But as the management is aware of the genuineness of the submissions of the workmen, the same was not done. A number of sittings were held both at the bipartite level and tripartite level but the matter could not be resolved. A meeting with the management was held on 12th April, 1975 in the presence of Sub-area Manager where it was noted :

"Sri Vinoy Kumar raised the point of measurement of mine car coal tubs of Girimint Colliery on the plea that the bigger size of mine car/coal tubs are being used than those rates due for payment.

Sri N. N. Gautam said that it could be done at any moment He also informed that it was done in the past by AWC(C) and was found by him that on average the tubs were of standard size. Sri Gautam further said that the measurement will be done by measuring tape and not by filling the mine car with tubs loads of coal as suggested by the union. The union also suggested for payment on weighment basis which was not accepted".

(5) That the dispute was also discussed in the meeting held in the office of the Sub Area Manager dated 29th November, 1977 and in item No. 6 of the proceedings it has been noted :

> "SAM explained that both 144 cft. mine car and 40.5 cft. coal tubs are in use at Girimint Colliery. There is one doubt amongst loaders regarding actual size of 144 cft based not on any fact, since LEO(C) had measured the mine car himself and was satisfied. Since as the management cannot keep on measuring the mine cars over and over again, union was requested to take up the matter with area level"

(6) That another sitting was held in the office of the General Manager in the presence of Dy. CPO of the Employer and it has been noted in item no 1.1(a) that "the union demanded payment of 162 cft. for loading of the mine car which has a cubical content of 144 cft. was not acceptable to the management. The Union's claim for ascertaining the cubical content of the mine car by transferring coal from coal tub to mine car was also not acceptable to the management. The union re-iterated that a doubt exists in the minds of the workmen and as such the matter should be further deliberated upon.

1.1(b) On the matter of reloading of the fallen coal from Conveyor the management informed the union and agreed upon before the RLC(C) payment according to actual measurement of re-loading is made. As regards payment for the past period, the management at one stage agreed to make payment on this account from 1st April, 1978, as final settlement of the issue. But the involved unions did not agree to accept this offer of the management".

(7) That in view of the aforesaid facts and circumstances as may be evident from the proceedings of the Bi-partite meetings between the Employer and the workmen, the loaders of the Girimint Colliery attached to Pit no. 3 are getting less wages than what is actually due to them. The workers are also loosing in the matter of re-loading of the fallen coal

(8) That the entire matter of loading of coal in big tubs and reloading of 'fallen Coal' from the conveyor should be done in according to the norms of calculation. The workmen should be paid for the actual amount of coal loaded in the

said tubs, through proper measurement. The workmen should also be paid for the reloading of the fallen coal from the conveyor to the extent demanded by the union :

(9) That the union craves leave to add, alter or modify the present written statement after the filing of the same by the Employer.

In the circumstances the union prays that the Hon'ble Arbitrator will be pleased to decide amount payable to the workmen for loading the big tubs (Mine Cars) and the amount due on account of reloading of fallen coal to the extent of 20 per cent of the actual raising on account of reloading.

And for that act of kindness, your petitioner, as in duty bound, shall ever pray :

VERIFICATION

I, Shiv Kant Pandey, the Secretary of the union do hereby declare that the statements made in paras 1 to 7 are true to my knowledge I sign this verification on this the 24th day of March 1980 at Asansol

Sd/-

S. K. PANDEY, Secy.
24-3-80

ANNEXURE 'E'

Whereas an industrial dispute between the management of Sripur Area of M/s. Eastern Coalfields Limited, P.O. Sripur, Distt. Burdwan and their workmen represented by Koyala Mazdoor Congress(HMD) Gorai Mansions, G.T. Road, Asansol has been referred to the undersigned for Arbitration under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), (vide Notification in Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-Section II dated 16th February, 1980) you are hereby summoned to appear before the undersigned in person on the 11th day of March, 1980 at Sanctoria Office at Sripur at 11 am to answer all material questions relating to the dispute and you are directed to produce on that day all the books, papers and other documents and things in your possession or under control in any way relating to the matter under investigation by the undersigned.

Given on this the 26th day of February, 1980.

Sd/-

A. B SHAH, Arbitrator

1. B M. Mukherjee, G.M. Sripur Area.
2. K. L. Bose, Agent, Girimint Colliery.
3. Shiv Kant Pandey, Secy. KMC

c.c. to Shri S P Khawas with the original Gazette dated 5th February 1980. He would please make necessary arrangements.

ANNEXURE 'F'

Eastern Coalfields Limited

(A Subsidiary of Coal India Ltd)

Office of the Chairman cum Managing Director

Ref No. ECL/CMD/C-6D/21160

Dated the 17th June, 1980

To

1. Shri B. M Mukherjee,
   General Manager, Sripur Area.
2. Shri K. L. Bose, Agent, Girimint Colliery,
   Sripur Area.
3. Shri Shiv Kant Pandey, Secretary, Koyala Mazdoor Congress(HMS),
   Gorai, Mansions, G.T. Road,
   Asansol

Sub : Arbitration under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947—vide Notification in Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub Sec.-II dated 16-2-80.

Further to the Notice dated 26th day of March, 1980 the parties are hereby informed that the date of hearing of the above case has been fixed on 26th June, 1980 at the Sripur Guest House at Poniati at 9 a.m.

The Parties are directed to appear before the Arbitrator on the aforesaid date with all relevants documents, evidences etc.

Sd/-

A. B SHAH, Arbitrator

c.c. Shri Amitava Sinha, Pers Deptt. ECL—for information and advise.

ANNEXURE 'F'

Eastern Coalfields Limited

(A Subsidiary of Coal India Ltd)

Office of the Chairman cum Managing Director

Ref No. ECL/DIE(E)/135/21679

23 June, 1980

1. Shri B. M. Mukherjee,
   General Manager,
   Sripura Area.
2. Shri K. L. Bose,
   Agent,
   Girimint Colliery,
   Sripur Area.
3. Shri Shiv Kant Pandey,
   Secretary,
   Koyala Mazdoor Congress (HMS),
   Gorai Mansions, G. T. Road,
   Asansol.

Sub : Arbitration under section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947—vide Notification in the Gazette of India, Part-II Section 3, Sub-Section II dated 16th February, 1980.

Further to the notice, reference No. ECL/CMD/C-6D/21160 dated 17th day of June, 1980, the parties are hereby informed that the date of hearing of the above case fixed for 26th June, 1980 at Poniati Guest House at 9 a.m. has been adjourned as I, being the Arbitrator, have been called to attend an emergent meeting at New Delhi on that day. The next date of hearing has therefore, been fixed on Monday, 30th June, 1980 The venue & time remains unaltered.

The parties are hereby requested to appear before the Arbitrator on the aforesaid date & time with all relevant documents, evidences, etc.

Sd/-

A. B. SHAH, Arbitrator

c.c. CPO, Sanctoria (for attention of on Amitava Sinha).

ANNEXURE 'G'

Before Sri A. B. Shah, Arbitrator.

In the Matter of Government Order dated 5th February, 1980.

and

In the Matter of Arbitration Agreement u/s 10(A) of the I.D. Act, 1947—vide Notification in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section II, dated 16th February, 1980.

and

In the Matter of an Industrial Dispute between the Management of Sripur Area of M/s. Eastern Coalfields Limited, P.O. Sripur, District Burdwan.

and

Their workmen represented by Koyala Mazdoor Congress (H.M.S), Gorai Mansions, G. T. Road, Asansol.

Written Statement of the Employer.

The Employers beg to state :—

(1) That the management has not received any copy of the written statement of the workmen so far

although it was expected that the alleged dispute having been raised by the workmen they should have filed their written statement first and the management was required to submit their written statement by way of giving their answers to the allegations and claims made in the union's written statement. But the management has been deprived of this opportunity and, as such, they are filing their written statement by proceeding on and assumed basis and by thinking that the union will raise the same plea which were raised during the conciliation proceedings. The management may submit rejoinder if necessary arises later.

(2) That with this background the Management begs to submit further that the alleged dispute is not an Industrial Dispute at all and the issue raised does not even by incidental manner gives rise to an industrial dispute but for saving the e tablishment from being victimized by successive strikes the management has been compelled to refer the matter to Arbitration.

(3) That by inviting the specific matters in dispute which has been recorded in the said Government Order it is submitted that the cubical contents of the Mine Cars used by the management at Pit No. 2 & 3 of Girimint Colliery were never higher than 144 cft.

(4) That at all materials times and still now the average cubical contents of the said Mine cars used by the underground loaders in the above colliery cannot be more than 144 cft. and there is no merit in the contention of the workmen that the underground loaders have to load coal more than 144 cft. by loading such a mine car.

(5) It is necessary to submit that the daily work load of loaders, who are piecerated workers, has been fixed at 81 cft and this points out that the work done by the loaders is required to be evaluated on the basis of measurement of the container i.e. of the Coal tubs or mine cars.

(6) It is well known to the Honourable Arbitrator that there is no uniformity as to the type of Coal tubs/mine cars used in the Coal mining industry and containers of different measures are being used by different mines and there is no difficulty in determining the actual cubical content or volumetric content of such tub/mine cars and the same can be ascertained by measuring the length, breadth and height of the containers and by the process of multiplication of the three measurements.

(7) It is not understood why there should be any apprehension of giving any higher quantity of coal by loading coals into such a mine car in use in the colliery whether measured on 40.5 cft unit or on the basis of any other unit.

(8) The management submits that there is absolutely no merit in the claim of the workmen and it is prayed that Hon'ble Arbitrator be pleased to answer the dispute by accepting the submission of the management stated above and to pass an Award accordingly.

Dated, the 30th June, 1980

Sd./-

B. M. MUKHERJEE, General Manager,

Sripur Area.

VERIFICATION

I, Sri Kanailal Bose, Agent, Girimint Colliery do hereby say that the statement of facts made above are true to my knowledge I sign this verification on this 30th day of June, 1980 at my office

Sd/-

KANAILAL BOSE

ANNEXURE 'H'

Eastern Coalfields Limited

(A Subsidiary of Coal India Ltd.)

Office of the Chairman cum Managing Director

Ref. No. ECL|Dir|East|135|22463 June 30, 1980

1. Shri B. M. Mukherjee,
   General Manager,
   Sripur Area.

2. Shri K. L. Bose,
   Agent,
   Girimint Colliery,
   Sripur Area.

3. Shri Shiv Kant Pandey,
   Secretary,
   Koyala Mazdoor Congress (HMS),
   Gorai Mansions, G.T. Road,
   Asansol.

Dear Sir,

Sub : Arbitration under section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947—vide Notification in Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-Section-II Dated 16th February, 1980.

Further to the notice reference No ECL/Dir(F)/135/21679 dated 23rd June, 1980, the parties are hereby informed that the date of hearing of the above case has been fixed at 8.45 A.M. on Monday, the 7th July, 1980 at Girimint Colliery and also at 4.30 P.M. on Friday the 11th July, 1980 at CMD's Office, Sanctoria.

The parties are hereby requested to appear before the Arbitrator on the aforesaid days and time with all relevant documents etc.

Yours faithfully,

Sd/-

A. B. SHAH, Arbitrator

c.c. CPO, Sanctoria, Hqrs.

ANNEXURE 'H'

COPY

Shri A. B. Shah,

Arbitrator.

Sub : Arbitration U/s 10A of I.D. Act at Girimint Colliery.

Dear Sir,

Vide your reference No. ECL|Dir(East)|135|22463 dated 30 June, 1980 you have very kindly fixed 7th July, 1980 and 11th July, 1980 for hearing. In this connection I want to humbly submit that my mother is ill and I am going to see her in Banda (UP). I request you to kindly fix any date after 15th of July, 1980.

I have mentioned this to G.M. Sripur and Agent Girimint and they have no objection to change of date.

4th July, 1980.

Yours Sincerely,

Sd/-

VINAY KUMAR, General Secy.

KMC|HMS

ANNEXURE 'H'

KOYALA MAZDOOR CONGRESS

Gorai Mansions,
G.T. Road,
Asansol.

IMMEDIATE BY HAND

5th July, 1980

Shri A. B. Shah,
Director-in-Charge-East.
Eastern Coalfields Ltd.,
Sanctoria, P.O. Dishergarh,
Distt. Burdwan.

and

Arbitrator

Sub : Arbitration under section 10A of the Industrial Dispute Act, 1947 vide notification in Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section-II dated 16th February, 1980.

Dear Sir,

You had made site inspection in the said arbitration case and had directed for making measurement of all the 27 tubs separately and individually and for recording the measurement of representatives of the workmen and the management.

Accordingly I had nominated 3(three) representatives from our side on 4th July, 1980. I have received complaints from the representatives appointed by me to this effect that the management is not doing the measurement in a fair and proper manner. The management is placing hardless and is avoiding exact measurement.

I request you to kindly direct the management to desist from such activities which are likely to hamper the smooth progress of arbitration.

Yours sincerely,

Sd/-

VINAY KUMAR, General Secretary

ANNEXURE 'H'

Eastern Coalfields Limited

(A Subsidiary of Coal India Ltd.)

Office of the Chairman cum Managing Director

Ref. No. ECL/ABS/DIC(ED)/135/23288 dated 7-7-1980

1. Shri B. M. Mukherjee,
   General Manager,
   Sripur Area.
2. Shri K. L. Bose, Agent,
   Girimint Colliery,
   Sripur Area.
3. Shri Shiv Kant Pandey,
   Secretary,
   Koyala Mazdoor Congress (HMS),
   Gorai Mansions, G.T. Road,
   Asansol.

Sub : Arbitration under Section 10A of the Industrial Disputes Act 1947 vide Notification in Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section II dated 16-2-80.

Further to the notice reference No. ECL/Dir(East)135/22463 dated 30th June, 1980, the parties are hereby informed that the date of hearing of the above case has been re-fixed as requested by Prof. Vinay Kumar, General Secetary, KMC at 8 a.m. on Tuesday the 22nd July, 1980 at Girimint Colliery and also at 4.30 p.m. on Friday the 25th July, 1980 at CMD's Office Sanctoria.

The parties are hereby requested to appear before the Arbitrator on the aforesaid days and time with all relevant documents, etc.

Sd/-

A. B. SHAH, Arbitrator

c.c. CPO, Sanctoria (for information of Shri Amitava Sinha)

ANNEXURE 'H'

Eastern Coalfields Limited

(A Subsidiary of Coal India Ltd.)

Office of the Chairman cum Managing Director

ECL/Dir(E)/135/23289

July 7, 1980

Copy of letter dated 5th July, 1980 from Koyala Mazdoor Congress, Gorai Mansions, G.T. Road, Asansol addressed to Shri A. B. Shah, Director-in-Charge (East), ECL, Sanctoria and Arbitrator.

Sub : Arbitration under section 10A of the Industrial Dispute Act, 1947—vide Notification in Gazette of India, Part-II, Sec. 3, Sub-Section-II dated 16-2-1980.

You had made site inspection in the said arbitration case and had directed for making measurement of all the 27 tubs separately and individually and for recording the measurement of representatives of the workmen and the management.

Accordingly I had nominated 3(three) representatives from our side on 4th July, 1980, I have received complaints from the representatives appointed by me to this effect that the management is not doing the measurement in a fair and proper manner. The management is placing hardless and is avoiding exact measurement.

I request you to kindly direct the management to desist from such activities which are likely to hamper the smooth progress of arbitration.

Copy to : General Manager, Sripur Area. He is requested to see that correct measurement is done (jointly).

Sd/-

A. B. SHAH, Arbitrator

ANNEXURE 'H'

KOYALA MAZDOOR CONGRESS

Gorai Mansions, G.T. Road, Asansol.

Dated : 11th July, 1980

Shri A. B. Shah,
Director-in-Charge,
Eastern Coalfields Ltd.,

Sanctoria, P.O. Dishergarh, and Arbitrator.

Sub : Arbitration under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947—vide Notification in Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section II dated 16-2-80.

Dear Sir,

Kindly refer to your letter No. ECL/ABS/DIC(ED)/135/23287 dated 7th July, 1980 which is in reply to my letter dated 5th July, 1980. In this connection I have to further state that I have visited the Girimint Colliery on 7th July, 1980 at about 9.30 a.m. I have personally seen and counted 24 mine cars lying on the pit top which the management was refusing to measure on the ground that these cars are not being presently used. Similarly a large number of comparatively big size mine cars were lying in the under ground. The workmen told me that these mine cars have been in use till very recently and it was deliberately with a view to avoid measurement of these big size cars that these have been declared out of use without any reasonable grounds. I now learn that these are being removed.

I took up this matter with the Manager who was present. I pointed out to him that the mine cars which have not been torn into pieces and which can be measured must be measured because the dispute is not confined to the mine cars being used currently and, therefore, it is necessary that all the mine cars which have been used during the period in question must be measured to arrive at a right conclusion. I told him it is in the duty of both the parties to help the arbitrator in his task. The Manager told me that 27 mine cars which are in current use will be measured and in no circumstances he will allow measurement of any mine cars which are currently not in use. Accordingly to my opinion such mine cars are about 40 which are presently not in use.

As you know that the mine cars were introduced in the year 1969 and since then a number of mine cars have been in use from time to time In my humble opinion it is therefore, necessary that all the mine cars which we can conveniently measure must be measured and any further inspection, hearing should take place only after this part of job has been satisfactorily done.

The union assure you of its all co-operation.

Yours sincerely,
Sd/-
VINAY KUMAR, General Secretary

ANNEXURE 'H'

KOYALA MAZDOOR CONGRESS

Gorai Mansions,
G.T. Road,
Asansol.

Dated : 19th July, 1980

Shri A. B. Shah,
Director-Incharge,
Eastern Coalfields Limited,
Sanctoria,

P O Dishergarh (Burdwan) and Arbitrator.

Sub : Arbitration under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947—vide Notification in Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section II dated 16th February, 1980.

Ref : No. ECL/ABS/DIC(ED)/135/23288 dated 7-7-80.

Sir,

I have to invite your kind attention to the above and inform you that Prof. Vinay Kumar, General Secretary of this union is away from Asansol for some urgent organisational work and is expected to return back during the first week of August, 1980.

Under the aforesaid circumstances I like to pray before your goodself to postpone the date of hearing and thus enable us to appear before you with all relevant papers and documents.

Inconvenience caused to you is very much regretted.

Yours sincerely,
Sd/-
SHIV KANT PANDEY, Secretary

COPY

Eastern Coalfields Limited

(Subsidiary of Coal India Ltd.)

Office of the Chairman cum Managing Director

Ref. No ECL/ABS/DIC(E)/135/24949

Dated 21st July, 1980

1. Shri B. M. Mukherjee,
General Manager,
Sripur Area.
2. Shri K. L. Bose,
Agent,
Girimint Colliery,
Sripur Area.
3. Shri Shiv Kant Pandey,
Secretary,
Koyala Mazdoor Congress(HMS),
Gorai Mansions, G.T. Road,
Asansol.

Dear Sir,

Sub : Arbitration under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947—vide Notification in Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section II dated 16-2-80

Further to the notice reference No. ECL/DIR/(East)/135/22463 dated 30th June, 1980, the parties are hereby informed that the date of hearing of the above case has been re-fixed at 8.45 a.m. on Monday the 4th August, 1980 at Girimint Colliery as per special request made by Shri Shiv Kant Pandey, Secretary, KMC, Asansol vide his letter dated 19th July, 1980.

Yours faithfully,
Sd/-
A. B. SHAH, Arbitrator

c.c. CPO, Sanctoria (for information of Shri Amitava Sinha)

ANNEXURE 'H'

COPY

Eastern Coalfields Limited

(A Subsidiary of Coal India Ltd.)

Office of the Chairman cum Managing Director

Sanctoria, P.O. Dishergarh, Distt. Burdwan.

Ref. No. ECL/Dir(1)/135/24

July 31, 1980

1. Shri B. M. Mukherjee,
General Manager,
Sripur Area.
2. Shri K. L. Bose,
Agent,
Girimint Colliery,
Sripur Area.
3. Shri Shiv Kant Pandey,
Secretary,
Koyala Mazdoor Congress (HMS),
Gorai Mansions, G.T. Road,
Asansol

Dear Sir,

Sub : Arbitration under Section 10A of the Industrial Dispute Act, 1947—vide Notification in Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section-II dated 16-2-1980

Further to the notice reference No. ECL/ABS/DIC(E)/135/24949 dated 21st July, 1980, the parties are hereby informed that the date of hearing of the above case has been re-fixed at 8.45 a.m. on Friday the 22nd August, 1980 at Girimint Colliery at per special request made by G.M. Sripur Area vide his letter No 1973 dated 25th July, 1980.

Yours faithfully,
Sd/-
A. B. SHAH, Director-Incharge (East)

c.c. CPO, Sanctoria (for information of Sri Amitava Sinha)

ANNEXURE 'I'

BEFORE SHRI A. B. SHAH, ARBITRATOR

In the matter of Government Order dated 5-2-1980.

And

In the matter of Arbitration Agreement U/s 10(A) of the I.D Act, 1947—vide Notification in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section-II, dated 16th February, 1980

And

In the matter of an Industrial Dispute between the Management of Sripur Area of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Sripur, Distt. Burdwan.

And

Their workmen represented by Koyala Mazdoor Congress (HMS), Gorai Mansions, G.T. Road, Asansol.

Rejoinder filed by the Employer in reply to the Written Statement of the Workmen. :

The Employers beg to state most respectfully :

(1) That the statements made in Para 1 and 2 of the Written Statement of the workmen (hereinafter referred to as the "Said Statement") are matters of record and the Employers do not admit anything which are contrary to the said records.

(2) That the workmen are called upon to prove that the instant dispute arose since 1969 when the mine cars were introduced in the colliery.

(3) That the workmen are called upon to prove the illegations made in para 3 of the said written statement and it is denied that the mine cars were ever noticed to contain coals to the extent of the quantity equivalent to the load of six small

tubs of the size used in Kaithi No. 3 Seam and/or after giving allowance of one ton for spillage and said mine cars can contain at least five tons of coal.

(4) that the purport of the statement made in last two sentences in para 3 of said written statement has not been intelligible to the employers.

(5) that with regard to the allegations made in para 4 of said written statement it is denied by the Employers that there can be any dispute with regard to the cubical contents of the mine cars and same has been repeatedly measured whenever there was any dispute and it has always been found that the mine cars after full loading do contain 144 cft of coal.

(6) that the discussions referred in para 4, 5 and 6 of the said written statements are matters of record and the workmen are called upon to produce the same.

(7) that the claim made in respect of re-loading of fallen coal in para 7 and 8 of the said written statement are beyond the scope of the instant dispute referred to the Hon'ble Arbitrator.

(8) that the Employers beg to record here that the dispute in respect of re-loading of fallen coal is a subject-matter of a separate Industrial Dispute which is now pending adjudication being Reference 16 of 1979 before the Central Government Industrial Tribunal Calcutta.

Sd|--
B. M. MUKHERJEE, General Manager

Dated : the 20th August, 1980

VERIFICATION

I, Sri Kanailal Bose, Agent, Girimint Colliery do hereby say that the statement of facts made above are true to my knowledge and I sign this verification on this the 20th day of August, 1980 at my office.

Sd/-

KANAILAL BOSE

ANNEXURE J

ARBITRATION PROCEEDING

Proceeding of 22nd August, 1980

From Management side Shri K. L. Bose is present.

From Workmen side Shri Shiv Kant Pandey is present.

It is mutually agreed by both parties and also by Arbitrator and so Shri S. N. Banerjee, O.S.D. (Mining) who is also Chief of Survey Division of Eastern Coalfields Limited, headquarters is appointed by the parties and Arbitrator to measure all the Mine Cars in use or which were earlier in use and also to weigh contents of 3 Mine Cars and submit report to the Arbitrator.

(A. B. SHAH)
Arbitrartor

(K. L. BOSE)
Agent.
Girimint Colliery.

(SHIV KANT PANDEY)
Secretary, KMC.

ANNEXURE 'J'—Contd.

COPY

EASTERN COALFIELDS LIMITED

(A Subsidiary of Coal India Ltd.)

Ref. No. LR|SNB|LA|

Dated : 1-9-80.

To
Shri A. B. Shah,
Director-in-Charge (East),
Eastern Coalfields Ltd.,
Sanctoria.

Sub :—Verification of Mine Car capacity at Girimint Colliery.

Dear Sir,

Internal dimensions of 41 mine cars were measured on 25-8-80 in the presence of the representatives of the Colliery management and the union.

The results of the measurements were duly countersigned by the Production Manager, Colliery Surveyor and the Union Representatives. The average of the 41 Cars is 146.03 cft.

On the basis of these measurements the Mine Car volume has been calculated in each case, as shown in the enclosure.

The weighment of coal carried in mine cars was undertaken on 30-8-80. After the weighment for coal in two mine cars was completed a dispute arose between the Mining-Overmen and Mine-Sardars on one side and the underground loaders on the other side. The average is 3.44 tons.

The third mine car could not be huled from underground upto 6.30 P.M. in the evening and it appeared that the dispute between the mining staff and loaders would take sometime to be resolved. The work was therefore discontinued after consultation with Shri K. L. Bose, Agent.

The result of the weighment of the two mine cars is shown in the enclosure.

Yours faithfully,
Sd|--
(S. N. Banerjee)
OSD(Mining)

Encl :

ANNEXURE 'J'

CAPACITY OF MINE CARS OF GIRIMINT COLLIERY AS FOUND BY MEASUREMENT ON 25-8-80

Sl. No.	Mine Car No.	Capacity (cft)	Remarks
1	2	3	4
1.	X	147.86	In use
2.	A57	140.67	,,
3.	K20/A28	153 17	,,
4.	I5	145.38	,,
5	X2	152.25	,,
6	I66	148 06	,,
7.	I24	143 48	,,
8	A54	147.59	,,
9.	?	142.20	Not in use
10.	?	141.59	,,
11.	?	150.92	,,
12.	A54	148.34	,,
13.	111	148 57	,,
14.	A551	145.94	,,
15.	K30	147.94	,,
16.	I2	150.48	,,
17.	A3	145.78	,,
18.	A4	144.60	,,
19.	A11	149.64	,,
20.	30	145 44	,,
21.	I51	148 94	In use
22.	I46	142.72	,,
23.	K55	149 41	,,
24.	A44	144.72	,,
25.	K56	140.58	,,
26.	I29	145.58	,,
27.	A47	146.39	,,
28.	N	147.52	,,
29.	I44	142.57	,,
30.	A29	141.64	,,
31.	A43	149.56	,,
32.	I62	151 81	,,
33	A32	146.83	,,

1	2	3	4
34.	A52	142.43	In use
35.	A14	142 17	,,
36.	149	138.06	,,
37.	A56	142 56	Not in use
38.	?	145.16	,,
39.	?	141,28	,,
40.	?	143.56	,,
41.	?	153.93	,,
	Average	5987 32 CFT.	

41

=146.03 cft per mine car.

Tonnage of coal of two mine cars as found by weighment on 30-8-80

(1) WT. of coal & dumper = 13,350 kg.
(2) Tare of dumper = 6,470 kg.

Weighment of coal = 6,880 kg.
= 6 88 tonnes.

Av. Wt. of coal $= \frac{6.88}{2}$

per Mine Car = 3.44 tonnes.

ANNEXURE-'K'

COPY

KOYALA MAZDOOR CONGRESS

Rajnarayan : President.
Prof. Vinay Kumar : Genl. Secretary.
Shiv Kant Pandey : Secretary.

Gorai Mansions,
G. T. Road, Asansol

Dated : 1-9-1980

Shri A. B. Shah,
Director-in-Charge,
Eastern Division, ECL,
Sanctoria.

&

Arbitrator

In the matter of Government Order dated 5-2-1980; and

In the matter of Arbitration Agreement u/s 10(A) of the I. D. Act, 1947 vide notification in the gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 16-2-1980.

Before Shri A. B. Shah, Arbitrator :

Submission on behalf of the workmen.

1. That the third sitting of the Arbitration was held at Girimint colliery on 22-8-1980.

2. That in the above-mentioned third sitting it was decided that 3 mine cars loaded with coal will be chosen at random by a surprise visit and the coal contained in the 3 mine cars will be weighed. It was further decided to entrust this work to Shri S. N Banerjee, Chief of Survey division.

3. That Shri S. N. Banerjee visited the Girimint Colliery on 30-8-80 to complete this assignment.

4. That the local management of the Girimint Colliery created hurdles and impediments in this work. Changed the normal duties of the supervisory staff with a view to manipulate the weighing process in its favour and against the workmen. Mine cars containing coal of a particular type were weighed

5. That Shri Banerjee could not complete weighment of the coal as envisaged in column 4 of the order of the arbitration dated 22-8-80.

6. That in view of what has been stated above it is necessary that the whole exercise of weighment should be done afresh and without any hindrance from the management so that the arbitrator may arrive at truth and do justice.

7. That the workmen pray an order accordingly.

Sd|--
(Jagdish Singh)
Assistant Secretary,
Koyala Mazdoor Congress (HMS)
on behalf of the workmen.

Date : 1-9-1980.

Copy to :—(1) The General Manager, ECL, Sripur Area. P.O. Kalipahari, Dist. Burdwan.

Copy to :—(2) The Agent, Girimint Colliery, P.O. Pariharpur, Dist. Burdwan.

Sd|--
Assistant Secretary.

COPY

ECL|DIR(E)|135|32430 dated 4-9-80

1. Shri B. M. Mukherjee,
General Manager,
Sripur Area.

2. Shri K. L. Bose, Agent,
Girimint Colliery,
Sripur Area.

3. Shri Shiv Kant Pandey,
Secretary,
Koyala Mazdoor Congress (HMS),
Gorai Mansion, G.T. Road,
Asansol.

Dear Sir,

Sub : Arbitration under Sec. 10A of the Industrial Disputes Act, 1947—vide notification in Gazette of India, Part-II, Section-3 Sub-Section (ii) dated 16-2-80.

Further to the notice reference No. ECL/Dir(E)/135 dated 31-7-1980, the parties are hereby informed that the date of hearing of the above case has been fixed at 9 A.M. on Tuesday the 9th September, 1980 at Girimint Colliery.

Yours faithfully,

Sd|-
(A. B. Shah)
Director-in-Charge (East)

c.c. C.P.O. Sanctoria (for information of Sri Amitava Sinha).

ANNEXURE 'L'

PROCEEDING OF 9TH SEPTEMBER, 1980

The final hearing of Arbitration Proceeding is hereby being concluded on 9th September, 1980. From the management side S/Shri B. M. Mukherjee, General Manager, Sripur Area, K. L. Bose, Agent, Girimint Colliery and T. K. Singh, Addl. C.P.O. are present.

From the workmen side Prof. Vinay Kumar, General Secretary, Koyala Mazdoor Congress, Shri Shiv Kant Pandey, Secretary, Koyala Mazdoor Congress are present.

Shri S. N. Banerjee, O.S.D. (Mining) is called by the Arbitrator and in his presence the measurement of 41 tubs done by Shri Banerjee were shown to all the parties concerned. The average of 41 tubs measurement came to 146 cft and it was agreed by all the parties i.e. workmen, management and Arbitrator.

Then the date of enforcement of this measurement for the purpose of payment to underground loaders was argued. The management contended that this should be paid from the date

of Award whereas the workmen contended that this should be paid from the date of Nationalisation of Coal Industry. Thereafter the management submitted that the Mine Cars which are in use or were earlier in use and which had been measured were not present on the date of nationalisation and so it will be improper to extend this average measurement of 146 cft per Mine car to such long past. They contended that the last date for this extension for payment should be 1-1-79. After this the Arbitrator conveyed that both the paries had agreed earlier in conciliation proceeding dated 27th May, 1978 before the Asst. Labour Commissioner (C) that the settlement of this issue shall be effected from 1st April, 1978 and the same should be accepted now also by both the parties and he is inclined to decide the issue with effect from Ist April, 1978 which the parties accepted. The parties agreed to extend the date for giving award by the Arbitrator by an Agreement within 31st December, 1980.

(A. B. SHAH)
Arbitrartor

(B. M. MUKHERJEE)
General Manager
Sripur Area

(SHIV KANT PANDEY)
Secretary
Koyala Mazdoor Congress.

आदेश

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1980

का०आ० 115 —केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में ग्रिण्डलेज बैंक, कोचीन के प्रबन्ध मण्डल से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० सुन्दरसनम् डेनियल होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड के प्रबन्ध मण्डल की कोचीन में बैंक की विलिंग्डन आइलैंड शाखा में नियोजित कर्मकारों की मजदूरी से 15 मार्च 1978 को छह मिनट की मजदूरी काटने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

क्रमांक	नाम	विभाग	पदनाम
1	2	3	4
1.	ए० के० रामचन्द्रन	निक्षेप	विशेष सहायक
2.	बी० सी० परेरा	अग्रिम	लिपिक
3	डी० बी० पाई	निक्षेप	लिपिक
4	डी० एम० पाई	निक्षेप	लिपिक
5	ई० एल० डी० क्रूज	निक्षेप	लिपिक
6	श्रीमती फ्लोरा आस्टिन	टेलीफोन	आपरेटर
7	एच० पी० शिनाय	निक्षेप	लिपिक
8.	के० ए० कादरखान	पत्र-व्यवहार	लिपिक
9	के० ए० मैथो	निक्षेप	प्रधान लिपिक
10	के० पी० मालिया	निक्षेप	टंकक
11	एस० वेंकटाचलम	रोकड़	रोकड़िया
12	एल० सी० प्रभु	निक्षेप	प्रधान लिपिक
13	एल० वी० वैद्यानाथन्	बिल	लिपिक
14	एम० एम० भट्ट	लेखा	लिपिक
15	एम० पी० मेनन	लेखा	विशेष सहायक
16	एन० पी० पाई	निक्षेप	प्रधान लिपिक
17.	एन० आर० पाई	प्रेषण	प्रधान लिपि
18	एन० यू० पई	निक्षेप	लिपिक
19	एन० रविन्द्रन	निकासी	लिपिक
20	पी० जी० जेकब	निक्षेप	लिपिक
21	आर एन० प्रभु	बिल	लिपिक
22	आर० नारायणन	रोकड़	रोकड़िया
23.	वी० पी० मेनन	लेखा	लिपिक
24	वी० एन० प्रभु	निक्षेप	लिपिक
25.	फैंसिस एलबेरेज		ड्राइवर/चपरासी
26.	के० पुणकरन	पत्र-व्यवहार	चपरासी
27.	एन० एस० थांगापन	प्रबन्धक का कार्यालय	प्रबन्धक का चपरासी
28.	पी० एस० प्रभु	पत्र-व्यवहार	चपरासी
29.	एन० एस० दामोदरन	पत्र-व्यवहार	चपरासी
30	वी० एल० एन्टोनी	रोकड़	चपरासी

(iii) ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड के प्रबन्ध मण्डल और अखिल भारतीय राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी परिसंघ (ऑल इण्डिया नेशनल बैंक एम्प्लाइज फैडरेशन) के बीच तारीख 29-4-1970 और 14-1-1977 के हुए समझौतों के सुसंगत निबन्धनों को ध्यान में रखते हुए, क्या उपर नामित प्रबन्ध मण्डल की कोचीन केन्द्र के लिपिकीय केडर के पात्र कर्मकारों की प्रोन्नति करने की बजाय अन्य केन्द्रों से कर्मचारियों का स्थानान्तरण करके बैंक के कोचीन केन्द्र में प्रबन्धकीय काडर (कार्य श्रेणी) में रिक्तियों को भरने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० एल० 12011/7/79-डी० II(ए)]

ORDER

New Delhi, the 24th September, 1980

S.O. 115.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Grindlays Bank, Cochin and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And Whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an industrial Tribunal of which Shri T. Sundarsanam Daniel shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal

SCHEDULE

(1) Whether the action of the management of the Grindlays Bank Limited in deducting from the wages of the workmen employed at Willingdon Island Branch of the Bank at Cochin for

March, 15, 1978 wages for six minutes is justified? if not, to what relief are the workmen concerned entitled?

Sr No.	Name	Department	Designation
1	2	3	4
1.	A.K. Ramachandran	Deposits	Special Assistant
2.	B.C. Pereira	Advances	Clerk
3.	D.B. Pai	Deposits	,,
4.	D.M. Pai	,,	,,
5.	E.J. D'Cruz	,,	,,
6	Mrs Flora Austin	Telephone	operator
7.	H.P. Shenoy	Deposits	Clerk
8.	K.A. Kader Khan	Correspondence	Clerk
9	K.A. Mathew	Deposits	Head Clerk
10.	K.P. Mallia	,,	Typist
11.	L. Venkatachalam	Cash	Cashier
12.	L.C. Prabhu	Deposits	Head Clerk
13.	L.V. Vaidyanathan	Bills	Clerk
14.	M.S. Bhat	Accounts	Clerk
15.	M.P. Menon	Accounts	Special Assistant
16.	N.P. Pai	Deposits	Head Clerk
17.	N.R. Pai	Remittances	,,
18.	N.U. Pai	Deposits	Clerk
19.	N. Ravindran	Clearing	,,
20.	P.G. Jacob	Deposits	,,
21.	R.N. Prabhu	Bills	,,
22.	R. Narayanan	Cash	Cashier
23.	V.P. Menon	Accounts	Clerk
24.	V.N. Prabhu	Deposits	,,
25.	Francis Alverez		Driver/Peon
26.	K. Pushkaran	Correspondence	Peon
27.	N.S. Thangappan	Managers	Manager's peon
28.	P.S. Prabhu	Correspondence	Peon
29.	N.S. Damodaran	,,	Peon
30	V.L. Antony	Cash	Peon

(ii) Keeping in view the relevant terms of settlements dated 29-4-1970 and 14-1-1977 arrived at between the management of Grindlays Bank Limited and the All India National Bank Employees Federation, whether the action of the management named above in filling up the vacancies in the managerial cadre (Job Grade-I) in the Cochin Centre of the Bank by transferring employees from other centres instead of by promoting eligible workmen in clerical cadre of the Cochin Centre, is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?

[No. L-12011/7/79-D.II(A)]

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1980

का०आ० 116—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट विषय के बारे में 11 बैंकों के प्रबन्ध मण्डल से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री वी० नीलाद्रि राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या उपाबन्ध मे सूचीबद्ध बैंकों में नियोजित वाणिज्यिक कमीशन अभिकर्ताओं या जमा कलक्टरों की मांग कि वे उन बैंकों में नियोजित नियमित लिपिकीय कर्मचारियों को उपलब्ध वेतनमानों, भत्तों और अन्य सेवा शर्तों के हकदार हैं? न्यायोचित है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं और किस तारीख से ?

उपाबन्ध

1. सिंडीकेट बैंक, पायनियर हाउस, सोमाजीगुडा, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, गनफाउंड्री, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।
3. इण्डियन बैंक, 3-6-150, हिमायत नगर, हैदराबाद-29।
4. विजय बैंक लि०, 3-6-140/5बी, हिमायत नगर, हैदराबाद-29।
5. विश्व बैंक लि०, 4-1-353, आबिद रोड, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।
6. कार्पोरेशन बैंक लि०, 15-1-503/बी०/17-34, सिद्दम्बर बाजार, हैदराबाद-12।
7. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) स्थानीय मुख्य कार्यालय, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद।
8. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।
9. आन्ध्रा बैंक लि०, सुल्तान बाजार हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।
10. केनरा बैंक हिमायत नगर, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।
11. तमिलनाडु मरकेंटाइल बैंक लि०, 16-2-696, सिद्दम्बर बाजार, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

[संख्या एल० 12011/47/79-डी० II (ए)]

New Delhi, the 3rd October, 1980

S.O. 116—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of 11 banks and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri V. Neeladri Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the demands of the Commission Agents or as the case may be Deposit Collectors employed in the Banks Listed in the Annexure that they are entitled to pay scales, allowances and other service conditions available to regular clerical employees of those banks is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled and from which date?

ANNEXURE

1. Syndicate Bank, Pioneer House, Somajiguda, Hyderabad (A.P.)
2. State Bank of Hyderabad, Gunfoundry Hyderabad (A.P.).
3. Indian Bank, 3-6-150/5B, Himayatnagar, Hyderabad-29.
4. Vijaya Bank Ltd., 3-6-140/5B, Himayatnagar, Hyderabad 29

5. Vysya Bank Ltd., 4-1-353, Abid Road, Hyderabad (A.P.)

6. Corporation Bank Ltd., 15-1-503/B/27-34, Siddambar Bazar, Hyderabad-12.

7 State Bank of India, Hyderabad (AP) Local Head Office, Bankstreet, Hyderabad.

8. Central Bank of India, Bank Street, Hyderabad (A.P.)

9. Andhra Bank Ltd., Sultan Bazar, Hyderabad (A.P.)

10. Canara Bank, Himayatnagar, Hyderabad (A.P.)

11. Tamilnadu Mercantile Bank Ltd., 16-2-696, Siddamber Bazar, Hyderabad (A.P.)

[No L-12011/47/79-D.II.(A)]

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1980

का०आ० 117—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में बड़ौदा बैंक, अहमदाबाद के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री आर० सी० इसरानी होंगे जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या बड़ौदा बैंक, अहमदाबाद और गांधीनगर क्षेत्र, अहमदाबाद के प्रबन्ध मण्डल की श्री जे० एस० प्रजापति, भूतपूर्व भारमोचन लेखा मशीन प्रचालक (रिलीविंग एकाउंटिंग मशीन आपरेटर) की सेवाओं को 9-2-1979 से पर्यवसित करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल० 12012/128/79-डी० 2(ए)]

New Delhi, the 7th October, 1980

S.O. 117—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bank of Baroda, Ahmedabad and their workmen in respect of the matter specified in the Scheduled hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri R. C Israni shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Bank of Baroda (Ahmedabad and Gandhinagar Region), Ahmedabad in terminating the services of Shri J. S Prajapti, Former Relieving Accounting Machine Operator with effect from 9-2-1979 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

[No. L-12012/128/79-D.II.(A)]

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1980

का०आ० 118—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड, कोचीन के प्रबन्धमण्डल से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० सुन्दरसनम् डेनियल होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड, कोचीन के प्रबन्धमण्डल की केलूर शाखा के सम्बन्ध में श्री एम० ओ० फ्रांसिस, पड़ताल लिपिक को 10-7-78 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल० 12012/22/80-डी० II (ए)]
एस० के० बिस्वास, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th November, 1980

S O. 118.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Cochin, Ltd., Cochin and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Sri Sudarsanam Daniel shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bank of Cochin Ltd, Cochin in relation to their Kaloor Branch in dismissing the services of Shri M. O Francis, checking clerk with effect from 10-7-1978 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

[No. L-12012/22/80-D.II(A)]
S K. BISWAS, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1980

का०आ० 119—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्ध मण्डल से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण

गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० वी० गंगाराजू होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या पंजाब नेशनल बैंक, 18-ए, ब्रेबार्न रोड, कलकत्ता के प्रबन्ध मण्डल का पंजाब नेशनल बैंक, कटक में नियोजित श्री तपन कुमार घोष, क्लर्क-कम-लिपिक व गोदाम रक्षक को 22-3-1977 से पदच्युत करने का आदेश न्यायोचित था ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं०एल० 12012/124/78-डी० II (ए)]

एम० एच० एम० अय्यर, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 7th October, 1980

S O. 119.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M V. Gangaraju shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneswar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the order of dismissal of Shri Tapan Kumar Ghosh Clerk-cum-Godown Keeper employed at Punjab National Bank, Cuttack with effect from 22-3-1977 by the management of Punjab National Bank, 18-A, Brabourne Road, Calcutta was justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?

[No. L-12012/124/78-D.II(A)]

New Delhi, the 24th December, 1980

S.O. 120 —In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Lodna Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Lodna, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th December, 1980.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD.

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 5 of 1979

PARTIES :

Employers in relation to the management of Lodna Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Lodna, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice B. K. Ray,—Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.
Colliery Mazdoor Sangh.

State : Bihar. Industry : Coal.

Dhanbad, the 11th December, 1980

AWARD

By Order No. L-20012/48/78-D.III(A) dated 15th January, 1979 the Central Government have referred the dispute as mentioned in the schedule attached to the order for adjudication to this Tribunal. The schedule to the order reads thus :

"Whether the action of the management of Lodna Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Lodna, District Dhanbad in terminating the services of Shri Bhola Berhi, Workshop Khalasi of Lodna Colliery with effect from the 23rd December, 1976 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. After notice to the parties they have filed their respective written statements and rejoinders. The case of the concerned workman is that the reasons given in the order of termination of services (Ext. M-3) dated 22/23-12-76 are not true. He was not actually beyond 60 years of age when his services were terminated. The reasons thus given being false the order of termination is bad and cannot be sustained. The further case of the workman is that it was on account of emergency period in 1976 the management wanted to get rid of some of its workers on any pretext whatsoever. The concerned workman was one of such workers. The management to get rid of them constituted a Medical Board for examination of these workers whose services it wanted to terminate. After constitution of the Board the management directed the workers including the concerned workman to appear in the Medical Board which had been previously asked by the management to see that the workers to be examined by it would be found to be medically unfit. Accordingly the Board after examination of the concerned workman and some others found all of them physically unfit. Thereafter the services of all these workers who were found unfit were terminated. The report of the Medical Board did not represent correct state of things. There was no examination of the concerned workman by any expert and the findings of the Board saying that the vision of the concerned workman was defective and that he was beyond 60 years of age are not true. Curiously however sometime after the termination of services of all the aforesaid workman including the concerned workman, all the workman except the concerned workman were reinstated in their services. For no reason whatsoever the concerned workman's case was not considered and he was not reinstated. The findings of the Medical Board not being correct the order of termination on the basis of such finding is liable to be vacated and the concerned workman is entitled to be reinstated.

3. The case of the management is as follows. The concerned workman was working in the Mechanical workshop in the Lodna Colliery. He was working as Line Shaft Khalasi and his duties were to start line shaft, to lubricate the bearing of the line shaft and to re-fit the belt in case it fell down from pulley. While lubricating the shaft he had to climb up a ladder. The lubrication work was to be done while the machine was in motion. In 1976 it was detected by the Engineer incharge of Workshop that on account of defect in eye sight the concerned workman was not able to see things properly and therefore not able to do his work efficiently This physical defect in the concerned workman was brought to the notice of the management which by letter dated 6-12-76 directed the concerned workman to appear before a Medical Board of the management for the purpose of his examination. In pursuance to the direction the concerned workman appeared in the Medical Board and the Board after examination of the concerned workman found that his eye sight was defective and he was beyond 60 years of age Upon this report the services of the concerned workman was terminated with effect from 23rd December, 1976. On termination of his services the concerned workman was paid all his dues. The allegation of the sponsoring union that as the management due to emergency wanted to terminate the services of the concerned workman it got a false report from a Medical Board constituted by

it saying that the workman was physically unfit and that on the basis of the report removed the concerned workman from service, is absolutely false and imaginary. In the circumstances the order of termination can not be said to be bad and must be upheld.

4. In course of hearing management has examined two witnesses of whom MW 1 is one of the Doctors who was a member of the Medical Board constituted by the management for examination of the concerned workman and MW-2 is an Engineer incharge of Mechanical Workshop in which the concerned workman was working at the relevant time. Besides examining these two witnesses the management has proved only three documents, namely, Ext M-1 Medical Report, Ext M-2 Notice to the workman to appear before the Medical Board and Ext M-3 letter terminating the services of the workman. On the side of the workman he has only been examined and no document has been marked on his behalf.

5. Mr. S. Bose for the workman contends that the order of termination Ext M-3 terminating the services of the concerned workman only says that as the concerned workman was found to be beyond 60 years of age on medical examination his services were terminated. This document does not say anything about the defect in the eye sight of the concerned workman on which the management mainly banks upon for the purpose of establishing its case at the time of hearing. So far as the finding of the Medical Board regarding the age of the concerned workman is concerned on the evidence of MW 1 the Doctor, it is argued that the findings of the Medical Board that the concerned workman was beyond 60 years of age at the time of examination cannot be accepted. Therefore, if the only reason given in order of termination is not accepted the order of termination cannot be sustained. The contention of Mr. Bose on this point is well-founded. But the matter is not so simple as argued. Ext M-1 is the Medical Report and MW 1 is the Doctor who proves the report. In paragraph 31 of Ext M-1 the grounds of disqualification have been stated to be over age and defective vision. In paragraph 12 of Ext M-1 the vision of the right eye of the concerned workman has been given to be 6|12 with glass. In the same paragraph with regard to the left eye of the workman it has been said that there is a matured cataract in that eye and that the concerned workman can only count figures from a distance of 1 metre. MW 1 the Doctor deposes that the Board did not carry any special tests to determine the age of the concerned workman and it has opinioned on the basis of general appearance of the workman that he was over age on the date of his examination. This being the evidence of the Doctor with regard to the age of the concerned workman it may be said that on the basis of such a finding regarding age the termination of the service of the concerned workman is bad. But the consistent case of the management from the very beginning is that the defective vision of the concerned workman is also one of the reasons for termination of his service. It would have been better for the management had this reason also been given in the order of termination Ext M-3. But looking at the case of the management from the very beginning and looking to the documents the genuineness of which is beyond doubt it has to be held that the services of the concerned workman have been terminated due to his defective vision which has been found after medical examination. Omission to mention this defect in Ext M-3 is not fatal and on that ground the order of termination cannot be said to be bad. So the order of termination cannot be set aside merely because it does not mention about the defective vision provided it is established that the workman was not fit to continue in service due to defective eye sight. Ext M-2 is the Notice dated 6-12-76 in which the concerned workman was asked to appear before the Medical Board. This letter refers to an earlier order of October 1976 of the management. In pursuance to that order of the management the Superintendent issued the notice Ext M-2 after constituting a Medical Board directing the concerned workman to appear before the Board for medical examination. The evidence of the Engineer MW 2 also discloses that while supervising Mechanical Workshop in which the concerned workman was working he found that the workman had defect in vision. The Engineer has given in detail, the duties the concerned workman had to perform in the Workshop. According to the Engineer a workman with defective vision cannot do properly the work which had been assigned to the concerned workman. The inference therefore is that after the Engineer detected the defect in the vision of the concerned workman he must have reported about it to the management which constituted a Medical Board for examination of the concerned workman. There is nothing to dis-believe the evidence of the Engineer. Only some discrepancy between the date of the order of the management mentioned in Ext M 2 and the oral evidence of the Engineer had been pointed out to me on behalf of the concerned workman to say that the medical examination was a mere show and the real purpose of the management was to get rid of the concerned workman. The discrepancy pointed out to me is not very material and on the basis of that it cannot be said that the management in order to terminate the services of the concerned workman made a show of medical examination to get a report regarding defective vision of the concerned workman. Discrepancy pointed out by Mr. Bose is this. In the order Ext M-2 the management is said to have directed medical examination of the concerned workman in October, 1976. The evidence of the Engineer MW-2 shows that he detected the defect in the eye of the concerned workman in early December, 1976. The argument therefore, is how could the management as appears in Ext M-2 direct Medical examination of the concerned workman in October 1976 when the defect in the eye was detected by the Engineer in early part of December, 1976. Nothing has been shown to me as to why the Engineer has come forward to make out a false case against the concerned workman. The Engineer was deposing about the detection of the defect of the workman's eye sight from memory. Therefore it is just likely that while deposing he might have committed a mistake while saying that he detected the defect in early part of December, 1976. That being the position on account of this little discrepancy it cannot be said that the management is trying to make out a false case against the concerned workman. While the concerned workman was being examined before the Tribunal it was found on verification that he had a detective vision. So much stress cannot be laid on the discrepancy pointed out by Mr. Bose. It is also argued that the management should have produced the order referred to in Ext M-2 directing medical examination of the workman. No useful purpose would have been served by production of the document. So non production of the same is not fatal to the management's case. Mr. Bose then argues that the Chairman of the Medical Board has not been examined and none of the members of the Board, according to the evidence of the Doctor MW 1, was an Eye-Specialist. On these grounds it is contended that the defect found in eye sight by the Board cannot be accepted when it is not supported by an Expert evidence. The evidence of the Doctor MW-1 is to the effect that each Doctor is in a position to find out patent defects in the eye even though he is not an expert. According to him the normal eye sight of an eye is 6|6 whereas the right eye sight of the concerned workman is 6|12 with glass. It is an admitted fact that in this eye the workman had cataract which had been operated before medical examination. So therefore after operation with the glass according to the evidence of the Doctor the eye-sight of the right eye has not reached the normal stage. Regarding the left eye the evidence of the Doctor is that the concerned workman was not able to count from a distance of 1 metre. Further Doctor says that he found a matured cataract in the left eye which can be detected by any Doctor. This being the evidence of the Doctor it cannot but be said that the concerned workman had a defective vision on the date of his medical examination. MW-2 the Engineer says that with defective vision as was found it is very difficult to work with the machine with which the concerned workman was to work. To allow a workman to work in the machine with defective vision will be at the risk of his life. Moreover working of the machine by a man with defective vision will also spoil the machine. There is no counter evidence on the side of the union to rebut the evidence led by the management. The uncorroborated testimony of the concerned workman alone cannot be accepted in preference to the evidence of the Doctor and the Engineer. In these circumstances therefore, on consideration of the entire evidence I hold that the concerned workman had defective eye sight for which he could not have discharged his duties in the mechanical Workshop properly and therefore the only alternative for the management was to terminate his services due to physical defect. Such a termination is not retrenchment according to established position of law. There is no complain that the concerned workman has not been paid all his dues on the termination of his services. My conclusion, therefore, is that the order of termination terminating the services of the concerned workman is justified and the said workman is not entitled to any relief. The

reference is answered accordingly. There will be no order for costs.

B. K. RAY, Presiding Officer

[No. L-20012 (48)/78-D. III (A)]
S. H. S. IYER, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1980

का०आ० 121.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में बैंक आफ इंडिया, अहमदाबाद के प्रबन्ध मंडल से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री आर० सी० इसरानी होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या बैंक आफ इण्डिया, प्रादेशिक कार्यालय, भाद्रा, अहमदाबाद के प्रबन्धतन्त्र की, श्री टी० डी० धोलकिया, चपरासी को, तारीख 27-12-1978 के आदेश के अधीन बैंक की सेवा से उन्मुक्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल० 12012/210/79-डी० II (ए)]

ORDERS

New Delhi, the 31st October, 1980

S.O. 121.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bank of India, Ahmedabad and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri R. C. Israni shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Bank of India, Regional Office, Bhadra, Ahmedabad in discharging Shri T. D. Dholakia, Peon from the services of the Bank under order dated 27-12-1978 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled.

[No. L-12012/210/79-D.II(A)]

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1980

का०आ० 122.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में पंजाब नेशनल बैंक, कोटा के प्रबन्ध मण्डल से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० डी० चौधरी होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या पंजाब नेशनल बैंक की रामपुरा बाजार शाखा, कोटा के प्रबन्ध मण्डल की श्रीमती कमलाबाई पत्नी श्री रामस्वरूप, अंशकालिक सफाई कर्मचारी को 1 सितम्बर, 1978 से नियोजन से रोकने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल० 12012/87/79-डी० II (ए)]

New Delhi, the 6th November, 1980

S.O. 122.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Punjab National Bank, Kota and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. D. Chaudhary shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Punjab National Bank in relation to Rampura Bazar Branch, Kota in stopping from employment, Smt. Kamlabai wife of Shri Ramswarup, a part time sweepress with effect from 1-9-78, is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?

[No. L-12012/87/79-D.II(A)]

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1980

का०आ० 123.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के प्रबन्ध मण्डल से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री आर० सी० इसरानी होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के प्रबन्ध मण्डल की श्री गोपाल सिंह दरबार सिंह, चौकीदार की सेवाओं को 19-2-1979 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल० 12012/174/79-डी० II (ए)]

New Delhi, the 15th November, 1980

S.O. 123.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Central Bank of India, R.O., Ahmedabad and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri R. C. Israni shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Central Bank of India, Regional Office, Ahmedabad in terminating the services of Shri Gopalsingh Darbarsingh, Watchman from 19-2-1979 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

[No. L-12012/174/79-D.II(A)]

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1980

का०आ० 124—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, भावनगर के प्रबन्ध मण्डल से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री आर० सी० इसरानी होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, भावनगर के प्रबन्ध मण्डल की श्री कलोत्रा मोतीभाई नारायणभाई, अधीनस्थ कर्मचारी की सेवाओं को 20-4-1978 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[सं० एल० 12012/211/79-डी० II (ए)]

New Delhi, the 20th November, 1980

S.O. 124.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of State Bank of Saurashtra, Bhavnagar and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed:

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri R. C. Israni shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of State Bank of Saurashtra, Bhavnagar in terminating the services of Shri Kalotra Motibhai Narayanbhai sub staff with effect from 20-4-78 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

[No. L-12012/211/79-D.II(A)]

का०आ० 125—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में स्टेट बैंक आफ मैसूर बंगलौर के प्रबन्ध मण्डल से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है।

अतः, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० शनमुखप्पा होंगे, जिनका मुख्यालय गांधीनगर, बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या स्टेट बैंक आफ मैसूर, बंगलौर के प्रबन्ध मण्डल की अपने पत्र संख्या इस्ट/0343, तारीख 10 जुलाई, 1976 द्वारा श्री जे० कुमार, अधीनस्थ कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[सं० एल० 12012/16/80-डी० II (ए)]

एस० एस० मेहता, डेस्क अधिकारी

S.O. 125.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of State Bank of Mysore, Bangalore and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. Shanmukhappa shall be the Presiding Officer, with headquarters at Gandhinagar, Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of State Bank of Mysore, Bangalore in terminating the services of Shri J. Kumar, Sub-Staff under their letter bearing reference No. Estt./0343, dated 10th July, 1976 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

[No. L-12012/46/80-D.II(A)]

New Delhi, the 22nd December, 1980

S.O. 126.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes, Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th December, 1980.

BEFORE SHRI V. NEELADRI RAO, B.A.,B.L., INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 4 of 1979

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Collieries. (A.P.)

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.

APPEARANCES : Shri D.S. Varma, Advocate for Workmen Sri K. Srinivasa Murthy, Advocate for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, under Sections 7A and 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by its Order F. No. L-21011(4)/78-D. IV(B), dated 19-5-1979 has referred to his Tribunal the following issues for adjudication in the Industrial Dispute between the workmen and the Management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.

"Whether the action of the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem in terminating the services of 34 Trainee Clerks (whose particulars are given in the annexure) is justified? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?".

"ANNEXURE

Sl. No.	Name	Place of work	Date of Termination
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	K. Rama Rao	Coal Chemical Complex.	3-10-78
2.	Puli Laxma Reddy	RKP	4-10-78
3.	A. Venkata Reddy	Do	3-10-78
4.	Y. Laxman Reddy		3-10-78
		Bellampalli and Ramkrishnapur Area Do	
5.	B. Pulla Reddy		22-9-78
6.	V. Seshagiri		19-9-78
7.	K. Subba Rao		19-9-78
8.	M. Padmanabhacharyulu		19-9-78
		Bellampally Area	
9.	V. Narasaiah		22-9-78
10.	N. Varada Reddy		22-9-78
11.	P. Rama Murthy		22-9-78
12.	Y. Subbaiah		22-9-78
13.	N. Jayaprakash		22-9-78
14.	A. Venkata Krishna		22-9-78
15.	B. Rama Rao		22-9-78
		Kothagudem Area	
16.	R. Prabhakar		13-9-78
17.	M. Katyayani		13-7-78
18.	A. Govinda Rao		13-9-78
19.	K. Swaranalatha		13-7-78
20.	G. Samuel		13-9-78
21.	Mohd. Bashir		13-9-78
22.	K. Raja Babu		16-9-78
23.	Ch. Babu Rao		14-9-78
24.	P. Subba Rao		17-9-78
25.	M. Madhusudhana Prasad		13-9-78
26.	K. Sudhakar Reddy		16-9-78
		Ramagundam Area	
27.	N. Bosu Babu		25-9-78
28.	S. Narasimha Reddy		24-9-78
29.	R. Ramulu		17-9-78
30.	K. Sudhakar Reddy		17-9-78
31.	R. Bhadraiah		17-9-78
32.	P. Raja Reddy		17-9-78
33.	P. Kilasam		17-9-78
34.	P.S.R. Satyanarayana		17-9-78

2. The reference was registered by this Tribunal as Industrial Dispute No. 4 of 1979 and notices were sent to parties concerned.

3. A Memo dated 15-10-1980 was filled by the Workmen and the Management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem praying for passing an award in terms of the settlement. Sri B. Gangaram, Vice President, Singareni Collieries Workers' Union, Bellampalli who is permitted to represent. General Secretary and Branch Secretary of Singareni Collieries Workers' Union, Kothagudem and Sri V. Gopala Sastry, Personnel Officer of the Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem who is permitted to represent the General Manager, Kothagudem as per orders in M.P., admitted the terms of Settlement.

4. After having gone through the terms of the settlement, it can be stated that it is just and proper and it is in the interest of both the concerned workmen and also the Management. Such proper and just settlements have to be accepted in order to see that cordial relationships between the workmen and the management are maintained. Hence, in the circumstances, it is a fit case for passing the award in terms of the settlement, especially when it is stated that clause 1 of the terms of settlement was already implemented.

5. Award is passed accordingly in terms of the settlement between the parties. Copy of the settlement is herewith attached as part of the award.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 21st day of November 1980.

Sd/- Illegible.
Presiding Officer
[No. L-21011(4)/78-D.IV. (B)]

BEFORE THE HON-BLE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL), HYDERABAD.

In The matter of I.D 4 of 1979

BETWEEN

The Management of Singareni Collieries Co. Ltd., Kothagudem. — Management

AND

Their workmen represented by the Singareni Collieries Workers' Union, Kothagudem. — Workmen.

COMPROMISE MEMO

The dispute referred for adjudication in I.D. 4 of 1979 relating to the termination of services of Trainee Clerks, has been settled, as a result of mutual discussions held on 16th, June, 1980, on the following terms and conditions: —

"1.(a) Trainee Clerks, whose services were terminated for producing fake typewriting Certificates, whether their names are included in the schedule of reference of I.D. 4 of 79 or not, will be reinstate with immediate effect.

(b) There shall be no back wages or any other benefits on account of, and relating to the period starting with the date of termination, to the date of reinstatement, nor any claims to that effect would be entertained. They will, however, be permitted to draw minimum of Grade II (Clerical) from the date of passing Departmental Test to the date of termination of services.

(c) On reinstatement, their pay will be fixed at the apropriate stage in Grade-II, duly reckoning the service rendered by them from the date of passing the Departmental Test to the date of termination of their services.

(d) Grant of future annual increment would depend upon their passing the Typewriting Examination conducted by the Directorate of Technical Education, and earning satisfactory reports about their work, attendance and conduct.

(e) They will be given two years's time from the date of reinstatement to pass the Typewriting Examination, failing which their services are liable to be terminated.

(f) The Union shall withdraw the dispute now pending before the Industrial Tribunal (Central) Hyderabad, In I.D. 4 of 1979 and the parties will file a Memorandum accordingly, in full and final settlement of all the claims".

In the above circumstances, the parties pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to pass an Award in terms of the settlement referred to above.

For Management — For Workmen

Sd. D.V. Paranjpe, General Manager. M/s. Singareni Collieries, Co. Ltd.
Sd. P. Papa Rao, Sr. Personnel Officer. M/s Singareni Collieries Co. Ltd.

Sd. M. Komaraiah, General Secretary Singareni Collieries Workers' Union.
Sd. D.A. Nityananda Rao, Secretary, Singareni Collieries Workers' Union.

Dated : 16th June, 1980
Kothagudem Collieries.

COPY

Sd/-
Illigible
(A. P. PULLAREDDY
Divisional Personnel Officer.
S.C. Co. Ltd. Kothagudem

Before the Industrial Tribunal (C)
Hyderabad.
I.D. No. 4 of 1979

Workmen represented by the Singareni Collieries Workers Union, Kothagudem

Vs.

The Singareni Collieries Company Ltd. Kothagudam
Compromise of the Parties
Filed by DPO Singareni Collieries Company.
Filed on 10-11-80

New Delhi, the 23rd December, 1980

S.O. 127—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bankola Colliery of Eastern Coalfields Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 16-12-80.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 6 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bankola Colliery of Eastern Coalfields Limited,

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Mr. N. Das, Advocate.
On behalf of Workmen.—Mr. C. S. Banerjee, Jt Secretary of the Union.

State : West Bengal

Industry : Coalmine

AWARD

This reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has been sent to this Tribunal for adjudication of an industrial dispute between the management of Bankola Colliery of Eastern Coalfields Limited, P.O Ukhra, Burdwan and their workmen. The relevant Order of Reference of the Central Government is No L-19012(34)/79-D.IV(B) dated 21st January, 1980. The subject matter of adjudication is as follows :

"Whether the action of the management of Bankola Colliery of Eastern Coalfields Limited, Post Office Ukhra, Distt. Burdwan in stopping the workmen (whose names are given at annexure) with effect from 23rd March, 1975 is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?

ANNEXURE

1. Shri Chandrika Bhagat
2. Shri Jagadananda Lohar
3. Shri Bijoy Rajak
4. Shri Bhrigunase Harijan
5. Shri Viswaroop Baxi
6. Shri Ajit Kumar Patra."

2. The workmen are represented by the Joint General Secretary, Colliery Mazdoor Union, Cinema Road, P.O. Ukhra, District Burdwan. Both the parties appeared and filed their respective written statements. The case of the workmen appearing in the written statement is that the six concerned workmen mentioned in the order of reference worked at the Area Stores, Bankola Area from December, 1974 as Tindals. The management used to pay Rs. 7 per day to each of them for their service at the Area Stores. The Union raised a dispute before the Assistant Labour Commissioner, Central, in 1978 for proper categorisation of wages of the workmen in question. During the conciliation proceedings the management stopped the concerned workers from their work on and from 23-3-79. The reason for stoppage of work alleged by the union is that the workmen wanted to increase the rate of their wage of Rs 7 per day which was less than the rate recommended by the Wage Board. The prayer of the Union is that the workmen should be reinstated in their work as tindals with all back wages and facilities.

3. The management of the colliery has filed written statement and its case is that the concerned men never worked in the Bankola colliery as workman and their service as tindals in the Area Stores under Bankola Area has been denied. It is also stated that the management did not know any man named Viswaroop Baxi as mentioned in the order of reference. The other five men mentioned in the order of reference used to work as petty contractors for loading and unloading and arranging materials at the Area Stores, Bankola Area near Biseswari Khandia colliery which was not an establishment of Bankola colliery but was a separate establishment for supplying materials to different collieries within Bankola area. These five persons worked as contractors upto 23-3-79 ; Subsequently the management took decision that they would have the works of contractors done by some surplus hands for gainful utilisation. The story of the concerned workmen being employees of the colliery was not correct. The story of payment of Rs. 7 per day to the concerned men has been denied

4. In this case on the date of hearing the six concerned men were present but three of them examined themselves. They are Ajit Kumar Patra, Bijoy Rajak and Viswaroop Baxi. On the side of the management the Assistant Materials Manager for Bankola Area Stores has been examined as MW-1. Several documents have been exhibited on the side of the management and one document on the side of the workmen.

5. Mr. N. Das, learned Advocate appeared for the management and Mr. C. S. Banerjee, Joint General Secretary of the Union supported the workmen.

6. The main question in this case is whether the persons named in the Order of Reference were employees or workmen of Bankola Colliery of Eastern Coalfields Limited. Mr. Das has been authorised to represent the management by the General Manager of the employers, Messrs Eastern Coalfields Limited. According to Mr. Banerjee for the union the concerned persons are the employees of the Area Stores in the Eastern Coalfields Limited, but according to the management they were petty contractors for doing the work of loading and unloading commodities and to stack them and they were paid on the basis of the contractual rates tendered by them.

7. We have got the evidence of three concerned persons on the side of the union. They are Ajit Kumar Patra, WW-1, Bejoy Rajak, WW-2 and Viswaroop Baxi, WW-3. WW-1 has stated that he had been working in Bankola area since 1974. He worked in Bankola colliery Stores, Area Stores and in Area office and that he was paid wages by vouchers. He has stated that the duty hours of the concerned persons were from 9 a.m. to 1 P.M. and again from 3 P.M. to 5 P.M. S. B. Raman was the District Controller of Stores and after his retirement came B. N. Ruj. At first D. D. Mukherjee used to give them orders for work, then S. C. Dev gave orders next Anil Ray also gave orders and Sitaram Sinha also gave orders. They gave orders for work verbally. Ruj also used to give them orders. The witness has, however, stated that he did not work under any contractor. He told the authorities to make them permanent. At first he asked the authorities to raise the rate of Rs. 7 per day. The rate of payment given to them was less. When they were working there was no tindal but the authorities brought tindal, from Subhas Incline and Moira Depot in Bankola Sub-area. Thereafter, the authorities told them that they required no other tindal and that they were not given any work. They worked for the last time on 2nd or 3rd of April, 1979 and thereafter they were not given any work. His evidence is that if they were late to attend the Stores the Storekeeper used to take them to task. They used to get payment on daily basis and not on contract. They used to give hazira on plain paper and they were paid on the ba is of their attendance. He has been cross-examined and during cross-examination his evidence is that for about one month or two he used to give hazira with Storekeeper and then he got work there. Thereafter he started giving regular hazira there and this was the case with all others mentioned in the order of reference. He has admitted that they were not given any appointment letter either at Bankola Stores or at Bankola Area Stores. They did not get any bonus. Although the workers of the colliery were members of Provident Fund, they were not given any such membership. He has admitted the signature of Bijoy Rajak and Chandrika Bhagat in the tenders filed by the management, marked Exts. M-19 and M-20. He of course did not give any signature like this. According to him the duty of the tindal was to load and unload articles from vehicles and when there was no work they used to stack articles. From this witness we also get that they did not get payment which other tindals got and they did not apply in writing for Provident fund or bonus He has also stated that regular workers of the collieries or Stores used to get wages on wage-sheets and that those who used to work on work orders used to get payment by vouchers. This witness has admitted that the concerned persons used to work on work orders and used to be paid by vouchers. He has again stated that they were paid monthly by vouchers at the rate of Rs. 7 per day. His evidence is that they used to get payment every month on monthly basis.

8 The next witness, WW-2, Bijoy Rajak has stated that at first they used to get Rs. 6 per day, then it was raised to Rs. 7 and in the year 1979 it was raised to Rs. 10 per day. From him we get that either in 1976 or in 1978 work order system was introduced. The witness has stated that D. D. Mukherjee, Anil Roy, B N. Ruj, S. G. Day and all the clerks used to direct and give them work. They used to get wages monthly. This witness has also admitted that the concerned persons did not get any bonus. Although there was a hazira khata, they did not use to sign the hazira khata. From him we also get that they did not get payment for 2 or 3 months but thereafter a bill was drawn on plain paper and work orders were placed and they were paid by vouchers He has stated that he does not know how they were paid before the voucher system was introduced. This witnes also admits that he did not get any appointment letter. He has denied the suggestion that they worked on conract basis.

9. Lastly WW-3, Viswaroop Baxi has stated during evidence that when the Store was being constructed Raman Sahib brought them to the Stores. They used to load and unload commodities and to stack heavy articles. At first they used to get Rs 6 per hazira, thereafter it was raised to Rs. 7 and lastly it was raised to Rs 10 per hazira In 1978 the witness stated, Ruj Sahib told them not to work as they were not required He does not however remember the month when the work was stopped. He has also stated there was a hazira khata but they did not sign. This witness has also stated that they did not get any bonus and did not get the facilities which the regular workers of the collieries got. He knew what work order was and he has stated that they used to work on work order. He has stated that Exts. M-19 and M-20 were work orders. He has also stated that he used to work on work orders like those exhibited.

10. As against the evidence adduced on the side of the union, we get the evidence of MW-1 B. N. Ruj, referred to by the witnesses on the side of the union. This witness stated that at present he is the Assistant Materials Manager for Bankola Area Stores. He has been in this stores since June, 1977. From him we get that Bijoy Rajak, Chandrika Bhagat, Jadunandan, Bhrigurase and Ajit Patra were contractors for loading and unloading of materials. Of course there was no Jagadanandan Lohar either as an employee or a contractor. There was no Viswaroop Baxi either as an employee or a contractor. He has stated that the contractors were shown the materials to be unloaded coming from outside or to be loaded going outside and were asked for quotations about the rates. They used to give rates in writing. Thereafter on the basis of the quotations work orders were placed with them and after the completion of the work they were paid. Pay orders were prepared and the contractors were paid by vouchers. He has denied that the persons mentioned in the order of reference were tindals as alleged by them. The contractors were never allowed to unload lathe machines as stated by a witness on behalf of the union but they were taken down with the help of the crane. This witness has stated that after joining the Area Stores, he saw Chandrika, Bijoy, Jadunandan, Bhrigu and Ajit working as contractors. Employees working as tindals of the colliery or Stores were mentioned in D form register. These persons have not been mentioned in the B for register. He denied that these persons attended the Stores at 9 a.m. and left at 5 P.M. They were not required to sign any hazira. The contractors were not paid at the daily rates. The persons were never paid at the rate of Rs. 6 per day or Rs. 7 per day or Rs. 10 per day as alleged. They were paid on the basis of the quotations for works done by them. From this witness we also get that as some tindals were found surplus in other collieries. They were brought to the stores and as such they were not in need of any contractor for loading and unloading purposes. There was no work order on daily basis. He has also mentioned M-10 the work order signed by him. This is dated 19-5-79 but work according to him was done in February. 1979. He has explained by saying that the work orders exhibited in this case show that they were issued subsequent to the works done. In these cases works were given earlier and the said works were done and thereafter for regularisation of the matter, the written work orders were issued subsequently. MW-1 has stated that the works were done on verbal order by the staff. He prepared a noteshcet and the notesheet was duly approved by the Manager who signed the work orders subsequently. This witness was the District Controller of Stores at the relevant time and he was "work in-charge" and under his order the work was done. Mr. Raman was his predecessor-in-office and from him he took over charge. He has stated that Bankola colliery is a separate unit distinct from Bankola Area Stores But from the evidence I am satisfied that although the stores may be a separate unit supplying materials to different colliery including Bankola colliery, yet the ultimate management is done by the Eastern Coalfields Limited which authority has appeared in this case to represent the management.

11. Regarding the documentary evidence, we find that the management has filed a number of payment vouchers in respect of Chandrika Bhagat, Jadunandan, Bijoy Rajak and Bhrigurase Several work orders have also been filed and two tenders giving quotations for the works done also signed by Bejoy and the other Chandrika have been filed and marked exhibits.

12. It has been first contended by Mr. Das, learned Advocate appearing on behalf of the management that the reference is bad on two grounds. First, the order of reference shows that the dispute mention the date of stoppage of work is 23rd March, 1975 whereas the claim of the union is that the work was stopped on 23rd March 1979. Admittedly we find from Ext. W1, the report submitted by the Assistant Labour Commissioner to the Secretary to the Government of India, Ministry of Labour that there was a dispute between Chandrika Bhagat and five others and the management over the stoppage of work from 23-3-79 and clearly on the basis of that report

the Central Government decided to refer this dispute to the Industrial Tribunal. In my view, therefore, there was some clerical mistake due to inadvertance, and as such a wrong date appears in the order of reference. The dispute is over the stoppage of work on and from 23-3-79 all along and therefore I cannot say that the reference would be bad due to this typographical mistake or mistake due to inadvertance.

13. The second point urged by Mr. Das is that the reference is bad because in the reference it is stated that the dispute is between the management of Bankola colliery of Eastern Coalfields Ltd. and their workmen whereas the union claims that the concerned persons were employees of Bankola Area Stores which is a distinct unit and not under Bankola colliery. I do not place any importance to this argument because both the colliery and the Bankola Area Stores are under the management of Eastern Coalfields Limited and the General Manager of the Eastern Coalfields Limited has authorised Mr. Das to represent the said Coalfields Limited in this reference. Therefore, the Eastern Coalfields Limited knew that it was a party to the reference and that it has authority over both the Bankola Area Stores as well as the Bankola Colliery. I do not think, therefore, that the point urged by Mr. Das is of any importance.

14. However, the main question, as I have already stated, is whether or not the concerned persons were workmen under the Area Stores, Bankola area. The concerned persons went to say through the union that they were employees whereas the management says that they were petty contractors for the purpose of loading and unloading and stacking of commodities. I have already mentioned the nature of evidence of the witnesses on both the sides. From the evidence of the aggrieved persons themselves it appears that their claim of being workmen cannot be entertained. They stated in their written statement that their daily rate was Rs. 7 but at the time of evidence they wanted to say that it was raised to Rs. 10. From their evidence it appears that although there was a hazira khata for the regular workmen, these persons did not sign that khata. They did not get the same wages as other workmen used to get. They did not get the bonus or the facility of the Provident fund. They did not get any appointment letter whatsoever. On the other hand, the management has filed payment vouchers, pay order showing that Chandrika, Jadunandan, Bijoy Rajak and Bhrigurase worked for loading and unloading and stacking and arranging materials for different parties. The two quotations filed by Bijoy and Chandrika have been marked exhibits and there is no denying the fact that they signed the same. The witness have admitted that they worked on work order. The payment orders and the payment vouchers show that they were paid on the basis of works done on the basis of work orders at the contractual rate and not on daily wage basis. The Assistant Materials Manager, B. N. Ruj, the most competent witness has given evidence denying the claim of the union that the concerned persons were workmen supported by documentary evidence. On the other hand, I have no doubt to hold that Viswaroop Baxi examined in this case was neither a workman nor a contractor whereas Chandrika, Bijoy, Ajit, Jadunandan and Bhrigurase were contractors. It is clear that there has been a mistake in the name of Jagadnnandan Lohar mentioned in the order of reference. I accept the evidence of the management that Jadunandan Lohar was a contractor and Jagadananda Lohar was neither a contractor nor a workman under the management.

15. Giving my best consideration to the evidence, I have no doubt that the persons mentioned in the order of reference were not workmen of tindals as claimed. They were not employees of the management of Bankola Colliery or Area Stores of Bankola Area, Eastern Coalfields Limited. They are not entitled to get any relief in this case.

The award is passed accordingly.

Dated, Calcutta, the 9th December, 1980.

R. BHATTACHARYA, Presiding Officer.
[No. L-19012/34/79.D.IV(B)]

S.O. 128.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sripur Area of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Sripur, Distt. Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 16-12-1980.

Arbitration Award under Section 10A of Industrial Disputes Act between Management of Girimint Colliery of Eastern Coalfields Limited and workmen represented by Koyala Mazdoor Congress (HMS).

Shri A. B. Shah, Director (Technical) has been appointed Arbitrator in the dispute between Girimint Colliery of Sripur Area and Secretary, Koyala Mazdoor Congress (HMS) under Section 10A of Industrial Disputes Act, 1947 by Gazette Notification No. L-19011(8)/78-D.IV(B) dated 5th February, 1980. The specific matter of dispute referred for arbitration is as given below :

"Whether the claims of underground loaders of Pit Nos. 2 and 3 of Girimint Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited that the mine cars used by the management are of higher cubical contents than 144 cft. for which wages are paid at present and workmen's contention that they have to load more coal in terms of 40.5 cft. units, is justified ? If not, to what relief the workmen are entitled to and from what date ?".

Background of the Case

It was learnt that at Girimint Colliery there was a strike from 6th April, 1978 to 13th April, 1978 and then from 26th May, 1978 to 13th June, 1978 and 19th March, 1979 to 26th March, 1979. The point raised in these strikes along with others by the workmen was that the mine car that are being loaded by the loaders contain more volume of coal than they are being paid for. The workmen in question at 2 and 3 pits of Girimint Colliery by designation underground loaders had series of discussions during conciliation proceedings before Asstt. Labour Commissioner (C) on different dates, one being on 27th May, 1978 in which it was agreed by the parties before the A.L.C.(C) that in the event of final settlement of issue they shall be affected from 1st April, 1978.

A Notice was issued on 26th February, 1980 advising both parties to appear on 11th March, 1980 at 11 a.m. to put up all their evidences and witnesses material to the point at issue. On 11th March, 1980 the parties appeared before the Arbitrator in the office of Director (Technical), Eastern Coalfields Ltd., at 11 a.m. On 11th March, 1980 it was agreed by both the parties that Written Statements will be submitted by both parties to Arbitrator and one copy of same both parties will give simultaneously to each other.

Thereafter both parties can submit rejoinder to Arbitrator with simultaneously giving copy thereof to each other parties. In addition, it was also agreed that first the parties will give their evidences in support of their case and then site inspection will be arranged if necessary and thereafter both parties will be heard, and then the Arbitrator will give the Award.

On 11th March, 1980 the workmen's representative produced two witnesses namely Shri Bhikha Ram, underground loader and Shri Ramchij Koeri, underground loader and both were crossed examined after the main evidence by Shri K. L. Bose, Agent, Girimint Colliery. The proceedings of 11th March, 1980 are mentioned in Annexure 'B'. The acceptance of Arbitrator by the government is enclosed in Annexure 'A' and statement of Shri Bikha Ram and Shri Ramchij Koeri are marked in Annexure 'C', copy of Conciliation Proceedings record which says that final settlement of the issue shall be effected from 1st April, 1978 is marked as Annexure 'D'. Written Statement on behalf of workmen was submitted to Arbitrator on 24th March, 1980 which appears in Annexure 'E'.

Thereafter a notice was issued under Sl. No. ECL/CMD/C-6D/21168 dated 17th June, 1980 advising the parties to appear on 26th June, 1980 at 9 a.m. Shri Shiv Kant Pandey of Koyala Mazdoor Congress represented that first there should be an inspection and then there should be any hearing and accordingly 30th June, 1980 was fixed for inspection and hearing and a notice No. ECL/CMD/DIR(E)/135/21678 dated 23rd June, 1980 was issued to the parties. These notices dated 26th February, 1980, 17th June, 1980 and 23rd June, 1980 are marked Annexure 'F'.

On 30th June, 1980 management submitted its Written Statement which appears in Annexure 'G'. Then the dates were fixed for hearing on 7th July, 1980 and then on 11th July, 1980 but the union represented by letter dated 4-7-80 that they have difficulty in attending and so the same was postponed

The union appointed 3 representatives for being present for measuring tubs at site and then by letter dated 5th July, 1980 represented to Arbitrator that management is not measuring the tubs properly. The Arbitrator by letter No. ECL/CMD/Dir(E)/135/23289 dated 7th July, 1980 advised General Manager to ensure correct measurements of tubs at site jointly.

Then a notice was issued on 7th July, 1980 to the parties to appear on 22nd July, 1980 and 25th July, 1980 before the Arbitrator. Then by letter dated 11th July, 1980, the union represented that all the mine cars should be measured. Then the union by letter dated 19th July, 1980 represented that they have difficulty in attending on scheduled date and wanted postponment of date of hearing. The date of hearing was changed to 4th August, 1980 by letter No. ECL/CMD/ABS/DIR(E)/135/24949 dated 21-7-1980. Then later on by notice No ECL/CMD/DIR(E)/135/24 dated 31st July, 1980 the date of hearing was changed to 22nd August, 1980. All these notices and letters are marked in Annexure 'H'. The management submitted a rejoinder on 20th August, 1980 that appears in Annexure 'I'. Then on 22nd August, 1980 a hearing was held at Girimint Colliery and Shri S. N. Banerjee, O.S.D (Mining) was appointed by both parties to measure 3 tubs Accordingly on 25th August, 1980 and 30th August, 1980 Shri Banerjee visited Girimint Colliery to measure the tubs. On 25th August, 1980 Shri Banerjee measured all the Mine cars which were in use or were earlier in use numbering 41 and on 30 August, 1980 he continued weighment The measurements and weighments done by Shri Banerjee duly certified by him and proceeding of 22nd August, 1980 are put in Annexure 'J'.

Then on 1st September, 1980 the union conveyed that 3 mine cars have not been weighed and then the Arbitrator informed for a hearing on 9th September, 1980 of the parties by notice No ECL/CMD/DIR(ED)/135/32430 dated 4th September, 1980, which appears in Annexure 'K'.

The measurements done by Shri Banerjee were shown to the union which proved that 146 cft. should be taken on average proceeding of which appears in Annexure 'L'. Both union and management accepted this 146 cft. content of the mine cars in the concerned section of Girimint Colliery on 9th September, 1980 in Arbitration proceeding. Then the date from which payment of 146 cft. is to be given was debated by the parties. The management conveyed that this should be paid from the date of Award whereas the union wanted this to be paid from the date of nationalisation The management conveyed that going back in long past is not relevant because the tubs which have been measured were not the tubs present on the date of nationalisation and so at best it should be done from 1st January, 1979 i.e., from the date of National Coal Wage Agreement II. At last the Arbitrator referred to the agreement date of the parties referred in Annexure 'D' wherein the parties had agreed for final settlement to be affected from 1st April, 1978.

AWARD

After perusing the Written Statemets of workmen and management and rejoinder of the management, the arguments of both the parties and evidences places and mentioned in Annexure 'A' to 'L' I am of the opinion that the undermentioned decisions shall meet the ends of justice and accordingly I hereby give my Award :

(1) That as per measurement submitted by Shri S. N. Banerjee who was appointed by both the parties for measurement and weighment of Mine Cars ad whose measurement of 146 cft both parties have accepted on hearing of 9th September, 1980, I hereby decide that 146 cft. should be taken as volume of the mine cars of 2 and 3 pits of Girimint Colliery for purpose of payment to underground loaders.

(2) That this 146 cft. should be taken as basis for payment to underground loaders of 2 and 3 pits of Girimint Colliery with effect from 1st April, 1978 as agreed by the parties as marked in Annexure 'D', and the arrears should be paid by management within a period of 3 months from the date of Award.

(3) Whenever there is any change in the Mine Cars joint measurement is to be done and average volume per mine car is to be found out and payment has to be made accordingly to avoid any further dispute.

Sd/-

A. B. SHAH, Arbitrator and Director (Technical), ECL.

8th December, 1980.

MEMORANDUM OF SETTLEMENT BETWEEN MANAGEMENT OF GIRIMINT COLLY

AND

SECRETARY KOYALA MAZDOOR CONGRESS AND AGREED BY ARBITRATOR.

Name of Parties :

Representing Employer—Shri B. M. Mukherjee, General Manager, Sripur Area on behalf of 2&3 Pits of Girimint Colliery

Representing Workmen—Shri Shiv Kant Pandey, Secretary, Koyala Mazdoor Congress (HMS).

SHORT RECITAL OF THE CASE

By Memo No L-19011(8)/78.D. IV(B) dated 5th February, 1980 of Shri Sashi Bhushan, Desk Officer, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi, the Government of India has agreed for Arbitration into the dispute of the above parties in respect of 2 and 3 Pits of Girimint Colliery for Arbitration by Shri A. B Shah, Director (Technical), Eastern Coalfields Limited and the stipulation of the same was that the Award shall be given within 180 days from the date of publication of the agreement which was on 16th February, 1980 or within such date as had been extended by mutual agreement. The parties have mutually agreed that it was not possible to finish the Arbitration Proceedings within 180 days and decide to extend it for submission of Award to the Government of India by Arbitrator within 31st December, 1980.

Terms of Settlement

It is hereby mutually agreed by both parties that the Arbitrator Shri A. B. Shah, Director (Technical) Eastern Coalfields Limited in the matter of dispute between 2 and 3 Pits of Girimint Colliery of ECL and Workmen represented by Shri Shiv Kant Pandey, Secretary, Koyala Mazdoor Congress (HMS) will submit his Arbitration Award to the Central Government by 31st December, 1980

Signature of the Parties :

Sd/-

B M. MUKHERJEE, General Manager,

Sripur Area

Sd/-

SHIV KANT PANDAY, Secretary,
Koyala Mazdoor Congress.

I also agree to the above

Sd/-

A B SHAH, Arbitrator

WITNESSES :

1. (Sd.) Illegible.
2. (Sd.) Illegible

Dated : 4-12-80.

Sd/-

B M. MUKHERJEE, General Manager,
Sripur Area.

SHIV KANT PANDAY, Secretary,
Koyala Mazdoor Congress (HMS).

A B. SHAH, Arbitrator
Dated : 4-12-80.

[No L-19011/8/78-D.IV(B)]

S S. MEHTA, Desk Officer

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1980

का० आ० 129—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत दूध की सप्लाई के उद्योग को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 6 के अन्तर्गत आता है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत दूध की सप्लाई के उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छ: मास की कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[संख्या एच० 11017/8/80-डी० I (ए)]

New Delhi, the 23rd December, 1980

S.O. 129.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the industry for the supply of milk under the Delhi Milk Scheme which is covered by Item 6 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the industry for the supply of milk under the Delhi Milk Scheme to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. H-11017/8/80-D.I.(A)]

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1980

का०आ० 130—केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 174(ई) तारीख 28 जून, 1980 द्वारा खाद्य पदार्थ उद्योग में लगे भारतीय खाद्य निगम को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 जून, 1980 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्र सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ: मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 दिसम्बर, 1980 से छ: मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस० 11017/6/80-डी० I (ए)]
एल० के० नारायणन्, अवर सचिव

New Delhi, the 24th December, 1980

S.O. 130.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 474(E) dated the 28th June, 1980, the Food Corporation of India engaged in the Food-stuff industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 28th June, 1980.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Govenment hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 28th December, 1980.

[No. S-11017/6/80-D.I.(A)]
L. K. NARAYANAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1980

का०आ० 131.—मैसर्स रूस्तम मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, दुधेश्वर रोड, अहमदाबाद (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया) धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, कोई पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप से सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1 मार्च, 1980 से 28 फरवरी, 1981 तक उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखे रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट करे ।

3. समूह बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित समूह बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले से सदस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो, नियोजक, समूह बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो, नियोजक, समूह बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए समूह बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. समूह बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम कम है जो उस कर्मचारी की दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/मानिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. समूह बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस समूह बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द कर दी जायेगी ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द कर दी जाएगी ।

11. यदि नियोजक, प्रीमियम के संदाय, आदि में कोई व्यतिक्रम करता है तो, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों के, जो वह छूट न दी जाने की दशा में उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नाम निर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवनबीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की कार्रवाई पर समय लगा । तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[संख्या एस० 35014/24/80—पी० एफ० 2]

New Delhi, the 24th December, 1980

S.O. 131.—Whereas Messrs Rustam Mills & Industries Ltd., Dudeshwar Road, Ahmedabad (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Scheduled annexed hereto, the Central Government hereby exempts with effect from 1st day of March, 1980 and upto 28th February, 1981 the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of

the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-35014(24)/80-P.F.II]

का० आ० 132.—केन्द्रीय सरकार ने, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1366, तारीख 12 अप्रैल, 1979 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 (ii) तारीख 21 अप्रैल, 1979 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, मैसर्स सालेम स्टील लिमिटेड, सालेम–636005, तमिलनाडु को, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दी गई थी पूर्वोक्त स्थापन का शुद्ध नाम स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड सालेम स्टील प्रोजेक्ट, सालेम था ,

अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्धों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1366, तारीख 12 अप्रैल, 1979 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की उद्देशिका के पैरा 1 में, सालेम स्टील, लिमिटेड सालेम 636005, तमिलनाडु अभिव्यक्ति के स्थान पर स्टील अथारिटी आफ इंडिया, सालेम प्रोजेक्ट, सालेम–636005, तमिलनाडु अभिव्यक्ति रखी जाएगी ।

[सं० 35014/5/79-पी०, एफ–2]

S.O. 132.—Whereas in exercise of the powers conferred by clause (a) of the sub-section (1) of section 17 of the employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government had, by notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1366, dated the 12th April, 1979 published in Part II, Section 3(ii) of the Gazette of India dated the 21st April, 1979. exempted, subject to the conditions specified in the Schedule to the said notification, Messrs Salem Steel Limited, Salem-636005, Tamil Nadu from the operation of all the provisions of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952. And whereas the correct name of the aforesaid establishment was the Steel Authority of India Limited, Salem Steel Project, Salem;

Now, therefore, in exercise of the provisions of sub-section (1) of section 17 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. SO. 1366, dated the 12th April, 1979, namely :—

In the said notification, in paragraph I of the preamble, for the expression 'Salem Steel Limited, Salem-636005, Tamil Nadu' the expression 'Steel Authority of India Limited, Salem Steel Project, Salem—636005, Tamil Nadu' shall be substituted.

[No. S-35014|5|79-PF.II]

का०आ० 133—केन्द्रीय सरकार, उपदान संदाय अधिनियम, 1972(1972 का 39) की धारा 1 की उपधारा (3) के खंड ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे सभी अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रतिष्ठानों को, जिनमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित है या पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान किसी दिन नियोजित थे, ऐसे स्थापनों के वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें उक्त अधिनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।

[फा सं. एस–70020/13/76–एफ.पी०जी०]
एन० बी० चावला, उप सचिव

S.O. 133.—In exercise of the powers conferred by clause(c) of the sub-section(3) of Section 1 of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), the Central Government hereby specifies all inland water transport establishments in which ten or more persons are employed, or were employed, on any day of the preceding twelve months,)as a class of establishments to which the said Act shall apply with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. S. 70020/13/76-FPG]
N.B. CHAWLA, Dy. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981